हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2017 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में पूर्वाह्न 11.00 बजे आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

15/03/2017/1100/RG/AG/1

प्रश्न सं. 3822--क्रमागत

श्री अनिरूद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पतंजलि योगपीठ को जिला सोलन में जो 96.02 बीघा जमीन दिनांक 19-01-2010 को 17,31,214/-रुपये एक मुश्त व एक रुपये प्रतिमास के हिसाब से दी गई थी, तो इस लीज को सरकार द्वारा वर्ष 2013 में कैन्सिल क्यों किया गया? क्या इसका रेट कम था इसलिए कैन्सिल किया गया या violation of by laws थे इसलिए कैन्सिल किया गया या इसमें कोई भ्रष्टाचार का मामला था? कृपया स्पष्ट करें।
अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त उस समय जो लीज ऐग्रीमेंट हुआ था उसकी कॉपी भी मैंने मांगी थी, लेकिन मुझे उत्तर में सिर्फ एक नोटिफिकेशन की कॉपी ही दी गई है। स्टाम्प पेपर पर लंबा-चौड़ा ऐग्रीमेंट होता है इसलिए शायद मुझे वह नहीं दिया गया। तो कृपया उस ऐग्रीमेंट की कॉपी भी सदन में रखने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैंने प्रश्न के 'घ' भाग में पूछा था कि 'क्या यह भी सत्य है कि हाल ही में सरकार द्वारा पुनः इस भूमि को लीज पर देने का निर्णय लिया गया है? यहां इसका उत्तर दिया गया है कि 'मामला विचाराधीन है।' अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है या सरकार के पास विचाराधीन है और जब यह मामला एक बार कैन्सिल किया गया, तो दुबारा क्यों विचाराधीन है इसका क्या कारण है?

Health & Family Welfare Minister: Mr. Speaker, Sir, this is fact that this land was given to Patanjali Yogpeeth by the previous Government. The order of the Government was on 19th January, 2010. Thereafter, Acharya Balkrishan was given Power of Attorney by the Patanjali Trust and he was to sign the lease agreement. But ultimately from the perusal of the record it appears that instead of Acharya Balkrishan some third person, who was not authorized, signed that lease agreement which is also one of the violations because Power of Attorney

was given to Acharya Balkrishan. He did not sign the agreement. The agreement was signed by the third person. In original lease deed there was overwriting as well as cuttings which also attract violation of the lease

15/03/2017/1100/RG/AG/2

agreement. Similarly, there were other violations also of the lease agreement. Of course, land measuring 96.02 bighas was given. An amount of Rs. 17,21,214/- in one instalment was taken and thereafter it was decided that per month only Rs. 1/- lease money will be given. So, there has been lot of misrepresentation also. Now, Acharya Balkrishan made a representation to the Hon'ble Chief Minister that please this cancellation of the lease may be reconsidered. It was written to the Hon'ble Chief Minister. The Chief Minister has considered this matter and the matter was taken to the Cabinet. The Cabinet in its wisdom decided that he should first withdraw the case from the High Court because when we took up the land and building they filed a writ petition in the High Court. The High Court said that the building should not be dismantled. So, we have put lot of police force there and we are also spending lot of money on that. **Now, it is under the active consideration of the State Government.**

एम.एस. द्वारा जारी

15/03/2017/1105/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 3822 क्रमागत---

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत सारी विसंगतियां बताई हैं। अगर ये सारी डिसक्रिपैंसिज थीं और गैर-कानूनन थी तो मुख्य मंत्री जी को एक रिप्रेजेंटेशन देकर और उसके आधार पर केबिनेट की विज्डम में कहां से आ गया कि अब

कोई गलती नहीं है, सारा ठीक है? क्या ऐसे सलेक्टिवली केबिनेट अपनी विज्डम एप्लाई करती है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, अगर जनहित में हो तो कई बार सरकार अपने फैसले बदलती भी है। आपके समय में भी कई फैसले बदले गए थे और जो मिसरिप्रेजेंट उन्होंने किया था उसके बाकायदा हमने उच्च न्यायालय में पूरे एफेडेविट दिए थे। उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। अभी सूचना मिली है कि उन्होंने बिना शर्त उच्च न्यायालय से अपनी रिट पीटिशन वापिस ले ली है और उसके बाद सरकार ने अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। इसमें एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि there has been several legal and technical irregularities. The question to be determined is whether these irregularities were malafide or not malafide. So, it appears that there was no malafide on your part while giving this lease to Patanjali Yogpeeth.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेलाफाइड और नॉन-मेलाफाइड की बात कही है। जब जल्दबाजी में निर्णय लिया गया तो कितनी फोर्स वहां डिप्लॉय की गई तथा वह कितने समय तक रही?

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

15.03.2017/1110/जेके/एएस/1

प्रश्न संख्याः 3822:-------**जारी**------

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः-----**जारी**------

आपने माना कि बहुत खर्च आ रहा था। कितना खर्चा सरकार का हुआ? क्या इस पर सरकार कार्रवाई करेगी कि गलत निर्णय ले कर वहां पर गलत तरीके से पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई और सरकार का पैसा बर्बाद किया गया?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि फैसला जल्दबाजी में लिया गया। सरकार कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेती है, जो भी फैसला लेती है सोच-समझ कर लेती है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं हुई है। आपने यहां पर कहा कि फोर्स कितनी लगी है? एक पुलिस गार्द वहां पर लगी है। इसका खर्चा कितना आया, यह तो गृह विभाग से पूछना पड़ेगा, राजस्व विभाग इसका हिसाब नहीं रखता है। यह सूचना अगर आपको चाहिए होगी तो वह सूचना भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी । हमने जल्दबाजी में फैसला नहीं किया। जल्दबाजी में लीज़ देने का फैसला पिछली सरकार ने लिया था। उसमें मैं एक और बात बता दूं लैसी पतंजलि योग पीठ थी और लैसर डिप्टी कमिशनर, सोलन थे। अगर आप लीज़ एग्रीमैंट को देखेंगे लैसी की जगह डी0सी0, सोलन ने दस्तखत किए हैं और लैसर की जगह आचार्य बालकृष्ण जी ने किए हैं। क्या ये जल्दबाजी नहीं थी? आपने डी0सी0 को कह करके जल्दबाजी में एग्रीमैंट करवा दिया, इसलिए यदि मैं एक-एक वायलेशन बताऊं तो मेरे ख्याल से बहुत समय लगेगा इसलिए हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। जब सरकार फैसला लेगी तो सोच-समझ कर लेगी। रेप्रिजेन्टेशन उनकी आई थी उसमें हमने कहा था कि उन्होंने सरकार के खिलाफ बहुत गम्भीर आरोप लगाए हैं। जब तक ये आरोप वापिस नहीं लेते तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो उन्होंने रेप्रिजेन्टेशन दी है उस पर सरकार विचार करेगी।

15.03.2017/1110/जेके/एएस/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि आचार्य बालकृष्ण ने साईन ही नहीं किए, किसी और ने कर दिए। अब आप कह रहे हो कि उसने लैसर की जगह लैसी कर दिया। क्या आप इसे केबिनैट मिनिस्टर के रूप में देखते हो? किसने कहा कि दस्तखत किए हैं? वहां के अधिकारी देखते हैं। किसने कहा कि साईन किए हैं? 118 की वायलेशन का एक ऐसा ही मामला था। वे कोर्ट में हार गए थे। बड़ोग में एक होटल है। वह गवर्नमैंट ने टेक ओवर कर लिया था। आपने उसे वापिस किया और आपने उसका स्पैशली धर्मशाला में ज़वाब दिया कि महिला

एन्टरप्रन्योर थी इसलिए हमने वापिस कर दिया। आपकी सरकार ही ऐसे फैसले कर रही है। हमने सारे फैसले ठीक किए और पूरा टाईम लगा करके किए। इसकी लीज़ मनी का जो वहां से पहले रेट आया था वह कम था। हमने फिर दोबारा से इसको भेजा था कि लीज़ मनी कम लग रही है वहां पर कोई सेल ही नहीं हुआ था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि आचार्य बालकृष्ण जी ने दस्तखत नहीं किए थे। बालकृष्ण जी ने किसी व्यक्ति विशेष को उनकी तरफ से दस्तखत करने के लिए भेजा था और उस व्यक्ति ने लैसर की जगह दस्तखत किए न कि लैसी की जगह दस्तखत किए। दूसरे, Only Acharya Balkrishan was authorized by the Power of Attorney to sign the lease agreement. But Acharya Balkrishan has further authorized a third person; whereas the person, who has given the Power of Attorney, cannot further give the Power Attorney to a third person. That is also a violation. So my respectful submission to this Hon'ble House is that whatever the decision the Government will take in future, everything will be taken into account. That is my submission to you.

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

15.03.2017/1115/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 3822 क्रमागत

श्री अनिरूद्ध सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कोई-न-कोई बाइ-लॉज ज़रूर वॉयलेट हुए होंगे इसीलिए लीज़ कैंसिल हुई है। यह बात बिल्कुल ठीक है। परन्तु इसको पुनः कैबिनेट में लाने की क्या ज़रूरत थी जबकि केस पतांजलि योग पीठ द्वारा कोर्ट में दायर किया गया था? कैबिनेट में लाने की क्या ज़रूरत थी कि इस पर विचार करेंगे? यह तो 'Give & Take' वाला मामला है कि आप लोग आरोप वापिस लो तो हम आपको जमीन लीज़ पर देंगे। यह सरासर गलत है।

मेरा आग्रह है कि मैंने यह जमीन व्यक्तिगत रूप से भी देखी है। इसमें अनाथ आश्रम बन सकता है, गौसदन बहुत अच्छा बन सकता है क्योंकि जगह बहुत अच्छी है। यहां स्पोर्टस कम्प्लैक्स बहुत अच्छा बन सकता है, इस जमीन को उस परपज़ के लिए उपयोग में लाया जाए। क्या आप हाउस में आश्वस्त करेंगे कि यह लीज़ पुनः उन्हें न दी जाए? क्योंकि एक तो उन्होंने बाइ-लॉज वॉयलेट किये और फिर दोबारा एप्लीकेशन दे दी कि हमारे को दोबारा जमीन लीज़ पर दे दी जाए और मामले को कंसीडर किया जाए। मेरा आग्रह है कि इसको कंसीडर न करके इसमें कुछ और एक्टिविटीज़ की जाएं और पतांजलि योग पीठ को जमीन न दी जाए।

Health Minister: Mr. Speaker, Sir, first, I would like to reply to Prof. Prem Kumar Dhumal's queries. Infact, the project reports submitted by the Patanjali Yogpeeth, was for another land. Your Cabinet, your wisdom decided to give another land and in that memorandum there was an over writing and cutting. They have changed the place of the land. That is one thing. Similarly, Sir, the lease is sanctioned by the Cabinet, canceled by the Cabinet, so the representation too has to be decided by the Cabinet. We have not taken any final decision as yet. But this is a fact that they had made allegations against the State Government and the State Government gave a rejoinder affidavit to the Hon'ble High Court. That was also very important. So whatever decision the State Government or the Cabinet will take, everything will be taken care of.

15.03.2017/1115/SS-AS/2

डॉ राजीव बिन्दल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि पतांजलि योग पीठ द्वारा इसमें योग का प्रशिक्षण देने के लिए; पंचकर्म, षठकर्म चिकित्सा पद्धति के लिए; लोगों के इलाज के लिए और जड़ी-बूटी उत्पादन की ट्रेनिंग और इस प्रकार के काम, जिससे लोगों को लाभ होगा, उस परपज़ के लिए यह एलॉटमैंट की गई थी?

Speaker: This is not an issue.

Dr. Rajiv Bindal: It is the issue.

Speaker: It is the issue of the land only.

डॉ राजीव बिन्दल: भूमि दी किस चीज़ के लिए थी?

Speaker: This pertains to the lease of land

Dr. Rajiv Bindal: The lease of land for what purpose? It was for the purpose of Social service.

Speaker: The basic issue is that the Government has given land. It pertains to the land only.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है जैसे इन्होंने कहा कि किन-किन परपज़ के लिए दी गई थी। इसमें मेन परपज़ मैडिशनल हर्बज़ को प्लांट करने का था। इन्होंने बाकी शर्तें पूरी कोई नहीं की, सिर्फ एक की कि फाइव स्टार होटल बनाने का काम शुरू हो गया। जिस परपज़ के लिए लीज़ मांगी थी, वह कोई परपज़ हल नहीं हुआ। वहां कोई मैडिशनल प्लांट नहीं लगा हुआ है। एक बात और है कि यह इंदिरा आवास योजना के तहत पंजाब गवर्नमैंट में लेट राजा यादविन्द्र सिंह के समय इंदिरा होली-डे होम के नाम पर था और जब यह एरिया हिमाचल में आया तो यह एरिया स्टेट गवर्नमैंट का बन गया। इसलिए सब कुछ विचार करने के बाद every pros and cons will be looked into and there after the Government or the Cabinet will decide it and will take decision.

अगला प्रश्न जारी श्रीमती के0एस0

15.03.2017/1120/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्या: 3823

श्री रवि ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपका जो जवाब आया है, उसमें जो आपने लाहौल स्पिति का क्षेत्रफल राज्य के टोटल एरिया का 24.85 प्रतिशत बताया, क्या वजह है कि आपका पांगी, भरमौर का जो एफोरैस्टेशन का बजट है, वह दोगुना है? क्या लाहौल-स्पिति में इसकी जरूरत नहीं है? यदि है, तो क्या इसका प्रावधान करेंगें?

दूसरे, जो वहां पर खाली पोस्टें हैं, उनको आप कब तक भर देंगें?

तीसरे, जितनी भी हमारे वहां पर बिल्डिंग्ज़ बन रही हैं, जैसे हट्स बन रहे हैं, रैस्टहाऊस बन रहे हैं, गार्ड हट्स बन रहे हैं, उनके लिए भी काफी कम मात्रा में बजट का प्रावधान किया गया है। क्या इसका प्रावधान करने की भी कोशिश करेंगें, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि रवि ठाकुर जी ने कहा कि भरमौर और पांगी में बजट ज्यादा है, लाहौल और बाकी क्षेत्रों में कम है। भरमौर और पांगी में रावी नदी पर जहां से रावी नदी निकलती है, वहां से ले कर थीन डैम तक अधिकतकर हाईडल प्रोजैक्ट्स बन कर तैयार हुए हैं। थीन डैम-I, II, चमेरा-I, चमेरा- II, चमेरा-III , बुड्डल प्रोजैक्ट, जी.एम.आर. का प्रोजैक्ट, होली बजौली, कुठेड़ प्रोजैक्ट और एक जहां से रावी नदी निकलती है, वहां भी बन रहा है। तो जो वनरोपण का पैसा डिपोज़िट होता है, केम्पा का पैसा होता है, उसको खर्च करने के लिए जो पंचायतें उसमें आती हैं, उनमें वह डवैल्पमैंट का पैसा, लाडा का पैसा खर्च होता है। उसमें यह पैसा भरमौर और पांगी के लिए है। क्योंकि लाहौल-स्पिति में अभी तक कोई भी हाईडल प्रोजैक्ट या माइक्रो हाईडल प्रोजैक्ट नहीं बना है, इन्वैस्टिगेशन स्टेज पर है। अगर कुछ नालों पर बने हैं तो वे सरकारी तौर पर हिमाचल प्रदेश

इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के हैं। वहां से तो पैसा नहीं आएगा लेकिन ट्राईबल एरिया में 9 प्रतिशत जो प्रदेश का बजट है, उसके मुताबिक सारे ट्राईबल एरिया में पैसा सब प्लान के तहत जाता है। ट्राईबल एरिया के लिए एफोरैस्टेशन के लिए 18.51 प्रतिशत बजट जाता है और लाहौल में 4.92 करोड़ रुपया दिया गया है। उसके तहत यह पैसा खर्च हो रहा है । जहां तक माननीय सदस्य जी ने कहा है कि मुलाज़िमों की कमी है तो भरमौर में 102 पोस्टों में से 85 भरी हैं और 17 खाली है। पांगी में 100 पोस्टें हैं, 78 भरी है, 22 खाली है। लाहौल में 90 में से 61 भरी है और 29 खाली हैं। किन्नौर में 179 हैं जिनमें से 147 भरी है और 32 खाली हैं और वाइल्डलाइफ स्पिति में 68 पोस्टें हैं जिनमें से 44 भरी है और 24 खाली हैं। टोटल 124 पोस्टें खाली हैं। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में गाड्र्ज़ की, क्लर्कों की और बाकी पोस्टें भी दी हैं और उनको भरने की प्रक्रिया जारी है। और जो रिक्त पदों की पोजीशन बताई गई है, भविष्य में उनको भी भर दिया जाएगा ताकि कोई भी समस्या न रहे।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री महोदय ने सभा पटल पर रखी है, उसके अन्तर्गत भरमौर में हर्बल/मैडिसिनल प्लांट्स के लिए शून्य है जबकि बाकी मदों में तीन-तीन करोड़ रुपया है। इसके क्या कारण है? क्या वहां पर कोई जड़ी-बूटी नहीं है या आप उसमें इंट्रस्टिड नहीं हैं? यह सूचना केवल ट्राईबल एरियाज़ तक सीमित है, प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से इतना ही था लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि प्रदेश के अन्य भागों में भी बहुत ज्यादा जड़ी-बूटी पैदा होती है। जैसे सिरमौर में कीड़ा जड़ पांच हजार रुपये किलो जाती है । नाग छतरी

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

15.3.2017/1125/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 3823---------- क्रमागत

श्री महेश्वर सिंह जारी----------

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के क्षेत्र में है और हमारे क्षेत्र में भी है। भांग और अफीम के लिए अगर कोई बदनाम क्षेत्र है तो चौहार घाटी और मलाना है। क्या वैकल्पिक रोजगार देने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आप वहां जड़ी-बूटी को ज्यादा प्रोत्साहन देंगे ताकि उनकी आजीविका का साधन बने और जो मादक वस्तुओं का व्यापार करते हैं उस पर पूर्ण रूप से विराम लग लाए। क्या सरकार ऐसा करने का विचार रखती है या नहीं?

Forest Minister: Speaker Sir, this question is only for tribal area. अगर महेश्वर सिंह जी चाहते हैं कि बाकी एरिया में भी ख्याल रखा जाए तो उसके लिए हम हर साल बजट देते हैं। हमारा जो वाइल्ड लाइफ एरिया है हम उसी के मुताबिक उसका पालन-पोषण करते हैं। यह प्रोजैक्ट आयुर्वेदिक विभाग का है और यह विभाग हर्बल प्लांट पैदा करता है इसलिए इसका जवाब भी आयुर्वेदिक विभाग ही दे सकता है। आपने जैसे बताया कि फलां-फलां जड़ी-बूटियां हैं उनका हम नेचर के मुताबिक ध्यान रखते हैं और उसके लिए पैसे का प्रावधान करते हैं। जहां तक आपने कहा कि यह भरमौर में जीरो है तो जहां रिक्वायरमैंट है वहां हर जगह उसके मुताबिक पैसा दिया हुआ है और उसी के अनुसार काम होता है।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का यह कथन कि केवल ट्राइबल एरिया के लिए सीमित है तो यह जवाब ठीक नहीं है। हम आपसे कोई ऐडिशनल इनफोर्मेशन नहीं मांग रहे हैं, information is already with you. जो जड़ी-बूटी पैदा होती है उसके लिए परमिट आप देते हैं और सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों में दिया है। एक खाने है कोई और वही लेता है तथा जड़ी-बूटी हर जगह से जाती है। इसलिए मेरा स्पैसिफिक प्रश्न था कि जहां हमारे इलाके भांग और अफीम की खेती के कारण बदनाम हो रहे हैं, शायद वहां लोगों की मजबूरी भी है इसलिए वैकल्पिक रोजगार

15.3.2017/1125/av/dc/2

देने के लिए क्या आप इस व्यवस्था को देखेंगे तथा वहां पर इसके अंतर्गत पैसा खर्च करेंगे? एक तरफ तो आपने पांगी, किन्नौर तथा बाकी जगह पर प्लांटेशन के लिए पैसा खर्च किया है और जब हमारा प्रश्न आता है तो आपका उत्तर होता है कि यह काम आयुर्वेदिक विभाग का है, तो यह पैसा आपने कैसे दिया? मेरे पास यह सूचना में है।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पर्टिकुलर्ली ट्राइबल एरिया के बारे में पूछा गया है और मैं उसी के बारे में जवाब दे रहा हूं। आपने अलग से प्रश्न करना फिर हम आपको उस हिसाब से जवाब देंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने श्री महेश्वर सिंह जी के प्रश्न के जवाब में कहा कि यह केवल ट्राइबल एरिया के लिए सीमित है जबकि प्रश्न के 'बी' भाग में दिए गए उत्तर के अनुसार आपने 18,51,32,000/- रुपये की राशि एकत्रित की है। इसमें से कोल डैम की 7,1,49,000/- रुपये की राशि है। जब आप सारी फिगर दे रहे हैं कि आपको वहां से अफोरैस्टेशन,वाइल्ड लाइफ और हर्बल मैडिसिनल प्लांट के लिए आया और आपने ट्राइबल एरिया में काम किया तो पैसा तो आपको कोल डैम ने भी दिया। कोल डैम से 7.1 करोड़ रुपये के लगभग राशि आई है। जब ट्राइबल का पैसा आपने ट्राइबल एरिया में ही खर्च करना है तो प्रदेश की बाकी जगह जैसे सतलुज के किनारे आप कोल डैम का पैसा खर्च करते, यह तो आपके जवाब में है।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 226 करोड़ रुपये की राशि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एरिया में खर्च होगी और पैसा इसी के लिए मिला है। जहां तक आप जड़ी-बूटियों की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा है कि जड़ी-बूटियां जंगल में रूटीन में पैदा होती है और उसका 10 ईयर फैलिंग प्रोग्राम होता है। पहले एक रैंज खोल दी जाती है और दूसरी रैंज तैयार हो जाती है। इस ढंग से इनका पालन-पोषण होता है और उसके लिए भी पर्याप्त पैसे का प्रावधान होता है। हर चीज जैसे प्लांटेशन के लिए प्रावधान होता है वैसे ही इसके लिए भी पैसे का प्रावधान होता है। अब जर्मन सरकार की तरफ से

15.3.2017/1125/av/dc/3

जायका के अंतर्गत 800 करोड़ रुपये की राशि का एक नया प्रोजैक्ट मंजूर हुआ है उसमें पूरे ट्राइबल एरिया के साथ-साथ दूसरे एरियाज भी लिए गए हैं।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय , जब महेश्वर सिंह जी प्रश्न कर रहे हैं तो मंत्री जी ट्राइबल की बात कर रहे हैं और यहां प्रश्न के 'बी' पार्ट में पूरे प्रदेश का जवाब दे रहे हैं। आपको जो 18,51,32,000/- रुपये की राशि आई इसमें से 15.44 करोड़ रुपये की राशि स्टेट प्लान और कोल डैम की है।

श्री वर्मा द्वारा जारी

15/03/2017/1130/टी0सी0वी0/ए0जी0/1
प्रश्न संख्याः 3823 ..... क्रमागत
श्री रविन्द्र सिंह ..... जारी।

हमारा प्रश्न यह है कि जब ये पैसा स्टेट प्लॉन और कौल डैम का है, तो इस पैसे को पूरे प्रदेश में खर्च करना चाहिए था। जबकि आप इसको ट्राइब्ल में शो कर रहे हैं। आपने सराहन में भी पैसे दिए हैं।

वन मंत्रीः यह जो 226 करोड़ रूपया हमने मंजूर करवाया है, यह वाइल्ड लाईफ सेंचुरी एरिया में सारे प्रदेश के अन्दर खर्च होगा not only in tribal areas.

15/03/2017/1130/टी0सी0वी0/ए0जी0/2
प्रश्न संख्याः 3824

श्री गोविन्द राम शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सिक्योरिटी कब वापिस हुई? दूसरा, 'ग' भाग में इन्होंने कहा है कि आदेश कर दिए हैं। ये आदेश कब हुए ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, एम.एन.डी.ए.वी., चार हमारे डेंटल कॉलेजिज़ हैं। इनमें फीस के अलावा हॉस्टल में रहने और सामान इस्तेमाल करने की सिक्योरिटी लेते थे, लेकिन अब 2016-17 से स्पष्ट आदेश कर दिए गये हैं कि भविष्य में कोई सिक्योरिटी न ली जाये। जो सिक्योरिटी छात्रों से ले ली हैं, उस सिक्योरिटी को शीघ्रातिशीघ्र उनको वापिस कर दिया जाये और यह प्रोसैस शुरू हो गया है।

श्री गोविन्द राम शर्माः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन छात्रों से यह सिक्योरिटी ली गई थी, उन छात्रों को आज से 5-6 महीने पहले डिग्रियां भी मिल चुकी हैं, इसमें पूरे प्रदेश से छात्र हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है। आज भी मुझे दूरभाष पर लोगों ने बताया कि अभी तक उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है। इन छात्रों और उनके परेंट्स के बार-बार कॉलेजों के चक्कर लग रहे हैं और वहां से उनको खाली हाथ वापिस आना पड़ रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि विभाग को सख्त आदेश देने की कृपा करें कि उनको तुरन्त सिक्योरिटी वापिस की जाये।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है और हमारे डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च ने इन चारों मेडिकल कॉलेजों को इंस्ट्रक्शन्ज़ जारी कर दी हैं कि वर्ष 2016-17 में कोई सिक्योरिटी न ली जाये। अब वह इस साल से कोई सिक्योरिटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिन छात्रों से सिक्योरिटी ली थी और जैसे ही वे छात्र पास आउॅट हो रहे हैं, उनको भी हमने एक समय सीमा निर्धारित की हैं कि जल्दी-से-जल्दी उन छात्रों की सिक्योरिटी वापिस करें। मैं बता देना चाहता हूं कि 2010-11 के बैच के जो छात्र थे, उनमें सिर्फ 17 की सिक्योरिटी बाकी बची है और 41 छात्रों की सिक्योरिटी वापिस कर दी गई हैं। जिन छात्रों की सिक्योरिटी बाकी बची है, उसके लिए सभी कॉलेजों को सख्त आदेश कर दिए गये हैं कि सिक्योरिटी शीघ्रातिशीघ्र वापिस करके हमें (सरकार) इंटीमेट करें।

प्रश्न समाप्त

15/03/2017/1130/टी0सी0वी0/ए0जी0/3

प्रश्न संख्याः 3825

डा0 राजीव बिंदलः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है, उसके अनुसार धर्मशाला की आबादी कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बढ़ाई गई और उस आधार पर उसको कॉरपोरेशन बनाया गया।

श्रीमती एन0एस0 .... द्वारा जारी।

15/03/2017/1135/ एन0एस0/ए0जी0 /1

प्रश्न संख्याः 3825 -- क्रमागत

डॉ0 राजीव बिन्दल -----जारी

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इसमें नये क्षेत्रों का समावेश किया गया उससे पहले धर्मशाला की कितनी आबादी थी और सोलन, नाहन और मण्डी की कितनी आबादी थी? इसमें अन्य क्षेत्रों का समावेश क्यों नहीं किया गया ताकि उनको भी कॉर्पोरेशन बनाया जा सके। दूसरा, आपने कहा है कि केंद्र सरकार से स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत 500 करोड़ रूपये की धनराशि प्राप्त होगी। परन्तु जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके पृष्ठ 27 के ऊपर पैरा नम्बर : 58 में लिखा है कि 2,109 करोड़ रूपये की राशि स्मार्ट सिटी के लिए प्राप्त होगी। आपने मेरे प्रश्न के जवाब में 500 करोड़ लिखा है। मुख्य मंत्री जी ने 2,109 करोड़ लिखा है। इसमें से कौन-सी बात सही है? तीसरा, जब केंद्र सरकार का पैसा था तो टोटल पब्लिसिटी में प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के मंत्री की ही पब्लिसिटी क्यों की, केंद्र सरकार का नाम उस पब्लिसिटी में क्यों नहीं लिया गया?

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में आंकड़ा रखा है वह बिल्कुल सही है और जो दूसरा आकंड़ा है वह भी बिल्कुल सही है। पहले तो माननीय सदस्य अपने प्रश्न को पढ़ें। इन्होंने 'ख' भाग में लिखा है कि धर्मशाला नगर को स्मार्ट सिटी घोषित होने के उपरांत कितनी सहायता राशि केंद्र से मिलेगी? तब हमने बताया कि केंद्र से 500 करोड़ रूपये की राशि मिलेगी। पूरा प्रोजैक्ट 2,109 करोड़ रूपये का

है। उसमें से केंद्र से 500 करोड़ आना है। बाकी जो है इसमें गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का शेयर 488 करोड, स्टेट शेयर 500 करोड़, कनवरजैंस विद अदर स्कीमज़ 253 करोड़, पी0पी0पी0 मोड 669 करोड़ रूपये और बेनिफिशरीज़ और यूज़र्ज का 134.42 करोड़ तथा रेवैन्यू का 63.50 करोड़ है। यह टोटल प्रोजैक्ट 2,109 करोड़ रूपये का है। हमने बजट में प्रोजैक्ट की कोस्ट बतायी है। आपने प्रश्न में पूछा कि सैंटर से कितनी राशि मिलेगी तो वह 500 करोड़ ही मिलेगी। दूसरा, आपने पूछा है कि धर्मशाला को क्यों बनाया गया और बाकी एरियाज़ की कितनी आबादी थी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाहन की आबादी 29,500, मण्डी की आबादी 26,430 और सोलन की आबादी 39,456 है।

15/03/2017/1135/ एन0एस0/ए0जी0 /2

डॉ0 राजीव बिन्दल : सर, सोलन की आबादी 49,456 है।

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) : मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें सोलन की आबादी 39,456 है। हम इसका पता कर लेंगे और फिर इसको रैक्टिफाई कर देंगे। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इस स्मार्ट सिटी के लिए 14 शहरों ने अपना प्रपोजल दिया था। इसमें धर्मशाला, सोलन, मण्डी, हमीरपुर, मनाली, कुल्लू, बिलासपुर, श्री नैना देवी जी, डलहौजी, तलाई, भुन्तर, नारकंडा और बन्जार आदि शहरों के प्रपोजल आए थे। नाहन ने तो इसमें अप्लाई भी नहीं किया था। आप वहां के सम्मानीय विधायक हैं तो आप वहां से पहले अप्लाई तो करवाते तब आप नाहन की बात करते। जिन 14 शहरों ने अप्लाई किया है उनका मूल्यांकन किया गया। आप मानते हैं कि क्या गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने मूल्याकंन गलत किया है? भारत सरकार ने इसका मूल्याकंन किया है और उन्होंने ही धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के लिए चुना है।

डॉ0 राजीव बिन्दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी विषय और प्रश्न को होशियारी के साथ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 'क' भाग में पूछा है कि इसको जब

कॉर्पोरेशन बनाया उस समय बाकी क्षेत्रों को कॉर्पोरेशन क्यों नहीं बनाया गया और इसको कार्पोरेशन बनाते समय धर्मशाला की कितनी आबादी थी?

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

15/03/2017/1140/RKS/AS/1

प्रश्न संख्याः 3825.... जारी

डॉ0 राजीव बिन्दल...जारी

वास्तव में 22 हजार की आबादी वाले धर्मशाला को नगर निगम बना दिया गया, जबकि 49, 456 की आबादी वाले सोलन को छोड़ दिया गया। अब उसको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न माननीय उद्योग मंत्री जी को ट्रांसफर हुआ है इसलिए माननीय मंत्री जी परेशानी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। शायद माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने इसीलिए यह प्रश्न ट्रांसफर करवाया होगा। मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा-सीधा सवाल है कि धर्मशाला कि आबादी कितनी थी जब उसमें नए क्षेत्रों का समावेश किया गया और बाकी को कॉर्पोरेशन बनाने से पहले क्यों छोड़ा गया?

उद्योग मंत्री(प्राधिकृत)ः अध्यक्ष महोदय, धर्मशाला स्मार्ट सिटी क्यों न बनाई जाए? (व्यवधान)... धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण शहर है। धर्मशाला को हाल ही में दूसरी राजधानी घोषित किया गया है। धर्मशाला विंटर कैपिटल पहले से ही है। विधान सभा वहां पर है। धर्मशाला तिब्बतन निर्वासित सरकार की राजधानी भी है। कोर्पोरेशन वहां पर बन गई है। धर्मशाला प्रदेश के सबसे बड़े ज़िला कांगड़ा की हैडक्वार्टर है। धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने में इनको क्या एतराज़/ आपत्ति है?

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय मंत्री जी आप केवल विषय को बदलकर अपनी बात जस्टीफाइ नहीं कर सकते हैं। हमारा सवाल सीधा है कि आपने कोर्पोरेशन बनाते समय केवल धर्मशाला को ही क्यों कोर्पोरेशन बनाया, बाकी को कॉर्पोरेशन क्यों नहीं बनाया गया? स्मार्ट सिटी तो केन्द्र सरकार की देन है, उसके लिए आप धन्यवाद कीजिए। उसमें

आपका क्या योगदान है? आपका कुछ भी योगदान नहीं है। हमारा यह कहना है कि बाकी को कॉर्पोरेशन बनाने की दिशा में क्या आप विचार करेंगे?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूर्व सरकार में बहुत महत्वपूर्ण मंत्री रहे हैं। हैल्थ डिपार्टमैंट जोकि बहुत बड़ा डिपार्टमैंट है, उसका इन्होंने संचालन

15/03/2017/1140/RKS/AS/2

किया है। उस समय हैल्थ डिपार्टमैंट में 'नेशनल हैल्थ मिशन' के तहत तीन-चार सौ करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से आता रहा। क्या कभी आपने आदरणीय मनमोहन सिंह जी या गुलाम नबी आज़ाद जी का धन्यवाद किया? क्या आपने कभी उनका फोटो लगाया? "औरों को नसीहत, खुद मिंयां फज़ीहत"।

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय मंत्री जी जो मैं पूछ रहा हूं आप उसके बारे में उत्तर दीजिए । क्या आप बाकियों को कोर्पोरेशन बनाने पर विचार करेंगे या नहीं, इसके बारे में आप मुझे बताइए?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, धर्मशाला पूरी तरह जस्टीफाइड है। (व्यवधान).. एक मिनट आप सुनिए। हाई कोर्ट में भी इसका मसला गया है। सैंटर के पास भी गया है। पहली बार जब स्मार्ट सिटी के लिए 20 शहर घोषित हुए थे तो उसमें धर्मशाला का नाम नहीं आया था। बनारस का नाम भी नहीं आया था। लेकिन उसके बाद दोबारा मूल्यांकन हुआ।(व्यवधान)..क्यों आपका सवाल स्मार्ट सिटी का है।(व्यवधान).. आप पहले पूरा जवाब लें फिर उसके बाद आप भी बोलें। (व्यवधान).. अध्यक्ष महोदय, ये सिलैक्टिव रिप्लाई चाहते हैं। ये स्मार्ट सिटी का पूरा रिप्लाई नहीं चाहते कि स्मार्ट सिटी का मूल्यांकन कैसे हुआ? (व्यवधान).. हम पूरी बात भी बताएंगे। नगर निगम तब बनता है जब चुनाव होते हैं। आने वाले समय में ये उन पंचायतों जिनकी आबादी 39 हजार है को ऐड करवाना चाहते हैं। नगर निगम के लिए उनको जस्टीफाइड करवाना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी के लिए जस्टीफाइड करवाना चाहते हैं। उन पंचायतों के नाम आप एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमैंट को दें, हम उसकी प्रपोजल तैयार करवाएंगे। जब चुनाव आएंगे तो उस समय देखेंगे कि नगर निगम के चुनाव के समय क्या करना है।

अगला प्रश्न श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

15.03.2017/1145/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 3826

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी है, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक उसको पढ़ा है। आपका "ख" भाग का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है। उसमें संख्या दिखाई गई है कि वहां पर प्रदेश से कितने मरीज़ जाते हैं। कुल मिलाकर आपने यह 5346 की संख्या दिखाई है। सिरमौर से आपने केवल 19 रोगियों की संख्या दिखाई है जबकि कई जगह यह संख्या शून्य है। क्या यह संख्या एक दिन की है या पूरे साल की है? सिरमौर से चण्डीगढ़ सबसे नजदीक है, यह सबको पता है। मुझे लगता है कि यहां बैठे वहां के माननीय विधायक भी सहमत होंगे कि वहां से रोगियों की संख्या इस आंकड़े से कहीं बहुत ज्यादा है। कौन-सा वह रजिस्टर है जिसमें आप यह आंकड़ें मेंटेन करते हैं? यह सूचना कहां से आई है, एक तो मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरे, "ग" भाग के उत्तर में आपने कहा है कि सैक्टर 24 और 25 में पहले से ही सरायों का प्रबंध है जिसको लोक निर्माण विभाग देखता है और वहां पर एक जे.ई. नियुक्त है जो इसकी लाइजनिंग करता है। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा था कि क्या आप इसको स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लेंगे ताकि लोगों को यह सुविधा सही ढंग से प्राप्त हो। वहां पर जब लोग मरीज़ लेकर जाते हैं, जब तक उनके सारे टैस्ट पूरे नहीं होते तो उनको बाहर ही रहना पड़ता है। अस्पताल में रोगी तब एडमिट होता है जब उसके सारे टैस्ट पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को एडमिट होने तक दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इन दोनों सरायों को स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लेंगे और जो वहां पर खाली जगह पड़ी है, वहां डौरमैटरीज का निर्माण करेंगे ताकि यहां से जाने वाले मरीज़ों और तीमारदारों को वहां पर एक अच्छा और सस्ती दर पर स्थान उपलब्ध हो सके?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने 5346 रोगियों की संख्या दी है, यह जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि की है और यह पूरे हिमाचल प्रदेश की है। किस-किस जिले से कितने लोग गए हैं, उसके भी पूरे

15.03.2017/1145/SLS-AS-2

आंकड़े मैंने उपलब्ध करवाए हैं। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं सारी फिगर इनको दे सकता हूं। जो केस रैफर किए जाते हैं, वह जिला अस्पताल से रैफर किए जाते हैं। जो केस विभाग के रिकॉर्ड में एंटर होते हैं, हमने यह उन्हीं की फिगर उपलब्ध करवाई है। यह आंकड़े बिल्कुल सही हैं और यह एक साल के हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी कहा है कि जो रोगी और उनके अटैंडैंट वहां पर ठहरते हैं, उनको दिक्कत पेश आती है। मैं बताना चाहूंगा कि उनके लिए वहां पर दो बड़ी-बड़ी सरायों का निर्माण किया गया है। सरायों में यह भी व्यवस्था की गई है कि दिन में 5 बार ऐंबुलैंस सरायों से अस्पताल जाती है और 5 बार ही अस्पताल से सरायों तक वापिस आती है। वहां पर लोक निर्माण विभाग का जे. ई. इसलिए रखा गया है क्योंकि वह उन सरायों की मेंटेनैंस का काम देखता है और वह 24 घंटे उसी जगह पर रहता है। अभी तक कभी भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि जो पेशैंट्स वहां एडमिट हुए, उनके अटैंडैंट के वहां रहने में दिक्कत पेश आई हो या जिन पेशैंट्स को रैफर किया गया है, उनको दिक्कत आई हो। रैफर होने के बाद जग तक वह दाखिल नहीं होते हैं, उनके रहने की वहां व्यवस्था कर दी जाती है। जो जे.ई. वहां नियुक्त है, वह रिपेयर भी करता है और किसी भी तरह से होने वाली तोड़-फोड़ को भी ठीक करता है। वहां पर ठीक से व्यवस्था चल रही है और कोई शिकायत नहीं है। अगर कोई शिकायत इसके बारे में आती है, तो सरकार इसका कोई दूसरा सबस्टिच्यूट सोचेगी।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बात का विश्वास कौन करेगा कि सारे सिरमौर से केवल 19 रोगी वहां गए। आप इस रिकॉर्ड को चैक करिए। कई जगह पर तो शून्य का आंकड़ा है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां से पी.जी.आई. के लिए रोगी रैफर नहीं होता।

लाहौल से भी होते हैं, किन्नौर से भी होते हैं और हर जगह से होते हैं। इसलिए इसको वैरिफाई करिए।

जारी ...श्री गर्ग जी द्वारा

15/03/2017/1150/RG/DC/1

प्रश्न सं.3826--क्रमागत

श्री महेश्वर सिंह---जारी

दूसरा, शिमला का देख लीजिए शिमला से रैफर होने वालों की संख्या उत्तर में 'जीरो' दी हुई है। तो क्या यहां से कोई पी.जी.आई. नहीं जाता? कृपया आप इसको देखिए तो सही और पहले आप इसको अवलोकन करिए उसके पश्चात उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बल देकर कहना चाहूंगा कि ये आंकड़े ठीक नहीं हैं इनको सही करिए।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि वहां सारा कुछ जे.ई. की देखरेख में होता है और वहां से कोई शिकायत नहीं आई। तो जब वहां अन्दर जाने की ऐडमीशन ही नहीं मिलती, शिकायत कहां से आएगी? इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को वहां सुविधा मिले क्या ये कोई लायज़न ऑफिसर उस सराय में बैठाएंगे? इसके अलावा जो पी.जी.आई.जाते हैं वहां डॉक्टर्ज से मिलने के लिए ही उनको घण्टों लग जाते हैं, हां, जब से माननीय नड्डा जी ने अपना एक डॉक्टर वहां लायजनिंग ऑफिसर रखा है, थोड़ी सी सुविधा वहां उपलब्ध हुई है और वह जाकर कुछ तालमेल बैठाते हैं। उसी तर्ज पर क्या आप भी कोई इस प्रकार का ओ.एस.डी. उसी सराय में बैठाएंगे ताकि वह डॉक्टर्ज के साथ भी लायजनिंग करे और मरीजों को समय पर ऐडमीशन वगेरह मिले? वहां तो बैड लेने की भी बहुत दिक्कत आती है, सिफारिशें लगानी पड़ती है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां पर कोई एच.ए.एस. ऑफिसर का पद नहीं है और वह आयोग से करवाना पड़ेगा तब होगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि पद की क्या जरूरत है, आप किसी को भी वहां लायजनिंग ऑफिसर लगा दीजिए और पद सृजित करवाना भी आप ही का काम है, यह भी सरकार के माध्यम से होगा कहीं और से नहीं होगा। तो वहां रहने की और लायजनिंग ऑफिसर की माननीय मंत्री जी क्या व्यवस्था करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि वहां व्यवस्था ठीक चली हुई है। इन्होंने एच.ए.एस. अधिकारी को वहां बैठाने की बात कही, तो वहां एच.ए.एस. ऑफिसर हमारा कोई ज्यादा काम नहीं करेगा। हमारे पांच एच.ए.एस. अधिकारी पी.जी.आई. में डेपुटेशन पर बैठे हैं। अगर हमारे लोगों को वहां जरूरत पड़ती है, तो उप निदेशक, वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी वहां बैठे हैं जब भी किसी को कोई परेशानी होती है वे मुझे टेलीफोन करते हैं, तो उनको टेलीफोन करके ऐडमीशन भी दिला देते हैं।

15/03/2017/1150/RG/DC/2

जहां तक आप चाहते हैं कि किसी एच.ए.एस. अधिकारी को वहां लगा दिया जाए, **तो जो हमारे एच.ए.एस. अधिकारी(प्रोटोकोल) परवाणु में बैठे हैं, हम कुछ काम उनको सौंप सकते हैं,** लेकिन जो हमारे बाहर के एच.ए.एस. अधिकारी होंगे, उनकी तरफ पी.जी.आई. वाले कोई विशेष ध्यान नहीं देंगे। इसके अलावा जो हमारे एच.ए.एस. अधिकारी वहां लगे हैं वे डॉक्टर्ज को टेलीफोन करते हैं क्योंकि उनको पता है उनसे काम लेना होता है और डॉक्टर्ज उनकी बात मानते हैं। इसके अलावा उप निदेशक का पद प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पद है और हमारे आई.ए.एस. अधिकारी श्री अमिताभ अवस्थी वहां बैठे हैं। जब भी कोई मरीज वहां जाता है और उनको मिलता है, तो वे बाकायदा हमारी पूरी मदद करते हैं और डॉक्टर्ज से बात करके वे मरीज को ऐडमीशन दिलाने की कोशिश करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जहां तक सराय में ठहरने की व्यवस्था की बात की है, तो मैं इनको बता दूं कि मेरे पास ये आंकड़े मौजूद हैं। आप देखिए जनवरी, 2015 से लेकर दिसम्बर, 2015 तक 28,359 लोगों को दोनों सरायों में ऐडमीशन मिला है और अगर आप वर्ष 2016 का देखेंगे, तो दिसम्बर, 2016 तक भी 32,809 लोगों के अटैंडेंट्स को उन सरायों में ऐडमीशन मिली है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि शिमला से कोई रेफर नहीं हुआ। तो शिमला में भी हमारे यहां पी.जी.आई. के मुकाबले का अस्पताल है और शिमला में हर सुविधा उपलब्ध है। इसलिए यहां से कोई रेफर नहीं हुआ। लाहौल-स्पीति एवं किन्नौर के लोग इसलिए नहीं जाते कि किन्नौर के लोग पहले आई.जी.एम.सी. में दाखिल होते हैं और आपको पता है कि लाहौल के लोग पहले कुल्लू आते हैं और कुल्लू से यदि किसी को रेफर किया जाए, तो उसका रिकॉर्ड भी हम रखते हैं कि कौन सा केस कुल्लू से रेफर किया गया है। **इसलिए ये आंकड़े ठीक हैं, लेकिन फिर भी**

माननीय सदस्य को कोई शक या शंका है, तो इस बारे में मैं फिर विभाग से पूछूंगा कि ये आंकड़े ठीक हैं, अगर गलत होंगे, तो उनको सही करके सदन में रखेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां एक सीनियर आई.एस.एस. ऑफिसर डिप्टी डायरैक्टर बैठे हैं, तो क्या उन्हीं को यह ओ.एस.डी. का लायजनिंग का काम देंगे ताकि लोगों को असुविधा न हो? बात इन तक नहीं पहुंचती, लोग वहां दर-दर की ठोकरें खाते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे?

एम.एस. द्वारा मंत्री जी शुरू एवं प्रश्न जारी

15/03/2017/1155/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः3826 क्रमागत--

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उसको नोटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। वहां हिमाचल के हमारे 5 एच0ए0एस0 ऑफिसर्ज हैं और एक सीनियर आई0ए0एस0 ऑफिसर भी है। जब उनके पास लोग जाते हैं तो वे निश्चित तौर पर लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" के अंतर्गत हमने एक व्यक्ति को वहां बिठाया है जोकि इस योजना के अंतर्गत जो मरीज वहां आते हैं, उनको वह व्यक्तिगत तौर पर ले जाकर दाखिल करवाकर उनका उपचार भी करवाते हैं तथा उनको पैसा भी मौके पर ही उपलब्ध करवा दिया जाता है।

15/03/2017/1155/MS/DC/2

प्रश्न संख्याः 3827

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है, मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र चौपाल में हिमाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा जंगल हैं और मेरे ही चुनाव क्षेत्र से पिछली साल 300 करोड़ रुपये के लगभग फॉरैस्ट कॉरपोरेशन को रेवेन्यु आया है। मेरा जो क्षेत्र है बीच में देहा से लेकर चौपाल हैडक्वार्टर तक, वहां 30 किलोमीटर थिक फॉरैस्ट में रोड गई हुई है। उसमें फॉरैस्ट का

कोई भी विश्राम गृह नहीं है। मेरे क्षेत्र में जब बर्फ गिरती है तो वहां सड़कें बन्द हो जाती हैं क्योंकि उस क्षेत्र में 5-5 और 6-6 फीट बर्फ गिरती है। उस क्षेत्र के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं घोषणा की थी कि इस क्षेत्र में विश्राम गृह बनना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में विश्राम गृह बनना बहुत जरूरी है। हमारे बुजुर्गों ने ये जंगल संचित करके रखे हैं और उससे हिमाचल प्रदेश सरकार को बहुत राजस्व आता है इसलिए उस क्षेत्र के लोगों को भी कुछ लाभ मिलना चाहिए क्योंकि उस क्षेत्र के बीच में जो 30 किलोमीटर का स्पैन है, जब बर्फ गिरती है तो बहुत सारे लोगों को उस क्षेत्र में यातायात बन्द हो जाने के कारण बाहर ही रहना पड़ता है और सड़कों पर रात गुजारनी पड़ती है। इसलिए उस क्षेत्र में फॉरैस्ट विश्राम गृह की सुविधा मिलनी अति आवश्यक है।

वन मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं चौपाल व्यक्तिगत तौर पर गया था और वहां पर वास्तव में ही थिक फॉरैस्ट है। जब सर्दियों में बर्फ पड़ती है तो उस क्षेत्र में रास्ते बन्द हो जाते हैं और बीच में ही लोग स्टकऑफ हो जाते हैं। माननीय सदस्य और स्थानीय लोगों ने भी मुझे निवेदन किया था कि उस जंगल के सेंटर प्लेस में किसी एक स्थान पर इन्स्पैक्शन हट बनाई जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इन्हें कहा है और मैं भी इनसे प्रोमिस करता हूं कि वहां पर एक इन्सपैक्शन हट अगले साल बना दी जाएगी।

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो प्रश्न के "क" और "ख" भाग की सूचना दी है, वह सूचना मैंने विस्तार से मांगी थी। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे एरिया में पौधरोपण हुआ है और बहुत सारे विश्राम गृह रिपेयर हुए हैं। जैसे किस विश्राम गृह में क्या चीज रिपेयर हुई है और कितना पैसा किस चीज में खर्च किया है, हरेक विश्राम गृह की सूचना मैं चाहूंगा। इसके अलावा जहां पौधरोपण हुआ है

15/03/2017/1155/MS/DC/3

उसमें भी किस क्षेत्र में पौधरोपण हुआ है क्योंकि कई क्षेत्रों में 6-6 और 7-7 लाख रुपये का पौधरोपण हुआ है तो उसमें भी मैं जानना चाहूंगा कि कहां कितनी राशि से पौधरोपण हुआ है और किस स्पीशिज का पौधरोपण हुआ है तथा उस क्षेत्र में कितनी फैंसिंग हुई है उसका अलग से यदि डिटेल मिल जाए तो मैं आभारी रहूंगा। मैं मंत्री जी के ध्यान में यह भी लाना

चाहूंगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कागजों में शो करते हैं लेकिन स्पॉट पर कुछ नहीं होता है। मैं फिर उसके बाद माननीय मंत्री जी का दौरा उस क्षेत्र में करवाऊंगा जहां कागजों में है और स्पॉट पर कुछ नहीं है परन्तु इसकी यदि एक बार पूरी डिटेल मिल जाए कि हरेक फैंसिंग में कितने पैसे लगे, किस स्पीशिज की प्लांटेशन हुई और विश्राम गृहों पर कितना खर्च हुआ?

वन मंत्रीः अध्यक्ष जी, वैसे तो माननीय सदस्य को सूचना विस्तारपूर्वक दी गई है लेकिन इसके अलावा भी ये चाहते हैं कि सारे चौपाल क्षेत्र की सूचना विस्तृत रूप से दी जाए, तो सूचना इनको मुहैया करवा दी जाएगी।

जहां तक वर्ष 2016-17 का सवाल है तो

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

15.03.2017/1200/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 3827ः-----**जारी**---

वन मंत्रीः-----**जारी**---------

वन मण्डल चौपाल व बलसन वन क्षेत्र में 14 वन रक्षक हट, एक गैंग हट, एक फोरैस्ट रैस्ट हाऊस और दो ब्लॉक ऑफिसर्ज क्वार्टर्ज के निर्माण व मुरम्मत के लिए 32 लाख 14 हजार 700 रूपए दिए गए हैं, उसमें से 25 लाख 88 हजार रूपए खर्च हो गए हैं और 6 लाख 26 हजार 700 रूपए बचते हैं, वे अभी 31 मार्च से पहले खर्च कर दिए जाएंगे।

प्रश्नकाल समाप्त

15.03.2017/1200/जेके/एजी/2

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति का 167वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 147वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित है; और
ii. समिति का 168वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 152वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17), समिति का 67वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के

नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम व हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम सीमित से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं ।

15.03.2017/1200/जेके/एजी/3

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए बजट अनुमान

सामान्य चर्चा ।

अध्यक्षः अब वित्तीय वर्ष 2017-2018 पर सामान्य चर्चा होगी। माननीय सदस्य हंस राज जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं?

श्री हंस राजः अध्यक्ष महोदय, पिछले कल मेरी चर्चा रह गई थी उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। कल जब बजट अभिभाषण पर हम लोग चर्चा कर रहे थे उस समय वह चर्चा पूरी नहीं हुई थी।

अध्यक्षः वह नहीं होगी। आप अभी बैठिए। प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। फिर मैं आपसे पूछुंगा। अब वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों में वार्षिक द्वितीय विवरण पर आगे चर्चा आरम्भ होगी। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, मैं माननीय सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि हमारे पास तकरीबन 210 मिनट हैं और इस तरह हम आज का कार्यक्रम खत्म करेंगे। इसमें 15 लोग बोलने वाले हैं। सभी माननीय सदस्यों को 12 से 13 मिनट तक बोलने की इज़ाजत देंगे लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ज्यादा बोलना चाहेगा तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। यह मैं पहले बता रहा हूं क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे लोग बोलने से रह गए। वे कह रहे थे कि हमने बोलना था लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी समय सीमा से बहुत आगे चले जाते हैं। आप लोग बुरा न मानिए क्योंकि यह आपको पहले बता दिया है। अब बजट अनुमान पर चर्चा होगी। सबसे पहले श्री सतपाल सिंह सत्ती जी चर्चा में भाग लेंगे।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आपका क्या मैटर है? (Interruption) I don't know the matter.

श्री हंस राजः माननीय अध्यक्ष जी, पिछले कल मेरी स्पीच पूरी नहीं हुई थी।

Speaker: I was not present here. मुझे बताईए मामला क्या है?

15.03.2017/1200/जेके/एजी/4

श्री हंस राजः अध्यक्ष जी, ऐसा है कल जो विषय चला था, बजट अभिभाषण पर जब मैं बोल रहा था। मैंने केवल समापन ही करना था। सभापति महोदय, श्री कुलदीप कुमार जी ने पहले मुझे 10 मिनट दिए भी थे लेकिन उससे पहले ही हाऊस स्थगित कर दिया। मैं यहां पर अपना पूरा विषय रख ही नहीं पाया था।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, यहां पर कल की कार्यवाही दोबारा से नहीं चल सकती है।। am sorry.

श्री हंस राजः अध्यक्ष महोदय, यह कल की कार्यवाही नहीं है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बैठ जाईए। आप मान भी जाया करें। मैं जो रूलिंग दे रहा हूं उसके बाहर न जाएं। यह गलत बात है। मुझे माफ करना मैंने पहले गलत नाम कह दिया था। अब श्री कुलदीप कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च, 2017 को जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया है उसके ऊपर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 35,783/- करोड़ रुपये के व्यय का बजट पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। 10 मार्च, 2017 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने 11:00 बजे बजट पेश करना शुरू किया और साढ़े चार घंटे तक बजट पढ़ते रहे और मेरे विपक्ष के दोस्तों को पता नहीं क्या तकलीफ होती रही। एक चीज़ देखने वाली थी कि 11:00 बजे से बर्फबारी शुरू हुई और जब तक मुख्य मंत्री जी बजट पढ़ते रहे तब तक बर्फबारी होती रही और जैसे ही मुख्य मंत्री जी ने बजट खत्म किया तो बर्फबारी भी बंद हो गई। इस बजट से इन्द्र देवता भी खुश हो गए लेकिन विपक्ष के लोग उससे खुश नहीं हुए।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

पता नहीं, इनको उससे क्या परेशानी हुई? यह बजट सब वर्गों का हितैषी है चाहे वह नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो या व्यापारी वर्ग हो, सब वर्गों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने हितैषी बजट पेश किया है। क्योंकि चुनावों का वर्ष है इसीलिए मेरे विपक्ष के दोस्तों को इस बात की तकलीफ हो रही है कि यह बजट इनका सफाया करेगा और आने वाले चुनावों में इनको सदन तक पहुंचने नहीं देगा। आज मैं माननीय विपक्ष के नेता की अखबार में एक स्टेटमैंट पढ़ रहा था। एक अखबार में स्टेटमैंट आई है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने आगे कर्ज़ लेने का रास्ता बंद कर दिया है। यह कर्ज़ लेने का रास्ता बंद नहीं किया लेकिन यह जो बजट पेश किया है इसने भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों का रास्ता यहां तक बंद कर दिया है। हर वर्ग का इस बजट में ख्याल रखा गया है। नौजवानों खास करके किसानों का ख्याल रखा गया है। प्रदेश में आजकल नौजवानों की पापुलेशन 40 परसैंट के करीब है और नौजवानों का खास करके इस बजट में बहुत ख्याल रखा गया है।

यह माननीय सदन कई ऐतिहासिक लम्हों के लिए मशहूर रहा है और हतिहास के पन्नों में कई

15.03.2017/1205/SS-AG/2

बातें इसमें लिखी गई हैं। इसी तरह से जो बेरोजगारी भत्ता है जोकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में पेश किया है, यह भी एक ऐतिहासिक फैसला इस माननीय सदन से पास हो कर जायेगा। यह एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम होगा। मेरे विपक्ष के माननीय सदस्य अब बेरोजगारी भत्ते का भी विरोध कर रहे हैं। वैसे वे एक तरफ कहते हैं कि वे बेरोजगारों के बड़े हितैषी हैं लेकिन दूसरी तरफ जब उनको बेरोजगारी भत्ता मिलने लगा तो उसका भी विरोध करने लगे। अब इनका डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है।

जारी श्रीमती के0एस0

15.03.2017/1210/केएस/एएस/1

श्री कुलदीप कुमार जारी----

लेकिन ये बेरोज़गार नौजवान इनको बख्शने वाले नहीं हैं जिनको आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो मरहम लगाया है, जो गरीब बेरोज़गार नौजवान नौकरी के लिए जाते थे, जिनके पास किराये के लिए पैसा नहीं होता था, उनको आज एक हजार रु0 बेरोज़गारी भत्ता दे कर फायदा दिया है। विपक्ष के लोग आज इस भत्ते का विरोध कर रहे हैं तो वे बेरोज़गार लोग आपको बख्शने वाले नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की स्पीच सुन रहा था। इस बजट में जो खूबियां हैं विपक्ष के माननीय सदस्यों ने उनको न गिनने की कसम खाई है। उसमें कमियां ही निकालते रहे लेकिन ये कोई खास कमी नहीं निकाल पाए। इन्होंने यही कहा कि इसके

लिए पैसा कहां से आएगा, ये योजनाएं कैसे इम्पलीमैंट होंगी? और यही चिन्ता इनको सता रही है। हमारे एक कहावत हुआ करती थी कि ऊंट कपास ले कर चले और जब बूढ़िया ने देखा कि बहुत सारे ऊंट कपास ले कर जा रहे हैं तो वह बेहोश हो गई। बाद में जब उससे पूछा कि वह क्यों बेहोश हो गई तो बूढ़िया कहने लगी कि इस कपास को कातेगा कौन? तो बजट के बारे में भी इन लोगों ने इस तरह की ही बात की है। बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सभी वर्गों के हित की बात कही है, जो पैसा रखा है, हर स्कीम के साथ-साथ उसको इम्पलीमैंट करने का तरीका भी रखा है और इम्पलीमैंट करने के लिए पैसा भी रखा है और उसकी चिन्ता भी माननीय मुख्य मंत्री जी को है। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले विधायक निधि 50 लाख रु0 हुआ करती थी लेकिन पिछले चार सालों में यह बढ़ी है और अब विधायक निधि 1 करोड़ 10 लाख कर दी गई है, विपक्ष के साथी कहते हैं कि इसको 1 करोड़ 25 लाख करवाओ लेकिन आपने 1 करोड़ 10 लाख का भी धन्यवाद नहीं किया। आप तो थैंकलैस हैं। अच्छी बात का विरोध करना बुरा होता है। विधायक नीधि जो आपको 1 करोड़ 10 लाख रु0 मिल रही है, इसका भी अगर आप विरोध करते हैं तो आप सभी मुख्य मंत्री जी को

15.03.2017/1210/केएस/एएस/2

लिखकर दीजिए कि हमारा 1 करोड़ 10 लाख रु0 वापिस ले लीजिए। मांगना तो आप जानते हैं लेकिन जो आपको मिला है उसका धन्यवाद भी करिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, नाबार्ड के अंतर्गत कांग्रेस सरकार का एक ही लक्ष्य था कि सबका विकास, समग्र विकास और उस सबका विकास, समग्र विकास के सिद्धान्त को ले कर कांग्रेस सरकार चली और हर विधायक को नाबार्ड के अंतर्गत, आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत 70 करोड़ रु0 की स्कीमें देने का प्रावधान था। अब वह 80 करोड़ रु0 कर दिया गया है और आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। सभी विधायकों के क्षेत्रों को बराबर पैसा

मिलेगा। 10 करोड़ रु0 उसमें बढ़ा दिए गए हैं लेकिन आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा नहीं है।

जहां तक किसानों की बात आई, यह बजट जहां नौजवानों के लिए हैं वहीं किसान हितैषी भी है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

15.3.2017/1215/av/as/1

श्री कुलदीप कुमार जारी----------

प्रदेश में 90 प्रतिशत किसान है जो कि खेती-बाड़ी के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन इस बजट में किसानों के हित की बात की गई है। इस बजट में बागवानी विकास योजना के अंतर्गत किसानों-बागवानों के लिए वर्ल्ड बैंक से 1134 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री किवी प्रोत्साहन योजना चालू की गई है। यहां पर माननीय बिन्दल जी कल इस योजना का विरोध कर रहे थे अब वे यहां से चले गये हैं। मुख्य मंत्री किवी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बजट में जो 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है उनको पता नहीं इस योजना को चालू करने से क्या प्रोब्लम है। प्रदेश सरकार ने कृषकों को आवारा पशुओं, जंगली जानवरों तथा बंदरों की समस्या से निपटने के लिए मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना शुरू की है। हमारे प्रदेश में जंगली जानवरों और आवारा पशुओं की एक बहुत बड़ी समस्या है इसलिए खेती के रख-रखाव के लिए पहले जो कांटे वाली तार में सोलर या दूसरा कंरट देने हेतु 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी वह राशि अब बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दी गई है। उसके लिए भी बजट में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पोली हाउस के उपदान के लिए जो किसानों के फायदे की योजना है और इस योजना के अंतर्गत हमारे बहुत से किसानों ने फायदे उठाये हैं। पोली हाउस उपादान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को 2000 वर्ग मीटर से बढ़ाकर अब 4000 वर्ग मीटर किया गया है उसमें भी किसानों का फायदा है। इसके अतिरिक्त पोली शीट बदलने का जो प्रोग्राम था उसमें एक नया प्रोग्राम मुख्य मंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम चालू की गई है इससे भी किसानों का

फायदा होगा। इसके साथ-साथ उत्तम चारा उत्पादन योजना के अंतर्गत किसानों के लिए 7 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए जो सिंचाई की स्कीमें थी जिन्होंने बोर वैल लगाने है उसके लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान था। जिन किसानों ने अपने लिए पर्सनल बोर वैल लगाने है उसके लिए इस बजट में 10 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ हमारी प्रदेश सरकार किसानों-बागवानों को गैर मौसमी सब्जियां उगाने हेतु भी प्रोत्साहन दे रही है जिसका हमारे किसान-बागवान बहुत लाभ उठा रहे हैं। उसके लिए इस बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कल यहां पर धर्माणी जी ने भी बात कही थी कि हर घर में किसानों को बकरियां पालने के लिए अब एक नई स्कीम कृषक बकरी पालन योजना के नाम से शुरू की गई है जिसके अंतर्गत 60 प्रतिशत उपदान देने का प्रावधान किया गया है। ये सारी

15.3.2017/1215/av/as/2

योजनाएं किसानों-बागवानों के हित के लिए हैं। इसलिए यह बजट खासकर प्रदेश के नौजवानों और किसानों-बागवानों के हित का बजट है। इन सबके अतिरिक्त सबसे बड़ी मुश्किल यह आ रही थी कि हमारे जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुने हुए सदस्यों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो बजट मिलता था वह 14वें वित्तायोग ने बंद कर दिया था। जिस कारण से वह अपने क्षेत्र में विकास के लिए कोई राशि खर्च नहीं कर पाते थे। उनकी उसके लिए मांग थी और मुख्य मंत्री जी ने केंद्र सरकार से इस मांग को कई बार उठाया लेकिन केंद्र सरकार ने इसको रिजैक्ट किया।

श्री वर्मा द्वारा जारी

15/03/2017/1220/टी0सी0वी0/डी0सी0/1
श्री कुलदीप कुमार ..... जारी।

राज्य वित्तायोग ने भी इसके बारे में सरकार से सिफारिश की थी कि जो जिला परिषद् और पंचायत समिति के सदस्य हैं, उनको अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ-न-कुछ धन

उपलब्ध करवाना चाहिए। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने हमारी सिफारिश को मंजूर किया और इसके साथ-साथ जिला परिषद् और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए फण्ड का प्रावधान भी किया, ताकि वे अपने क्षेत्र का विकास करवा सकें। इसके लिए 42 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इससे पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य (जिला परिषद/पंचायत समिति) जो अपने आप को तिरस्कृत हुआ समझते थे, आज उनका मान-सम्मान बढ़ा है। वे भी आज माननीय मुख्य मंत्री जी और इस सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। "Mukhya Mantri Rural Road Repair Scheme" के अन्तर्गत जो हमारी गांव की सड़कें हैं, उनकी रिपेयर के लिए 20 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बी0पी0एल0 और आई0आर0डी0पी0 परिवारों को मकान दिए जाते थे, जिनके लिए विभिन्न निर्माण योजना के अंतर्गत 115 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसके लिए जल आपूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के 450 करोड़ रूपये के विद्युत भार को प्रदेश सरकार वहन करेगी। घरेलू उपभोक्ताओं को जो विद्युत उपदान दिया जाता है, यह स्कीम भी माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह द्वारा शुरू की गई थी, आज उस उपदान के लिए भी 450 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट के अन्तर्गत किया गया है।

माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए

इस बजट में खासकर नौजवानों का ख्याल रखा गया है। ये जो बजट हैं, ये नौजवानों के लिए समर्पित बजट हैं। जो नौजवान नशे की तरफ जाते थे और बेरोजगार घूमते थे, उनके लिए सरकार ने नौकरियों का पिटरा खोला है। इस बजट में लगभग 19000 नौकरियां प्रस्तावित की गई हैं। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते के रूप में +2 और इससे ज्यादा जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की हैं, उन बेरोज़गारों को 1000 रूपया प्रतिमाह दिया जाएगा। जो विकलांग/दिव्यांग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं

ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें, उनके लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार देने के लिए भी यह सरकार चिन्तित हैं।

श्रीमती एन0एस0 .... द्वारा जारी।

15/03/2017/1225/ एन0एस0/डी0सी0 /1

श्री कुलदीप कुमार ----- जारी

इस बजट में बेरोज़गार युवकों के लिए 1000 नई बसों के परमिट देने का भी प्रावधान किया गया है ताकि बेरोज़गार नौजवान रोजगार हासिल कर सकें। जिन नौजवानों के पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं हैं उनको 1000 रूपया प्रति माह बेरोज़गारी भत्ता भी दिया जाएगा। इसके साथ-साथ युवा क्लबों के लिए जो अनुदान राशि थी उसको 25,000 से बढ़ा करके 35,000 कर दिया गया है। यह खेलों और नवयुवक के क्लबों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। इसके अतिरिक्त 'मुख्य मंत्री खेल विकास योजना' हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छा कदम है। आजकल हम जिस भी गांव या कस्बे में जाते हैं वहां के नौजवान मांग करते हैं कि यहां पर कोई जिम खुले, ग्राउंड बनाया जाए या फिर हमें क्रिकेट की किट दी जाए या फिर फुटबाल खेलने का सामान दिया जाए। 'मुख्य मंत्री खेल विकास योजना' के अन्तर्गत हर विधान सभा क्षेत्र में एक खेल के मैदान को बनाने की घोषणा की गई है। आप लोग इसके लिए भी मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद नहीं करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य please wind up.

श्री कुलदीप कुमार : इसके साथ-साथ इस बजट में व्यापारियों के भी हित की बात की गई है। व्यापारी लोग इनके (भाजपा) हितैषी होते हैं। यदि कोई दो करोड़ का कारोबार करने वाला डीलर हैं उसको स्वतः कर निर्धारण की योजना इस बजट में दी गई है। इसके साथ-साथ 40 लाख तक वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को एकमुश्त कर योजना

के दायरे के अन्तर्गत लाने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जो सोशल सैक्टर हैं इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 650 रूपये से बढ़ाकर के 700 रूपये किया गया है। मंदबुद्धि बच्चों का कोई सहारा नहीं होता है वे भी माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करेंगे क्योंकि उनके लिए भी बिना किसी आय सीमा के पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 80 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए पेंशन 1200 से बढ़ा करके 1250 रूपये की गई है। (व्यवधान)

15/03/2017/1225/ एन0एस0/डी0सी0 /2

अध्यक्ष : प्लीज़ आप वाईंड अप कीजिए।

श्री कुलदीप कुमार : इस बजट में विशेष तौर पर विकलांगों के लिए जो रिजर्वेशन 3 प्रतिशत थी और यह बहुत सालों से इतनी ही थी उसको बढ़ा करके 4 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दिहाड़ादार मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ा करके 210 रूपये कर दी गई है। जल गार्डों का मानदेय 1500 रूपये से बढ़ा करके 1700 रूपये किया गया है। पंचायत चौकीदारों का सहायता अनुदान 2050 रूपये से बढ़ा करके 2350 रूपये किया गया है। इसके अलावा पंचायत सिलाई अध्यापकों को कोई नहीं पूछता था उनका सहायता अनुदान 2300 रूपये से बढ़ा करके 2600 रूपये किया गया है। आंगनबाड़ी कर्मी और सहायक हर बार अपने मानदेय बढ़ोतरी की मांग करते रहते थे उनके भी राज्य मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय 450 रूपये से बढ़ा करके 1000 रूपये किया गया है। आंगनबाड़ी सहायकों का राज्य मानदेय 300 से बढ़ा करके 600 रूपये प्रति माह किया गया है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

15/03/2017/1230/RKS/AG/1

श्री कुलदीप कुमार...जारी

इसके साथ-साथ आप सब लोगों को जो पहले डिस्क्रेशनरी ग्रांट 4 लाख रुपये की थी उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। उसके लिए भी आप धन्यवाद नहीं करते हैं। आप थैंकलैस हो गए हैं। आपको इतने थैंकलैस नहीं होना चाहिए। जो डिस्क्रेशनरी ग्रांट 5 लाख रुपये मिल रही है उसके लिए आप माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद कीजिए। हरेक विधायक को इसकी समस्या होती थी। जब विधायक बतौर मुख्य अतिथि स्कूलों के फंक्शन के लिए जाते थे तो वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रोत्साहन हेतु विधायकों के पास कोई ग्रांट नहीं होती थी। इस बजट में विधायकों को 5 लाख रुपये की डिस्क्रेशनरी ग्रांट दी गई है।

Speaker: Hon'ble Member, please wind-up.

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं वाईंड-अप कर रहा हूं। मैं सरकार का धन्यवाद ही कर रहा हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के चौकी-मीनार में माननीय मुख्य मंत्री जी ने डिग्री कॉलेज दिया। अम्ब में सिविल हॉस्पिटल दिया। दुसाड़ा में कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर दिया। मेरे चुनाव क्षेत्र में 2-3 आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी दी गई है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। कई स्कूल दिए गए, खासकर जो कटोड़ प्राइवेट स्कूल चल रहा था, वहां पर सरकारी स्कूल दे दिया गया है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं वाईंड अप कर रहा हूं।

Speaker: You are not winding-up.

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, चिन्तपुरनी जो एक बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है, वहां पर लगभग 55 करोड़ रुपये का मल्टी पर्पज़ पार्किंग व वहीं पर लगभग 15 करोड़ रुपये का सीवरेज का काम भी चला हुआ है, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं।

15/03/2017/1230/RKS/AG/2

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि जो हमारी सड़कों/पुलों की डी.पी.आर्ज. नाबार्ड के अंतर्गत भेजी गई है वह जल्द सैंक्शन हो ताकि उस क्षेत्र को जल्द-से-जल्द सड़कों और पुलों से जोड़ा जा सके। क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र ऊना जिला का सबसे पहाड़ी क्षेत्र है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह बजट बहुत सराहनीय बजट है। हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। यह बजट हर वर्ग का हितैषी है। इस बजट में किसान, मजदूर और खासकर नौजवानों व व्यापारियों का विशेष ध्यान रखा गया है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

15/03/2017/1230/RKS/AG/3

श्री सतपाल सिंह सत्ती: अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता, मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने 10 मार्च को जो बजट यहां पर पेश किया है, बजट का जो अनुमान प्रस्तुत किया है, उस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जो बजट आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उस पर बड़े विस्तार से विपक्ष के नेता श्रद्धेय धूमल जी ने काफी विस्तार से अपने विचार रखे हैं और आंकड़ों के साथ तुलना भी की है। पिछले चार वर्षों में जितने भी बजट पेश किए गए उनमें आंकड़ों के हिसाब से प्रोफैसर साहब ने यह दर्शाया है कि हर वर्ष जो आदरणीय वीरभद्र सिंह जी के द्वारा बजट पेश किया जाता है, उस बजट में जो घोषणाएं होती हैं, वह अगले वर्ष के बजट में कहीं दिखाई नहीं देती है। ज्यादातर 80 प्रतिशत घोषणाएं ऐसी होती हैं जिनका काम भी शुरू नहीं होता है और अगली बार किसी-न-किसी नये नाम से कोई नई योजना लेकर आते हैं।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

15.03.2017/1235/SLS-AG-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती.... जारी

बजट का प्रावधान न होने के बावजूद भी उन योजनाओं को यहां पर पढ़ा जाता है और उन पर बड़ी पीठ थपथपाई जाती है। बीच-बीच में कुछ कवियों की पंक्तियां बोलकर उनको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन जब अगला बजट आता है तो वह योजनाएं उस बजट बुक से गायब होती हैं और अगली बार कई नई योजनाएं आ जाती हैं। जैसे नई पिक्चर्ज़ आती हैं, उसी तरह से आप नया फट्टा लगा कर, स्कीमों का नया नाम रखकर नई योजनाएं लेकर आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा विषय ध्यान में आया है वह है कि मुख्य मंत्री जी ने वाही-वाही लूटने के लिए अनेक क्षेत्रों में तरह-तरह की संस्थाएं खोलने की घोषणा की है। जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र है। उसमें दर्शाया गया है कि पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में लगभग 42 कॉलेज खोले गए हैं और अब 119 कॉलेज सरकारी हो गए हैं। इसी तरह से अगर हम प्रशासन की दृष्टि से देखें तो प्रशासन को मज़बूत करने के स्थान पर नए-नए कार्यालय खोलने पर ज़ोर दिया जा रहा है। उन कार्यालयों में चाहे स्वीपर से लेकर एस.डी.एम. हो या न हो, उनमें तहसीलदार हो या न हो, नायब तहसीलदार पहुंचे या न पहुंचे। इस तरह के 14 नए एस.डी.एम. ऑफिस इन्होंने खोले, 16 नए तहसीलदार ऑफिस खोले और 31 नई उप-तहसीलें बनाईं। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हैल्थ की दृष्टि से देखते हैं, हम लोग दूर-दराज़ के क्षेत्रों में रहते हैं और जो संस्थान वहां पहले से खुले हैं उनको अगर हम देखें; उस बारे में यहां पर चर्चा भी हुई है और एक प्रश्न का उत्तर भी आया है कि हैल्थ डिपार्टमैंट में ही लगभग 9500 पोस्टें खाली पड़ी हैं। कुल खाली पद 10184 हैं लेकिन फिर भी 21 नए सिविल हॉस्पिटल खोले गए, 34 कम्युनिटी हैल्थ सैंटर्ज़ खोले गए, 96 प्राइमरी हैल्थ सैंटर्ज़ खोले गए और 29 सब-हैल्थ सैंटर्ज़ खोले गए हैं। इसी

तरह ई.एस.आई. के माध्यम से 5 नए हॉस्पिटल खोलने की घोषणा हुई है। जब हम बजट बुक को उठाकर देखते हैं तो जो यह घोषणाएं हुई हैं, मुझे लगता है कि आने वाले अगले 10-15 साल तक भी कोई भी मुख्य मंत्री अगर कोई नई संस्था न खोलें तो भी उनका

15.03.2017/1235/SLS-AG-2

बजट इसी में लग जाएगा, तब भी ये संस्थान पूरे नहीं होंगे।

कांग्रेस की रैलियों में इस तरह की घोषणाएं होती हैं जबकि प्रशासन के साथ या वित्त विभाग के लोगों के साथ या जो इन क्षेत्रों के एक्सपर्ट हैं उनके साथ चर्चा करके घोषणाएं होनी चाहिए। मैंने देखा कि कई जगह पर ज़रूरत होने पर भी संस्थान खोलने की घोषणाएं नहीं होती हैं। ठीक है कि किसी क्षेत्र से मंत्री बनते हैं। लेकिन मंत्री केवल अपने चुनाव क्षेत्र का ही नहीं होता बल्कि वह पूरे प्रदेश का होता है। कई बहुत अच्छे विधायक होंगे जो मेहनत करते होंगे या भागदौड़ करते होंगे, लेकिन सभी 68 विधायक 68 निर्वाचन क्षेत्रों से ही जीत कर आए हैं। अगर वहां का विधायक वहां की समस्याएं नहीं उठा सकता तो मुख्य मंत्री जी से मेरा यह कहना है कि विभाग के लोगों को स्वयं इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हैल्थ सैंटर कहां खुलना चाहिए, जनता की डिमांड कहां है और जनता को ऐसे संस्थान कहां पर दूर पड़ते हैं। कई-कई स्थानों पर हम लोग देखते हैं कि हर किलोमीटर के बाद प्लस टू स्कूल खुल गया और एक ही गांव में आयुर्वेदा की डिसपैंसरी भी है और एलोपैथी की डिसपैंसरी भी है। वह गांव सड़क के किनारे है। वहां थिक पापुलेशन है और वहां पर 4 प्राइवेट डॉक्टर भी प्रैक्टिस करते हैं। इसके विपरीत पहाड़ी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि 15 किलोमीटर तक न तो कोई प्राइमरी हैल्थ सैंटर है; 20 किलोमीटर तक न तो कोई हैल्थ सब-सैंटर है और न वहां कोई प्राइवेट डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। इस तरह वहां के लोग रास्ते में ही बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। जो हिमाचल प्रदेश की सरकार में चलती का नाम गाड़ी वाली बात चली है उसके कारण एक ऐसी डवलपमैंट हो रही है जैसे कि किसी व्यक्ति की शरीर की टांगें मोटी हो जाए, हाथ पतले हो जाएं, शरीर सूख जाए और पेट बढ़ जाए। फिर उसको आप कहें कि यह व्यक्ति बहुत हैल्दी है क्योंकि इसके कुछ पक्ष तो बड़े मज़बूत हैं। वही व्यक्ति मज़बूत होता है जो पैरों से लेकर दिमाग तक हैल्दी होता है। फिर वही सरकार ठीक होती है जिसमें या तो मंत्री अपना दिमाग लगाएं या फिर

एक्सपर्ट लोगों को बिठाकर उनसे बातचीत करे। देखने में आता है कि इस सरकार में संस्थान तो खोले गए लेकिन उन संस्थानों की मज़बूती के लिए कोई काम नहीं किया गया। आज भी प्राइमरी हैल्थ सैंटर्ज़ और सी.एच.सीज. का काम आए हुए मरीज़ को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजने का है।

जारी ...श्री गर्ग जी द्वारा

15/03/2017/1240/RG/AS/1
श्री सतपाल सिंह सत्ती---जारी

अध्यक्ष महोदय, ऐसा भी देखने में आया है कि ऐसे-ऐसे ऐक्सपर्टस डॉक्टर्ज हैं जिनको बेचारों को जिला मुख्यालयों में होना चाहिए, लेकिन उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सी.एच.सीज़. में घुमा दिया जाता है और बाद में परेशान होकर वे नौकरी छोड़ देते हैं और बाद में उनका अपना क्लीनिक बढ़िया चलता है। ऐसे ही ऊना में पिछले 3-4 सालों में अनेकों डॉक्टर्ज ने नौकरियां छोड़ीं। शायद तनख्वाह से ज्यादा उनकी पैसे कमाने की इच्छा भी नहीं थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग पैसे कमाने की दृष्टि से बहुत भाग-दौड़ करने में विश्वास नहीं करते और सभी में सेवा-भावना है, लेकिन उनको इतना तंग किया गया कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी। आज ऊना मुख्यालय में एक डॉक्टर ऐसे हैं जो पूरा हिप चेन्ज कर देते हैं। वे सरकारी क्षेत्र में थे, लेकिन उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सी.एच.सी. में इस प्रकार से घुमाया गया कि उन्होंने नौकरी से तौबा कर ली और अपना क्लीनिक खोल लिया। आज वे बढ़िया 5-10 लाख रुपये कमा रहे हैं। इसी तरह से गायनॉलॉजिस्ट्ज हैं जिन्होंने अपने अस्पताल खोल लिए हैं और इसके विपरीत सरकारी क्षेत्र में हमें डॉक्टर्ज नहीं मिल रहे क्योंकि हम डॉक्टर्ज के साथ ठीक ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बी.जे.पी. से, कांग्रेस से, कौन कहां से है, कौन किस पार्टी का है, यह देखते हैं। हमें तो मैडिकल कॉलेज चलाने के लिए भी डॉक्टर्ज नहीं मिल रहे और हम जिला अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर्ज नहीं रख सकते। अब एक एम.डी. का पी.एच.सी. में क्या काम है? वहां इन्स्ट्रूमेंट्स ही नहीं हैं, इनफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वह मरीज को सिर्फ रैफर ही करेगा और बेचारा वह क्यों नौकरी करेगा? इसलिए जो संस्थान हमारे प्रदेश में खोले जा रहे हैं जब हम उनकी स्ट्रेन्थनिंग नहीं करते तब तक प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बजट बुक देख रहा था, जो पुराने संस्थान खुले हैं, ठीक हैं। मेरा तो यह मानना है कि नया संस्थान तब तक नहीं खुलना चाहिए जब तक हम वहां स्वीपर से लेकर उसके हैड तक की नियुक्ति न कर दें। लेकिन आज क्या हो रहा है कि केन्द्र सरकार से पैसा आ रहा है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की दो-अढ़ाई करोड़ रुपये की बिल्डिंग्ज बन रही हैं, हम लोग उसमें उद्घाटन करते हैं और दूसरे दिन देखते हैं कि उसके अंदर ताला लटका हुआ है या फार्मासिस्ट अंदर बैठा हुआ है। न तो वहां डॉक्टर है, न ही वहां स्वीपर या कोई पानी पिलाने वाला है। यह आप लोग व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं।

15/03/2017/1240/RG/AS/2

अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही स्कूल-कॉलेज का मामला है। कॉलेज खुल गए, लेकिन उनमें हमारे जिला मुख्यालय के टीचर्स बदल दिए, ऊना में पांच अंग्रेजी के शिक्षक थे, तीन बदल दिए, दो रह गए और वहां बच्चों की 4500 स्ट्रेन्थ है, तो कहां से लोग पढ़ाएंगे? कोई इधर और कोई उधर भेज दिया जाता है। शिक्षक भी परेशान, पिछला कॉलेज शिक्षा संस्थानों में जुड़ रहा है और अगला कॉलेज ठीक से बस नहीं पा रहा है उसमें ऐडमीशन्ज ही नहीं आ रही हैं। इसलिए जो संस्थान खुल रहे हैं इस बारे में मेरा यह मानना है कि हम जो संस्थान खोलें, सोचे-समझकर खोलें न कि रैली के माध्यम से जब हम भाषण देते हैं, उस समय किसी ने बोल दिया और हमने भी दो मिनट के लिए तालियां बजा दीं, तो उसके कारण हिमाचल का सारा सिस्टम खराब हो रहा है और हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि उन खर्चों से आने वाले समय में अगर जितने कर्मचारियों की यहां लिस्ट आई है अगर वे सारे कर्मचारी रखने हों, तो मुझे लगता है कि तनख्वाह देने के सिवाय एक रुपया भी विकास के लिए आपके पास नहीं बचेगा। कॉलेज खोलें, स्कूल खोलें, डिसपेन्सरी खोलें, स्वास्थ्य केन्द्र खोलें हम सब कुछ करें, लेकिन कम-से-कम अपने संसाधनों के मुताबिक करें और जहां जरूरत है उसके हिसाब से करें।

अध्यक्ष महोदय, आज ये लोग स्वयं कह रहे हैं कि मैडिकल कॉलेज के लिए डॉक्टर्ज नहीं आ रहे हैं। लेकिन बिल्डिंग्ज कितनी बड़ी बन गई हैं, 900 करोड़ रुपये की मण्डी में बन गई, ऐसे ही हमें जानकारी मिली है कि टांडा मैडिकल कॉलेज में 900/- करोड़ रुपये से एक बिल्डिंग बनी, उसका उद्घाटन हुआ है और उसमें इन्होंने मशीनरी भी पहुंचा दी हैं,

लेकिन उसके लिए डॉक्टर्ज नहीं मिल रहे हैं, तो अब उस मशीनरी को कौन चलाएगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ऐक्स-रे की मशीन आ जाती है, लेकिन ऐक्स-रे करने वाला आदमी नहीं है। जिला मुख्यालयों में अनेकों ऐसे सामान पड़े हैं जो कमरों में बन्द पड़े हैं और उनको चलाने वाला कोई नहीं है। इस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर खरीदकर हम सरकार का पैसा तो बेकार कर ही रहे हैं उसके साथ-साथ जो खाने-पीने वाले हैं, उनकी भी मौज लगी हैं, लेकिन छात्रों को उनसे कुछ नहीं मिलने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों बातें यहां बोली गई हैं, आदरणीय धूमल जी ने भी बोला है। 'रूसा' के कारण आज पूरे प्रदेश के छात्र परेशान हैं और लोगों की शिक्षा तबाह हो गई है। लेकिन हम लोग उस पर बोलना हीं नहीं चाहते, उस पर कुछ करना ही नहीं चाहते, क्या करना है? इसलिए शिक्षा के

15/03/2017/1240/RG/AS/3

बारे में जो ऐक्सपट्र्स हैं उनको बैठाकर निर्णय लें, लेकिन उस बारे में हम लोग कुछ करना नहीं चाहते। आज इस विधान सभा के अंदर आए हुए हमें 15 साल हो गए, 15 सालों में यदि समय गिना जाए, तो मुझे लगता है कि अनेकों घण्टों का समय बन्दरों के ऊपर, आवारा पशुओं के ऊपर चर्चा करने में लगा होगा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है कि किसी ने इस समस्या का कोई समाधान किया हो। आज आपको अनेक खेत ऐसे दिखाई दे जाएंगे जहां सींचित भूमि है लेकिन लोगों ने उसमें सिंचाई करना छोड़ दिया है, बीजना छोड़ दिया क्योंकि वहां जंगली जानवर, आवारा पशु और बंदर लोगों की फसल तबाह कर रहे हैं। हम लोग यहां बैठकर जो चाहे बोलते रहें, हमारे पास कोई योजना नहीं है।

एम.एस. द्वारा जारी

15/03/2017/1245/MS/AS/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी------

माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि हरेक पंचायत में गौशाला होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने तो यह संकेत किया कि गौशाला खोलना कितनी मजबूरी और जरूरत हो गई है। यह बात ठीक है कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में गौशालाएं नहीं बन सकती हैं लेकिन हम कोई कलस्टर ही बना लेते। जैसे पिछली बार भी यहां बोला गया कि 10-15 पंचायतें मिलकर एक गौशाला खोल दे। वह सरकारी क्षेत्र में चलनी है या हमारे धार्मिक मंदिरों जैसे बाबा बालकनाथ, ज्वाला जी, चिन्तपूर्णी और नैनादेवी इत्यादि अनेकों मंदिर हैं उनके साथ मिलकर चला लें ताकि जो ये 32000 गायें सड़कों पर घूम रही हैं उनको गौशालाओं में रखा जा सके। हिमाचल प्रदेश में 500-600 करोड़ रुपये की फसल की आज बिजाई ही नहीं हो रही है क्योंकि अगर किसान बिजाई करते हैं तो फसल को जानवर उजाड़ देते हैं। अगर इसको बचाने के लिए 100-150 करोड़ रुपया हम खर्च कर देते तो मुझे लगता है कि जो दुर्घटनाएं भी आज इनकी वजह से हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, वे न मरते। आज दुर्घटना में मरने वाले एक-एक आदमी को हम 4 लाख रुपया देते हैं और उस व्यक्ति के न रहने से उसका परिवार भी बेघर हो जाता है लेकिन हम इन गायों के ऊपर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। यहां पर सिवाय भाषण के उस दिशा में कुछ नहीं हुआ और उसके ऊपर न ही कोई चर्चा है और न ही कोई प्लानिंग है। चर्चा होती है लेकिन उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं है। किसानों से जाकर पूछो कि वे कितने परेशान हैं?

हमने बाड़बन्दी की घोषणा की और पिछली बार आपने स्वयं बताया कि 2 प्रतिशत पैसा लोगों ने लिया। तो इसका मतलब हमारी योजना ही गलत है। लोगों की डिमाण्ड है कि ऊंची जालियां दें क्योंकि बन्दर/लंगूर इत्यादि जो जानवर हैं उनकी तो व्यक्ति स्वयं रखवाली करके उन्हें खेत में जाने से रोक सकता है लेकिन जो नील गाय, सूअर, सेल, खरगोश और हिरण हैं इनको उन जाली से रोका जा सकता है। जो कृषि के एक्सपट्र्स हैं, वे वास्तव में एक्सपट्र्स नहीं हैं क्योंकि वे स्वयं रेहड़ियों पर खड़े होकर बैंगन खरीद रहे होते हैं। इनको छोड़ दो, ये तनख्वाह लेने वाले लोग हैं। मैंने ऊना में देखा है। कृषि विज्ञान केन्द्र की अपनी

15/03/2017/1245/MS/AS/2

517 कनाल जमीन है और वे गांवों में जाकर लोगों को बड़े-बडे भाषण देते हैं कि आप गोभी, बैंगन और आलू उगाओ जबकि स्वयं शाम को डॉक्टर साहब रेहड़ी वाले के पास खड़े हो

जाते हैं कि इतने रुपये के बैंगन दे दो और इतने रुपये के आलू दे दो। मैं कहता हूं कि 517 कनाल जमीन अगर किसानों को दी होती तो उस गांव से सब्जी के ट्रकों के ट्रक भरकर जाते। इसलिए एक्सपर्ट वे हैं जो खेत के अंदर मिट्टी में लोगों के साथ पड़े हैं। उनको बुलाओ कि आपकी जरूरत क्या है। यहां तो ऐसी योजना बनती है कि उसमें से क्या लेनदेन हो सकता है। यह एक्सपर्ट वाला मामला कुछ नहीं है। हमने सोच लिया कि जो लोग कमरों और ऑफिसिज के अंदर रहते हैं वे एक्सपर्ट्स हैं जबकि वे एक्सपर्ट नहीं हैं। जो फील्ड के अंदर बेचारे मेहनत कर रहे हैं वे एक्सपर्ट हैं। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा है कि हिमाचल प्रदेश और पूरे हिन्दुस्तान में किसानों को बचाइए। आज सड़कें गायों, जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से भरी पड़ी हैं। आजकल जंगलों में जाकर कोई जानवरों को नहीं मारता है। इसलिए बजट में उसके बारे में कोई बृहत योजना बनें जिसको अगली सरकार भी चला सके और आप लोग भी चलाए ताकि अल्टीमेटली जाकर 5-7 सालों के बाद हम किसानों को कह सकें कि भाई साहब यह मेन डिमाण्ड थी जोकि हमने आपकी पूरी कर दी है।

इसी तरह से सिंचाई की योजनाएं हैं। आदरणीय मोदी जी ने 50 हजार करोड़ रुपये की "प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना" चलाई। आपको उसके लिए कन्सल्टैंसी लेने के लिए ही एक साल का समय लग गया। आप उसके लिए कन्सल्टैंट ही फाइनल नहीं कर सके। आज किसानों को सिंचाई के लिए पानी की यदि जरूरत है तो माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठी हैं ये केन्द्र से जितना पैसा चाहिए, ला सकती हैं, वहां जाये। जैसा धूमल जी के समय में होता था कि मंत्री स्वयं फाइलें लेकर जाते थे। मुझे आज भी लगता है कि यदि आप में से कोई मेहनत करता होगा तो आपको वर्तमान और पुरानी सरकार में अंतर जरूर नज़र आता होगा। मैं उसमें पार्टी में नहीं जाना चाहता। मंत्री जी भी जानते हैं क्योंकि उनको प्रधानमंत्री जी की ओर से दिशा-निर्देश हैं कि काम नहीं रूकना चाहिए। अगर हमारी सरकार होती तो मैं यह मानकर चलता हूं कि यदि हम लोग औद्योगिक विकास के लिए पैसा मांगते तो जैसे मुकेश जी के विभाग को

15/03/2017/1245/MS/AS/3

ऊना में 120 करोड़ रुपये और कंदरौड़ी को 120 करोड़ रुपये मिले हैं, हमें कांग्रेस के शासनकाल में 250 करोड़ रुपया कभी भी नहीं मिलता। सवाल ही पैदा नहीं होता। यह भारतीय जनता पार्टी का शासन है कि मोदी जी ने यह बोलकर रखा है और वे बोलते भी हैं

कि जब पूरा देश विकसित होगा और हरेक प्रदेश विकसित होगा तब देश विकसित होगा। जी0डी0पी0 ओवरऑल सबका बढ़ेगा, सब अमीर होंगे तब देश विकसित होगा। इसलिए जितने पैसे ही जरूरत है वहां जाकर ले आएं।

हमारी केन्द्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि हरेक जिला मुख्यालय में डायलेसिज सेंटर और ट्रॉमा सेंटर होगा। यहां पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी बैठे हैं। कितने डायलेसिज सेंटर/ट्रॉमा सेंटर के लिए केन्द्र को प्रोजैक्ट गए हैं? हमने बनाकर भेजे थे। हमारे ऊना में बहुत दुर्घटनाएं होती हैं बल्कि ऊना में जितनी दुर्घटनाएं होती हैं उसके हिसाब से वहां पर एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। वहां जब कोई दुर्घटना घटित होती है तो वहां से सब लोग जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और चण्डीगड़ उपचार के लिए जाते हैं। आई0जी0एम0सी0 तक तो हमारे लोग आते ही नहीं हैं क्योंकि यहां आने के लिए सात घण्टे लगते हैं इसलिए यहां कौन आएगा? इस तरह हमें बॉर्डर एरिया में छोड़ दिया है और अंदर ही एम्ज, अंदर ही तीनों मेडिकल कॉलेज और अंदर ही ई0एस0आई0 है। इसलिए संस्थान वहां खोलने चाहिए जहां रेल कनैक्टिविटी हो और लोग आएं। जिस डॉक्टर ने वहां पढ़ाने आना है उसने साथ में परिवार भी लाना है और वहां अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। मैं यह नहीं कहता कि इंटीरियर में काम नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कम-से-कम एक तरह का सारा सिस्टम देखकर डवलपमैंट तो करे।

आज "स्मार्ट सिटी" का 186 करोड़ रुपया आया है क्या किसी ने केन्द्र में जाकर बोला कि इसका आकर शिलान्यास करो ताकि हम काम आगे बढ़ाएं। आपको इस पर भी 400-500 करोड़ रुपया आ जाता। हमें जो पैसा आ जाता है, वह वैसे ही पड़ा रहता है और उसको ऐडवरटाइजमैंट पर लगा देते हैं लेकिन बजट या अन्य माध्यमों से उसकी कोई योजना नहीं दिखाई देती है

जारी जे0एस0 द्वारा-----

15.03.2017/1250/जेके/डी0सी0/1

श्री सतपाल सिंह सत्तीः-------**जारी**-----

न मुख्य मंत्री जी के मुखारविन्द से ही सुनाई देता है कि इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? 2200 करोड़ रूपया लगना है, अगर हर साल 200 करोड़ रूपया आएगा तो 11 साल लगेंगे स्मॉर्ट सिटी बनने में, अगर यही स्पीड रही। अगर आप मेहनत करेंगें, वैंकैया जी को बुलाओ, प्रधान मंत्री जी को बुलाओ। उनसे उद्घाटन व शिलान्यास करवाओ। वे उस दिन बोलेंगे। आपका एम्ज का शिलान्यास नहीं हो रहा है। कौल सिंह जी बार-बार अखबारों में बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि यहां पर वे जगत प्रकाश नड्डा जी का विरोध करते हैं और दिल्ली में जा करके हर 15 दिन के बाद गुलाब के फूलों वाला गुलदस्ता इनके हाथ में होता है, उनको देते हैं और फोटो खिंचाते हैं और फिर आ जाते हैं। आपने उनको कोई ऐसी लैंड का लैटर भेजा है? टैक्निकली बता सकते हैं कि उस लैटर की लैंग्वेज़ क्या होती है? जो ऑल सोर्सिज से उस डिपार्टमैंट को देनी होती है, फोरैस्ट से भी क्लीयरैंस है, गवर्नमैंट से भी क्लीयरैंस है और उसके बाद सेन्टर गवर्नमैंट नोटिफिकेशन करेगी। आप लोग कह रहे हैं कि सेन्टर गवर्नमैंट ने तो डेढ़ साल के बाद नोटिफिकेशन ही नहीं की है। आप लोग सारी फोरमैलिटी पूरी करो, हम आप लोगों को दावे के साथ कहते हैं अप्रैल महीने में मोदी जी को लाएंगे और शिलान्यास करवाएंगे। आप इसको क्लीयर तो करो। हम यहां पर मोदी जी को लेकर आएंगे, वो आएंगे तो उनसे चार चीजें और लेंगे। रेलवे के नैटवर्क के लिए पैसा लेंगे। लेकिन आप लोग मोदी जी से डरते हैं। वे तो आएंगे क्योंकि इस साल दो राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश के ही चुनाव हैं। उन्होंने तो आना ही है। वे सोने वाले प्रधानमंत्री तो नहीं है। वे तो अपना अभियान खत्म करके दूसरे दिन सोमनाथ पहुंच गए कि अच्छा गुजरात की बारी है और अभी किसी दिन आपके मन्दिर में भी माथा टेकते हुए मिल जाएंगे। वे आ जाएंगे और वे सोएंगें नहीं और न आपको सोने देंगे। आप रोकेंगें तो भी वे नहीं रूकेंगे। वे आएंगे ही आएंगे। उस कारण से इन 6-7 महीनों में कुछ भला करवा लो ताकि आप लोगों का भी किसी का फट्टा साथ में लग सके। नहीं तो उसके बाद तो यह सारा होना ही है।

मुझे लग रहा है कि आप झूठे आश्वासन दे रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन, यहां पर वित्त सचिव भी बैठे हैं और बाकी सचिव भी बैठे हैं और मंत्री महोदय बैठे हैं। किसने मिस गाईड किया होगा? ये बड़ा गुनाह मान कर मैं चलता हूं। आप लोग 28 अक्तूबर को हिमाचल प्रदेश को शौचमुक्त हिमाचल घोषणा कर देते हैं। मैं आप लोगों को 10 जगह ले जा सकता हूं जहां लोगों के घरों में टॉयलैट नहीं है। मेरा ही पिछली बार प्रश्न था कि 48 हजार लोगों ने आज भी शौचालयों के लिए पैसे देने के लिए निवेदन किया है और आपने यह कहा कि इस साल हम 10 हजार लोगों को पैसा दे देंगे। जिनके घरों में टॉयलैट नहीं है तो कैसे हिमाचल शौच मुक्त हो गया? आपने केन्द्रीय मंत्री को भी बुलाया। हमने तो बाद में अखबार में पढ़ा। हमने बाद में देखा। आपने क्लीयर भी करवा दिया और कार्यक्रम भी करवा दिया। कम से कम इतना बड़ा फ्रॉड तो न करो। इतना तो आप लोग मत करो। आप लोग जानते हैं कि हम लोग गांवों में घुमने वाले हैं। दोनों तरफ के पार्टी के लीडर गांवों-गांवों में जाते हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि इस तरह की झूठी वाहवाही लूटने से अच्छा है कि अगर हम ग्राऊंड वर्क करते हैं तो मुझे लगता है कि वह ठीक है। दूसरे, मेरा एक बहुत बड़ा ऑब्जैक्शन है। प्रदेश एक है और प्रदेश के सभी लोग हमारे हैं। वे चाहे कांग्रेस परिवारों के बच्चे पढ़े हों, चाहे बी0जे0पी0 के हों और चाहे किसी के भी हों, उन बच्चों के कैरियर के साथ बहुत बड़ा धक्का हो रहा है। हम सभी लोग भी पढ़े-लिखे लोग हैं। किस तरह से यह हो जाता है कि जिस डिपार्टमैंट के मंत्री की पोस्टें निकलती है उसी के डिपार्टमैंट में सारे इंटैलिजैंट लोग पैदा हो जाते हैं? यह 15 साल में आज तक मुझे समझ नहीं आया। आज तक यह बात समझ में नहीं आई। जब सबोर्डिनेट बोर्ड है, पब्लिक सर्विस कमिशन है और मंत्री भी इस गलतफहमी में न रहें, कई बार कांगड़ी में बोलते हैं और ध्वाला जी हमें सुनाते हैं। आपके 10-12 के जितने से कांग्रेस की सरकार नहीं बनेंगी और किसी की गवर्नमैंट मंत्रियों के कहने से नहीं बनती है। मंत्री तो अधिकतर हारते ही हैं। विधायक चाहे इधर के हों या उधर

के हों उन सबकी चिन्ता किया करो। दो-चार बालों को या अकेले बाल को परांदू नहीं लगता वहां पर भी 5,10 या 50 बाल चाहिए होते हैं तब

15.03.2017/1250/जेके/डी0सी0/3

परांदू फिट होता है। सरकार ज्यादा विधायकों से बनती है, एक-आध से नहीं बनती है। एच0आर0टी0सी0 वाला आता है तो 172 में से 72 लोग बाली जी चुन लेते हैं। वीरभद्र जी को चुप करवाने के लिए 39 उनके कंडक्टर भी लगा देते हैं। रोहड़ू में क्या ज्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं या हमीरपुर में, कौन से जिले में सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करिए।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः अध्यक्ष महोदय, अप्वाईंटमैंट्स का मामला जो हैं, मैं सर्विस कमिशन के ऊपर भी प्रश्न उठाता हूं। यहां पर हमारे महेन्द्र सिंह ठाकुर जी ने रिकॉर्ड दिया है। जिसके 98 नम्बर है, उसकी अप्वाईंटमैंट नहीं हो पाती है। इन्टरव्यू में 100-100 में से लोगों को 80-80 नम्बर भी दिए जा रहे हैं और जिनके लिखित परीक्षा में ज्यादा हैं क्योंकि पब्लिक सर्विस कमिशन में रिटन के जुड़ते नहीं है और स्क्रीनिंग टैस्ट होता है, उसके कारण जो बेचारा 80 परसेंट वाला बाहर हो रहा है जो 45 या 40 परसेंट वाला है वह इन हो रहा है। आप लोगों को क्यों गलतफहमी हो गई कि आपके सारे के सारे लोग नालायक ही हैं। आऊट सोर्सिंग में भी करेंगे, पी0टी0ए0 में भी करेंगे और एस0एम0सी0 में भी करेंगें। आप टैस्ट करवाओ, इन्टरव्यू करवाओ और जहां के लोग लगेंगे, वे लगे। हमें भी दुख होता है जब एक एरिया के लोग, डिपार्टमैंट के जो मंत्री हैं, वहां के लोग ज्यादा लगते हैं । इससे लोकतंत्र से लोगों का विश्वास भी उठता है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

15.03.2017/1255/SS-DC/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती क्रमागतः

लोगों का हम और आपके ऊपर भी विश्वास उठता है और कल को आप आयेंगे, हम आयेंगे तो हमें भी लोग परेशान करेंगे कि वह तो लग गया, उसको आज भी मेरे साथ रिटन टैस्ट में बिठा दो। सरेआम लोग बोलते हैं कि कांगड़ा बैंक में क्या-क्या हो रहा है। आप एजुकेशन बोर्ड को दे रहे हैं कि वे पेपर डालेंगे। आप लोगों की इस देश में संस्था है उसके माध्यम से पेपर डलवाओ। आपको विश्वास क्यों नहीं है कि आपके पढ़े-लिखे लोग हैं? वे भी पढ़-लिखकर आगे आ जायेंगे। आप लोगों ने बैकडोर एंटरी पर ही क्यों लक बांधा हुआ है। कमर कसी हुई है कि अपने लोग तो जैसे-तैसे पास करवाने ही हैं।

Speaker: Please wind up.

श्री सतपाल सिंह सत्तीः अध्यक्ष महोदय, यह मेरा आरोप है। विधान सभा के बारे में बोल नहीं सकते, आपने जो किया, आपको भी पूरे-का-पूरा पता है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कानून-व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि हम लोग यह करेंगे, तीन महिलाओं के थाने खोलेंगे। हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था की इतनी तबाही है, हम लोग यहां बैठे हैं जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं जो नूरपुर से लेकर पांवटा साहिब कालाअम्ब तक होंगे। महिलाओं के गले से चेन स्नैचिंग ऐसे होती है जैसे कभी हम दिल्ली का सुनते थे। घर में जा करके गेट खोल कर कारें, ट्रक उठाकर पंजाब में बेच रहे हैं। जब 30 गाड़ियों वाले लोग मंडी में पकड़े जाते हैं तो उसमें ऊपर से दबाव आता है। ए0एस0आई0 को परेशान किया जाता है। जो आदमी चोर है, जिसके घर में 30 गाड़ियां मिल गईं, No BJP, No Congress, क्या मतलब है उस चीज़ का? इसी के कारण गवर्नमैंट्स जाती हैं। जब गवर्नमैंट्स बदनाम होती हैं तो चंद लोगों के कारण बदनाम होती हैं। उसमें हम, आप लोग बेईमान नहीं होते हैं। किसी की कमी हो सकती है जब हम बाहरी

तत्वों को संरक्षण देते हैं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। उसके कारण सरकार बदल जाती है।

15.03.2017/1255/SS-DC/2

इसलिए बाहरी लोगों को, जो गन्दे लोग हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि किसी गवर्नमैंट को आश्रय देने की ज़रूरत है। वे आपके गले की चेन भी खींचेंगे। वे चली हुई महिला से नहीं पूछेंगे कि तूं बी0जे0पी0 की है या कांग्रेस की है। वे नहीं पूछेंगे, उनको तो गले में से सोना चाहिए। उनको गाड़ी या ट्रक चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में यह बार-बार बोला जाता है कि समान विकास हुआ है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में पिछले चार सालों में यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति बता दे कि मुख्य मंत्री जी ने कोई शिलान्यास या उद्घाटन किया है। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी के समय में पूरे प्रदेश में विकास होता था और 54 शिलान्यास और उद्घाटन मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुए थे।

Speaker: Please wind up.

श्री सतपाल सिंह सत्ती: सर, मैं पांच-सात मिनट में समाप्त कर दूंगा। अभी मेरे 23 मिनट हुए हैं। कुलदीप कुमार जी ने 27 मिनट बोला था।

अध्यक्ष: कोई 27 मिनट नहीं बोला था।

श्री सतपाल सिंह सत्ती: अध्यक्ष महोदय, ऊना विधान सभा क्षेत्र में हमने उस समय बस-स्टैंड का टैंडर किया। पी0पी0पी0 मोड पर बनाना शुरू किया लेकिन इन्होंने आ करके बंद कर दिया। कोई एक पैसा आज तक वहां नहीं लगा है। वहां पर हमने मिनी सचिवालय का साढ़े 9 करोड़ का एस्टीमेट बनाया, कोई एक पैसा नहीं लगा। बी0डी0ओ0 ऑफिस आज हमारा ऑफिसर क्लब में चल रहा है। हमने बी0डी0ओ0 ऑफिस तक तोड़ा था कि यहां पर नया मिनी सचिवालय बनायेंगे। लेकिन उसके बाद एक ईंट नहीं लगी है। न कुछ नया टूटा और न ही कुछ लगा। ऊना में जितने भी सीवरेज़ के काम संतोखगढ़ और मैहतपुर के हैं,

हमारे टाइम का पैसा रूका पड़ा है। अनेकों बार बोला लेकिन कोई उसमें काम करने को तैयार नहीं है। 50-50 लाख रुपया तो लगा दो जो धूमल जी के टाइम का वहां पर पड़ा हुआ है या उसको कहीं और ले जाओ। अगर आप लोगों को लगता है कि वहां काम नहीं करना है तो कहीं

15.03.2017/1255/SS-DC/3

और पैसे का उपयोग करो। कहीं की सीवरेज स्कीम तो पूरी करो। वहां पर न हमारी आई0पी0एच0 की डी0पी0आर0 बनी, न पी0डब्ल्यू0डी0 की डी0पी0आर0 बनी और न ऊना हैड-क्वार्टर पर कोई इस तरह के काम हुए लेकिन केन्द्र सरकार को बार-बार बोला जाता है कि केन्द्र सरकार का हमें सहयोग नहीं मिला। केन्द्र सरकार ने आज तक कभी इतना पैसा नहीं दिया होगा। यहां पर प्रश्न के उत्तर में आया है जोकि राष्ट्रीय उच्च मार्गों के बारे में हमने अगस्त महीने में लगाया था। हिमाचल प्रदेश में आज जो काम कीरतपुर से लेकर मनाली तक चला है उसके लिए 6403 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है और फोरलेन बन रहा है। आप ऐसा एक भी उदाहरण बता दो जब आपको साढ़े 6 हजार करोड़ रुपया एकमुश्त आया हो। मैं चैलेंज करता हूं, यहां 50 साल से राजनीतिज्ञ बैठे होंगे। दूसरा आपका फोरलेन परवाणू से लेकर कैथलीघाट तक बन रहा है। इसके लिए 2627 करोड़ रुपया आया है। मैं एक ही मद आपके ध्यान में ला रहा हूं, बाकी रोडों की बात छोड़ दो, कुल मिला कर दो फोरलेन्ज़ के लिए 9031 करोड़ 28 लाख रुपया नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले दो सालों में दिया है। अगर आप एक और नेशनल हाईवे की डी0पी0आर0 बना कर भेजेंगे तो आपको वह भी दिला देंगे। वे भेजेंगे, इसमें उनका कोई दोतरफा रवैया नहीं है। नितिन गडकरी जी ने आपके एडिशनल चीफ सैक्रेटरी चौहान जी उस समय साथ में थे तो उनको कहा कि भाई साहब अगर डी0पी0आर0 बनाकर भेजेंगे तो मैं पैसे दूंगा। मैं भी हैलीकॉप्टर में साथ में था।

Speaker: No more speaking. I would not allow you now. No recording.

15.03.2017/1300/केएस/एजी/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती : तो इस तरह से अध्यक्ष महोदय, जो दो तरफा व्यवहार हमारी विधान सभाओं से हो रहा है

Speaker: I won't allow you. No recording. This is not the way.

श्री सतपाल सिंह सत्ती: इसके बाद किसी ने नहीं बोलना है। मैं बस दो-तीन मिनट में खत्म कर दूंगा।

अध्यक्ष: दो मिनट में कैसे खत्म करेंगें आप?

श्री सतपाल सिंह सत्ती: दो-तीन मिनट में बोल देंगें।

अध्यक्ष: दो-तीन मिनट आपके कब खत्म होंगें?

श्री सतपाल सिंह सत्ती: अगर आपने जाना है तो आप उपाध्यक्ष महोदय को बुला लो। अगर आपको जल्दी है तो आप उनको बुला लो। वे यहां पर आ जाएंगें। आपको लघुशंका आई होगी। आप जा आओ थोड़ा, घूमकर आओ आप।

Speaker: Why should I go? (व्यवधान) I stop you. No more recording. यह गलत बात है। How long will you speak? You want speaking for hours. I won't allow you. (Interruption) आप सारा बजट ही पढ़ रहे हो। You can't read the entire Budget. (Interruption) आप समय देख लो, आपको कितना समय दिया है। मैंने आपको भी उतना समय दिया है जितना बाकियों को दिया है। Just see the time. I won't allow you. यह गलत बात है । मैंने सभी को समय दिया है। आप 25-26 मिनट बोल लिए हैं। अब आप सारा बजट पढ़ेंगें? This is not the way. मैं आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूं कि क्या सारा बजट ही पढ़ देंगें आप? आप 25-26 मिनट बोल चुके हैं। बाकियों ने भी बोलना है या

नहीं बोलना है? कुलदीप कुमार जी ने भी 23 मिनट बोला है। आप बन्द ही नहीं कर रहे हैं। वाइंड अप कीजिए तब तो ठीक है। You start another topic. This is wrong thing. आप क्या कहना चाहते हैं? Please wind-up in a minute.

15.03.2017/1300/केएस/एजी/2

श्री सतपाल सिंह सत्ती: अध्यक्ष महोदय, मेरा यही आग्रह है कि यह जो बजट है यह बिल्कुल आंकड़ों का मायाजाल है और मात्र झूठी घोषणाओं का पिटारा है। इस बजट से हिमाचल प्रदेश का कुछ भला नहीं होने वाला है। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश में चुनावों में रिजल्ट दिया है, उसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं और हिमाचल प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसके बारे में मैं दो मिनट के लिए बालूंगा। धर्माणी जी से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी जैसे इन्होंने कहा कि मोदी जी के मुंह पर थपेड़ा है। मैं तो बोलता हूं कि हमने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लिया है वोट से, गोवा को लिया है कोर्ट से और आज वीरेन्द्र सिंह मणिपुर में ओथ ले रहे हैं गठजोड़ से और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगें जनता की चोट पर। यह मैंने आपको बता दिया है। हम लोग सरकार बनाएंगें। यह बजट बिल्कुल फेल है इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करता। धन्यवाद।

अध्यक्ष: अब इस सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

15.3.2017/1410/av/as/1

सदन *की कार्यवाही दोपहर के भोजनोपरांत 2.10 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।*

उपाध्यक्ष : अब श्री राकेश कालिया जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश कालिया : उपाध्यक्ष महोदय, 10 मार्च, 2017 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर वर्ष 2017-18 के जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं, मैं उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में किसान-बागवान, बेरोजगार नौजवान, मजदूर, कर्मचारी इत्यादि सभी वर्गों को कुछ-न-कुछ देने का प्रयास किया है। खासतौर पर हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान है उनको बेरोजगारी भत्ता दिया गया है मैं उसके लिए यहां माननीय वीरभद्र सिंह जी के ऊपर चंद लाइनें बोलना चाहता हूं :-

यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है।।
पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना।
बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार-बार, तिनका-तिनका उठाना पड़ता है॥

माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी प्रयास किए हैं क्योंकि हम जब शुरू में आए थे तो थोड़े-थोड़े पैसों के लिए जिलाधीश के ऊपर निर्भर करते थे। उसके बाद विधायक निधि 15 लाख रुपये हुई। फिर 20 लाख रुपये हुई, कुछ आपकी तरफ से भी बढ़ाये गये। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने इसी टर्म में विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना के अंतर्गत 1.10 करोड़ रुपये की राशि की है जिसमें पहले 50 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाती थी। अब हमें छोटे-छोटे कामों के लिए किसी का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं तो क्या होता था कि हमारे जैसे छोटे एम0एल0ए0 देखते रह जाते थे और जिला का सारा पैसा कई बार वहां से बने मिनिस्टर के प्रभाव में चला जाता था। हम इस बात के लिए भी आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि

15.3.2017/1410/av/as/2

आपने डिस्क्रिशनरी ग्रांट देकर के हमें मंत्रियों क बराबर खड़ा कर दिया है। हम युवा क्लबों, स्कूलों तथा मैचिज इत्यादि में इस डिस्क्रिशनरी ग्रांट के माध्यम से पैसा दे सकते हैं। हम मुख्य मंत्री जी की दूरदर्शिता के ऊपर कहना चाहेंगे और यह भी कहना चाहता हूं कि फूड सिक्योरिटी ऐक्ट के तहत

श्री वर्मा द्वारा जारी

15/03/2017/1415/टी0सी0वी0/ए0एस0/1
श्री राकेश कालिया..... जारी।

माननीय मुख्य मंत्री ने जो स्कीम ऊना से 2004-05 में शुरू की थी, उसको जारी रखते हुए 3 दालें, 2 लीटर तेल और एक किलोग्राम नमक देने की योजना जारी रखी है। इससे गरीब लोगों को बहुत राहत मिली है। हमारा हिमाचल प्रदेश फल राज्य के रूप में विकसित हो, सेब तो यहां पहले ही होता है, लेकिन अब इटली से कुछ नये पौधे भी लाये जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब सत्यानन्द स्टोक्स जी यहां पर सेब लेकर आये थे, अगर ये (विपक्ष) उस समय होते तो ये उस पर भी नुक्ता-चीनी करते कि अमेरिका से जो सेब के पौधे लाये हैं, ये नकली पौधें हैं और इसमें वायरस है। नुक्ता-चीनी करनी की इनकी हमेशा आदत रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का किवी फ्रूट के लिए 4 करोड़ रूपये का बजट रखने के लिए भी धन्यवाद करता हूं। इससे हमारे नीचले 35 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र जैसे ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर के लोगों को फायदा होगा। आपने इस किवी फ्रूट का एक और फायदा बताया कि जिस प्रकार से बन्दर आम, संतरे, केले के फलों को बर्बाद कर देते हैं, उस प्रकार का नुकसान ये बन्दर किवी के फल को नहीं करते हैं। इसी तरह "मुख्य मंत्री कन्यादान योजना" की राशि को आपने 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया है, जिसके लिए गरीब लोग आपके आभारी रहेंगे। "मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना" के तहत पहले जो अनुदान 60 परसेंट दिया जा रहा था, अब उसको 80 परसेंट किया गया है, क्योंकि हमारे क्षेत्र ऊना में नील गाय, सांबर, बैल, आवारा पशु, बंदर और सुअर बहुत नुकसान करते हैं। इस अनुदान राशि को 80 परसेंट करने से हमारे किसानों को बहुत लाभ होगा। उनको खेती की रखवाली करने के लिए लगातार खेतों में नहीं बैठे रहना पड़ेगा। इसी तरह "वाई0एस0 परमार किसान स्वरोज़गार योजना" के तहत जो पॉलीहाऊस पहले 2000 वर्गमीटर में लगते थे, अब आपने 4000 वर्गमीटर में लगाने की मंजूरी दे दी है। आपने ग्रीन हाऊस रेव्लूशन लाने के लिए "मुख्य मंत्री ग्रीन हाऊस योजना" के तहत जिनके पॉलीहाऊस फट जाते हैं या कोई क्लाइमेट ट्रेजरी हो जाये तो उनको बदलने के लिए भी 50 प्रतिशत सबसिडी देने की बात की है। इसी के साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए

3 प्राइज रखें हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार 3 लाख रूपये, द्वितीय पुरस्कार-2 लाख रूपये और तृतीय पुरस्कार एक

15/03/2017/1415/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

लाख रूपया देने की घोषणा की है। आपने ब्लयू रेव्लूशन की भी इस बजट में बात की है, जो हमारे क्षेत्र मत्स्य पालन में रूचि रखते हैं, उनको रोज़गार देने के लिए आपने 1000 ट्राउट फिश सेंटर खोलने की घोषणा की है। ये माननीय मुख्य मंत्री जी की दूरदर्शिता का एक उदहारण हैं। इससे हमारे जो 12000 मत्स्य पालक हैं, उनको इन योजना का लाभ मिलेगा। जो मंकीज़ इंसान के प्रति हिंसक हो जाते हैं, उनको आपने तारादेवी (शिमला) में एक इकाई बनाने की घोषणा की है और उसमें 1000 बंदर रखे जाएंगे, क्योंकि ये बंदर स्कूल जाते बच्चों, महिलाओं या किसी के हाथ में कोई खाने का सामान देते ही झपट पड़ते हैं। आपने जो एक संस्था पर्यावरण के लिए काम करती है, उनके लिए "हिमाचल प्रदेश पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार" देने की घोषणा की है। इसमें प्रथम पुरस्कार एक लाख रूपये, द्वितीय पुरस्कार 50 हजार और तृतीय पुरस्कार 25 हजार रूपये देने की घोषणा की गई है। आपने इस बज़ट में प्रयास किया है कि सभी वर्गों को किसी-न-किसी तरह से लाभ पहुंचाया जाये और हिमाचल को भी आगे ले जाया जाये।

श्रीमती एन0एस0 .... द्वारा जारी।

15/03/2017/1420/ एन0एस0/ए0एस0 /1

श्री राकेश कालिया ----- जारी

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए इस बजट में 42 करोड़ रूपये की राशि चुने हुऐ बी.डी.सी. मैम्बर्ज़ और जिला परिषद के नुमाईंदों को 14 वें वित्त आयोग में ग्रांट देने की घोषणा की है। इससे जिला परिषद और बी.डी.सी. मैम्बर्ज़ ने जो फील्ड में कमिटमैंट्स की हैं, वे इस राशि से उन कमिटमैंट्स को पूरा कर पायेंगे। मैं इसके

लिए मुख्य मंत्री महोदय का बहुत आभारी रहूंगा। इस बजट में 'मुख्य मंत्री रूरल रोड रिपेयर योजना' के तहत भी प्रावधान किया गया है। आप (विपक्ष) कहते रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के रोड खराब हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये सड़कें एक दिन, दो साल या तीन सालों में खराब नहीं हुई हैं। हम आपको रोज़ कहते थे कि आप इन सड़कों की रिपेयर करवायें। आप नैशनल हाईवे की रिपेयर करवायें लेकिन आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। हमें ऐसा इनफरास्ट्रक्चर आपसे मिला है। जो सड़कें खराब थी उसके लिए मुख्य मंत्री महोदय ने 20 करोड़ का बजट रखा है। अभी मेरे एक मित्र बोल रहे थे कि हमने 9,000 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत करवायी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने कहां से कर दिया? अभी 4-5 सालों से तो यह योजना बन रही है। तब से जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है। हम सुन रहे हैं कि परवाणू से शिमला तक जो सड़क बननी है, पिछले चार-पांच सालों से इसकी योजना बन रही है। हमारी उस समय की केंद्र सरकार (कांग्रेस सरकार) ने इसकी सैंक्शन की थी। आप चाहें तो इसकी सैंक्शन निकलवा सकते हैं। आप इस मान्य सदन को मिसगाइड नहीं कर सकते हैं। सच्चाई को आप कभी भी ठुकरा नहीं सकते हैं। ये सब कुछ ओन रिकॉर्ड है। अगर आप जनता को जोर-जोर से बोल करके बताना चाहेंगे तो ऐसे किसी भी बात पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। पहले जनरल कैटेगिरी के लोगों को रहने के लिए मकान नहीं मिलता था। पहले किसी भी योजना के तहत कोई मकान नहीं मिलता था। अब मुख्य मंत्री महोदय इसके लिए 30 करोड़ की एक योजना लाये हैं। हर साल बी0पी0एल0 में जनरल कैटेगिरी के व्यक्ति को एक मकान दिया जाएगा। इसी तरह से हाउसिंग सबसिडी का

15/03/2017/1420/ एन0एस0/ए0एस0 /2

अमाउंट 75,000 से बढ़ा करके 1.30 लाख कर दिया गया है। 'मातृ शक्ति बीमा योजना' के तहत 10 से 75 वर्ष की आयु वाली महिलाओं/लड़कियों का बीमा किया जाएगा। हमारे माननीय मित्र हमेशा इस सदन में क्षेत्रवाद की बात करते हैं इसलिए मुख्य मंत्री महोदय ने ऊपर का हिमाचल और नीचे का हिमाचल की खाई को दूर करने के लिए धर्मशाला को

दूसरी राजधानी बनाया है। उसका क्या रूप बनता है इसके परिणाम बाद में ही नज़र आएंगे। पहले वहां पर विधान सभा दी गई और फिर हमने वहां पर दूसरी राजधानी दी है। जिन लोगों को शिमला दूर लगता है उन लोगों को इससे राहत मिलेगी। हमें भी कई बार दिल्ली जाना आसान लगता है और शिमला आना मुश्किल लगता है। ऐसी दिक्कतों को समझते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने दूसरी राजधानी दी है। इसके लिए मैं और न्यू मर्ज़ एरिया के लोग भी मुख्य मंत्री महोदय के आभारी हैं। शिमला क्षेत्र में जो पानी की दिक्क्त रहती है उसके लिए 837 करोड़ रूपये की कोल डैम से पानी उठाने की योजना बनाने की बात कही है। बिजली की पुरानी लाईनें और पुराने ट्रांसफॉर्मर, जहां कहीं पर पोल चेंज होने हैं उसके लिए भी मुख्य मंत्री महोदय ने 50 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया है। उसके लिए जनता आपकी धन्यवादी है। इसी तरह से पिछल साल स्किल डिवेलपमैंट में 1.55 लाख लोगों को पैसे दिये गये थे। इस बार आपने बेरोजगारी भत्ता जो प्लस टू पास हैं उनको 1200 रूपये और विकलांगों को 1500 रूपये देने की घोषणा की है। मुख्य मंत्री महोदय, यह आपका एक मास्टर स्ट्रोक रहेगा। जब हम विपक्ष में थे तो माननीय धूमल साहब कहते थे कि हम राख के ढेर पर बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि हम बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। आप कह रहे थे कि यह एक बारूद का ढेर है तो मुख्य मंत्री महोदय ने इसको डिफयूज़ कर दिया है और एक मास्टर स्ट्रोक लगाया है। बेरोज़गारों को उम्मीद होती है कि मेरा मोबाईल चलता रहे, मेरे बाईक में पैट्रोल डलता रहे, मैं कोई इंटरव्यू देने जाउं तो मुझे किसी को पूछना न पड़े तो यह उनके लिए एक बड़ी सहायता होगी। हमारे कई नौजवान डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और नशे की तरफ चले जाते हैं तो इस कदम

15/03/2017/1420/ एन0एस0/ए0एस0 /3

से उनको पोजीटिव एनर्जी मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपने पेंशन योजनाओं के भी पैसे बढ़ाये हैं। आपने वृद्धावस्था पेंशन 1200 से 1250 रूपये कर दी है। आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 650 रूपये से 700 रूपये की है। उसके लिए मैं और प्रदेश की जनता आपकी आभारी

हैं। हम आपकी दूरदर्शिता का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने प्रदेश में छोटी बसें लेने का फैसला किया है। हिमाचल जैसे हिली स्टेट में बड़ी बसें ऐक्सिडैंट का कारण बन जाती हैं। हमारे रोड छोटे और तंग हैं।

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

15/03/2017/1425/RKS/AS/1

श्री राकेश कालिया...जारी

जो आप 215 करोड़ रुपये की लागत से छोटी बसें खरीद रहे हैं उससे ट्रैफिक जाम नहीं होगा। दूसरा उन बसों से लोगों को सुविधा मिलेगी और एक्सिडैंट के चांसिज भी कम होंगे। हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग करना भी मुश्किल काम है। हिमाचल प्रदेश में जो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हैं उनके लिए आपने 15 करोड़ रुपये फंड्स रखा है। चाहे वे तारा देवी, कुल्लू, मंडी, जसूर या बिलासपुर के ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल हैं। इन स्कूलों में आपने नई तकनीकी के साथ ट्रेनिंग देने की बात की है। विश्व के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां हिमाचल प्रदेश में ड्राईविंग होती है, यदि ऐसे क्षेत्रों में ड्राइवर ट्रेंड होंगे तो जो हादसे देखने को मिलते हैं वे नहीं मिलेंगे। इसी तरह से आप बेरोजगार नौजवानों को एक हजार बस परमिट दे रहे हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए आपने काफी योजनाएं बनाई हैं। दो फोरलेन परवाणू से शिमला और कीर्तपुर से मनाली, ये बहुत पुरानी योजनाएं चली हुई हैं। 6-7 वर्षों से इनका भूमि अधिग्रहण हो रहा था। क्रेडिट लेने के लिए तो सब लोग आगे आ जाते हैं परन्तु सारी जनता जानती है कि कब से क्या-क्या हो रहा था। पहले यह रोड़ 90 मीटर से ज्यादा चौड़ा कर दिया गया था परन्तु बाद में इसकी चौड़ाई कम कर दी गई थी। इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 हजार मेधावी छात्रों को लैपटॉप्स बांटने की बात की थी, उसके लिए आपने फिर से 25 करोड़ रुपये का बजट रखा है। मेधावी छात्रों का प्रोत्साहन देने के लिए आपने यह योजना जारी रखी है। हिमाचल प्रदेश युनिवर्सिटी के आधुनिकीकरण और सीट्स बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपये दिया है। यह आपकी दूरदर्शिता है कि युनिवर्सिटी

को भी साथ-साथ लेकर आगे चला जाए। युवा क्लबों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार कर दी गई है। हमारे तीन जिलों में स्टेडियम पहले ही बने हुए हैं और आपने यह भी डिक्लेयर किया है कि 15 करोड़ रुपये की लागत से बाकी जिलों में भी इंडौर स्टेडियम बनाए जाएंगे। आपने यह भी घोषणा की है कि हर विधानसभा क्षेत्र में दस लाख की लागत से एक-एक खेल का मैदान बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री महोदय जी ने हर क्षेत्र में कुछ-न-कुछ देने का प्रयास किया है। हालांकि इसके लिए हमें केन्द्र

15/03/2017/1425/RKS/AS/2

सरकार से उतनी मदद नहीं मिली है जितनी की मिलना चाहिए थी। 'पत्रकार कल्याण योजना' के तहत 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। पत्रकार भी हमारी योजनाओं की कवरेज करते हैं। जहां हम उद्घाटन करते हैं, फाउंडेशन स्टोन ले करते हैं, पत्रकार हमारी योजनाओं की कवरेज करते हैं। इसके लिए भी हम आपके आभारी रहेंगे। आप किडनी के रोगी की डायलिसिस के लिए मंडी, सोलन, कुल्लू और धर्मशाला के अस्पतालों में डायलिसिस योजना शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए भी हम आपके धन्यवादी रहेंगे। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को 3 लाख रुपये अनुगृहित राशि दी जाती है, वह आपने बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। उसके लिए भी यह सदन आभारी रहेगा। इसी तरह से जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका मानदेय 450 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दिया गया है। आंगनबाड़ी सहायकों का मानदेय 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। जलगार्ड का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 1700 रुपये किया गया है। चौकीदारों का मानदेय 2050रुपये से बढ़ाकर 2350 रुपये किया गया है। शिलाई अध्यापकों का मानदेय 2300 रुपये से बढ़ाकर 2600 रुपये किया गया है। मिड-डे-मील वर्करों का मानदेय 200रुपये और बढ़ाया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी छोटी सी आय में एक बहुत बढ़िया काम करने का प्रयास किया है। मुख्य मंत्री महोदय ने साफ तौर पर बताया है कि हमें कहां से कितना पैसा आएगा। मान लो हमारे पास 100 रुपये है तो उसमें 28.67 रुपये

कर राजस्व से आएंगे। 5.78 रुपये गैर- कर राजस्व से आएंगे। 17.39 रुपये केन्द्रीय कर की हिस्सेदारी के रूप में आएंगे। 48.16 प्रतिशत हम केन्द्रीय अनुदान के रूप में आश्रित हैं। 100 रुपये खर्च कैसे करना है? 100 रुपये में से 26.91 रुपये वेतन दे देंगे। 13.83 परसैंट पैंशन दी जाएगी। 9.93 परसैंट से ऋण की अदायगी करेंगे। 9.78 परसैंट ब्याज की अदायगी की जाएगी। 39.55 परसैंट विकास योजनाओं के ऊपर खर्च करने के लिए रखा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय मैं आपको एक शेर बोलकर अपनी बात को विराम देना चाहता हूंः-

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

15.03.2017/1430/SLS-DC-1

श्री राकेश कालिया ...क्रमागत

अपने दम पे ये दुनिया जीत लूंगा,

मैं तूफ़ानों से टकराने का जोश रखता हूं,

उनके उकसाने से मुसकराहट खिल उठती है,

वक्त पर काबू में अपने होश रखता हूं,

बुजुर्गों की जंग का लोग करेंगे फ़ैसला,

सबके सामने मैं अपने गुण-दोष रखता हूं।

15.03.2017/1430/SLS-DC-2

उपाध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 10 मार्च को मान्यवर मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष के बजट प्रस्तुत करती बार जो यहां भाषण दिया गया है, मैं उस पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूं।

मुझे इस राजनीति में रहते हुए 40 वर्ष बीत गए। लोक सभा में रहा, राज्य सभा में रहा और विधान सभा में भी रहा। लेकिन मैंने प्रथम बार इतना लंबा और नीरस भाषण सुना और 40 वर्षों में यह पहला अवसर है। मुख्य मंत्री जी साढ़े चार घंटे लगातार बोलते रहे और यहां पर इतना नीरस एवं आधारहीन भाषण दिया कि वह बजट पर कम बोले, अनेकों आगामी घोषणाएं कर दीं। पुरानी पूरी हुई नहीं, उन्हीं को बदल कर पुनः घोषणाएं कर दीं और इसी में सारा समय चला गया। ऐसी लोरी गाई कि अधिकांश मंत्री इन साढ़े चार घंटों में यहां सोए पाए गए। अख़बारों में भी इनके सोने के बारे में बात आई। घोषणाओं में तो मुख्य मंत्री जी सचमुच नंबर-1 हैं। इतनी घोषणाएं की कि पिछला कोई मुख्य मंत्री इतनी घोषणाएं नहीं कर पाया है। कोई प्राथमिक स्कूल मांगता है तो मिडल स्कूल मिलता है। मिडल मांगता है तो हाई मिलता है। हाई स्कूल मांगता है तो प्लस टू मिलता है। प्लस टू मांगे तो कॉलेज मिलता है। बैजनाथ में तो घोषणाओं की इतनी झड़ी लगाई कि मांगने वाले भी हैरान हो गए कि यह सब-कुछ बिन मांगे मिला है; ऐसा वक्त फिर कभी और नहीं आएगा।

लोग मज़ाक में कहते हैं कि भागते चोर की लंगोटी भली। सब जानते हैं कि यह सब घोषणाएं तो पूरी नहीं होगीं, इसलिए घोषणाओं का आनंद लेते हैं और भीड़ जुटती है। यह सही बात है। महोदय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राजस्व विभागों की हालत ऐसी बन गई है कि भविष्य में आने वाली सरकारों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, इन्हीं कामों को करना कठिन हो जाएगा। स्कूलों की आपने क्या दशा कर

15.03.2017/1430/SLS-DC-2

दी? सर्वेक्षण के मुताबिक कम स्कूल खुलते हैं और ऐच्छिक रूप से ज्यादा खुलते हैं। हमें वह समय याद है जब वित्त विभाग इन पर अंकुश लगाता था। कोई योजना जाती थी तो वित्त विभाग अपना पक्ष रखता था कि इसके लिए पैसा नहीं है। लेकिन मुख्य मंत्री जी का दबदबा इतना है कि वित्त विभाग भी मूक दर्शक बनकर मोहर लगा रहा है। अरे, बिठाने के लिए कानूनगो नहीं है फिर भी वहां तहसील खुल गई। यह सब हुआ है।

पिछले कल जब बाली जी, मान्यवर मंत्री जी बोल रहे थे, बड़े ज़ोर-शोर से बोल रहे थे और आपको तालियां बजाने की बात भी कह रहे थे। मुझे कुछ समय तक तो यह विश्वास ही नहीं हुआ कि ये बाली जी बोल रहे हैं। वह अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बेरोज़गारी भत्ते को लेकर यहां तारीफ़ के बड़े पुल बांधे हैं। माना कि आपने प्रावधान किया है लेकिन कब किया? अंतिम चरण में; चौथे वर्ष में। वह भी अनेकों कंट्रोवर्सीज और दवाब के कारण हुआ है। बजट में लिखा है कि अभी इस योजना को बनाना है। अब 3 महीने तो योजना बनाने में चले जाएंगे। जब घोषणा का समय आएगा तो शायद हो-न-हो, कहीं आचार सहिंता लग गई तो यह बाद में मिलेगा। ऐसी घोषणा कर डाली! जब ये बोल रहे थे तो मुझे राम लीला का एक प्रसंग याद आ गया। कहीं पर राम लीला हो रही थी और हनुमान के पार्ट के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढ़ रहे थे कि किसे हनुमान बनाया जाए। उस दिन राम लीला में यह दिखाना था कि हनुमान जी उड़कर लंका जाएंगे। उनको बाली जी जैसा एक व्यक्ति मिल गया।

जारी ...श्री गर्ग जी द्वारा

15/03/2017/1435/RG/DC/1
श्री महेश्वर सिंह---जारी

और उन्होंने उसको हनुमान का किरदार दे दिया। उसकी कमर में एक रस्सा बांध दिया गया और स्टेज पर ऊपर स्टील के पोल में उसको बांध दिया। सबके मित्र और दुश्मन दोनों होते हैं। अंधेरा था और स्टेज के पास लग रहा था कि वाकई में हनुमान जी उड़ रहे हैं, आगे-पीछे हो रहे हैं, महिलाएं कीर्तन गा रही थीं। इसी बीच एक व्यक्ति ने चाकू फेंका जिससे रस्सा कटा और हनुमान जी एक दम से धड़ाम से आगे गिरे। सबने तालियां बजाईं और कहने लगे यह हनुमान जी तो जोश में चले गए और कहने लगे कि यह तो लंका पहुंच जाते। लोग दौड़े और उसको पकड़ा, कहां कि बधाई हो हनुमान जी, तालियां बजीं और हनुमान को मंच पर ले गए और उसको सम्मानित करने लगे। उसने कहा कि ताली बाद में बजाना पहले यह बताओ कि मेरा रस्सा किसने काटा, मेरी तो कमर टूट गई थी। तो इसी प्रकार का दृश्य कल देखने को मुझे यहां मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, अनेकों इस प्रकार की बेतुकी घोषणाओं पर पूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता ने यहां चर्चा की, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप फिर घण्टी बजा देंगे, तो मन के तार टूट जाएंगे। इसलिए समय से पहले ही मैं समाप्त करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में कुछ बातें मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन में रखना चाहूंगा। अच्छा हुआ कि राजस्व मंत्री जी आ गए, ये इन चीजों के मेरे सबसे बड़े गवाह हैं। जब नई सरकार बनी, तो 25 जनवरी को कुल्लू के ऐतिहासिक मैदान में तीन घोषणाएं हुईं। पहला तो लग घाटी में सब्जी मण्डी का खोलना, दूसरा भून्तर में तहसील खोलना और तीसरी घोषणा पर्यटन के लिए पर्यटन सूचना केन्द्र की स्थापना भून्तर में करने की थी। पहली घोषणा के बारे में तो माननीय मुख्य मंत्री जी को बारे-बार याद करवाया, कुछ काम भी हुआ, लेकिन जिनको वे बड़े प्रेम से मकड़झण्डू कहते हैं, उनके हस्तक्षेप से आज चार वर्ष बीत गए और वह योजना समाप्त हो गई। लेकिन सब्जी मण्डी नहीं खुली। यह मुख्य मंत्री जी की पहली घोषणा थी। आप (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की ओर इशारा करते हुए) कह रहे हैं कि तहसील खुल गई। निश्चित रूप से दशहरे के उत्सव पर आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि घोषणा की थी कि एक वर्ष में नया भवन बनेगा। शिलान्यास हो गया, ---(व्यवधान)--मुझे बोलने तो दो, फिर उसके बाद बात होगी। साथ में पर्यटक सूचना केन्द्र का शिलान्यास भी हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री

15/03/2017/1435/RG/DC/2

जी को बताना चाहूंगा कि आपकी अध्यक्षता में हुई घोषणा के बावजूद कि यहां तहसील भवन बन जाएगा, एक भी पत्थर उस शिलान्यास पर नहीं लगा। तो ये आपकी घोषणाएं हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार वर्ष 2013-14 के दशहरे की बात मैंने कह दी कि इन्होंने क्या किया। मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2013 में एक घोषणा की। अभिभाषण में भी उसका उल्लेख था और मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में भी आदर्श ग्राम योजना का उल्लेख था। शायद आप सबको भी याद होगा। दो बार हम विधायकों से इस बारे में अनुशंसा ली गई कि कौन सा गांव आदर्श बनाना है। दस-दस लाख रुपये का प्रावधान दो सालों में किया गया, लेकिन आज उस घोषणा का नाम ही इसमें से निकाल दिया गया। अब वह मुख्य मंत्री ग्रामीण आदर्श योजना पता नहीं कहां गई, कहां नहीं गई। अब आप एक नई चीज ग्रामीण रूरल रोड्ज के लिए पैसे का प्रावधान लेकर आए हैं। भगवान करे कि यह पूर्ण हो। कहीं यह भी ऐसी न हो जैसी मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना थी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के पैरा-3 के बिन्दु एक के अन्तर्गत घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा तथा समावेश विकास के क्षेत्र में प्रथम रहा है, सवोच्च रहा है।

एम.एस. द्वारा जारी

15/03/2017/1440/MS/AS/1

श्री महेश्वर सिंह जारी-------

इतना तो हम मानते हैं कि ये जो जगह-जगह स्कूल खोले, आपने घोषणाएं कीं तो निश्चित रूप से साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा होगा लेकिन क्या उतनी गुणवत्ता भी बढ़ी? गुणवत्ता का तो सर्वनाश हो गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी यहां बैठे हैं। मुझे लगता है कि आपको किसी ने पूछा भी नहीं है कि कहां क्या करना है। मुझे तो आपने जब मैंने बात कही थी कि खराल क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि कोई भी

ऐसा संस्थान उस एरिया में नहीं है और वहां पर 9 पंचायतें हैं तो आपने कहा कि यह मापदण्ड में नहीं आता है। मेरे पास पत्र है जिसमें लिखा है कि इतनी आपको जनसंख्या चाहिए तब खुलेगा, अभी इंतजार कीजिए। फिर आनी में जाकर आपने 6-6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिए। क्या यह सच्चाई नहीं है? मापदण्ड को कौन देखता है? घोषणा-पर-घोषणा और आप मंत्री जी ऐसी कोशिश करते हैं कि मैं वहां पर स्टाफ पूरा करूं लेकिन उतने में मुख्य मंत्री जी एक और गड्ढा डालते हैं। फिर स्वास्थ्य मंत्री जी चलते हैं और उसको भरते हैं तो फिर एक और गड्ढा पड़ रहा है। तो ऐसा आपका हाल है कि घोषणा-पर-घोषणा तो है लेकिन पुरानी घोषणाएं ऐसे ही समाप्त हो रही हैं। बाली जी ने, अभी आज वे सदन में मौजूद नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी आप उनके मित्र हैं। मैं उपाध्यक्ष जी के माध्यम से कहूंगा कि आप उनको कन्वे कर देना। आपके जितने भी दुर्गम क्षेत्र जैसे मणिकर्ण और लगघाटी है। यहां आश्वासन दिया गया कि सिविल सप्लाईज कारपोरेशन वहां पर गैस एजेंसीज की स्थापना करेगा और पिछले कल जब मैंने एक प्रश्न इसी के संदर्भ में पूछा तो मंत्री जी जवाब देते हैं कि अभी तो इण्डियन ऑयल कम्पनी द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। आपने तो बात की थी अपने सिविल सप्लाईज कारपोरेशन की और अब इण्डियन ऑयल कम्पनी कहां से आपकी एजेंसी आ गई? आप सिर्फ सर्वेक्षण करवाते हैं।

इसी तरह से बसों के चलने के बारे में यहां पर बड़े-बड़े क्लेम और काउंटर क्लेम होते हैं। पहले बसें नहीं थी यह कहकर नई बसें शुरू नहीं हो रही थी। फिर जब बसें आई तो कहते हैं कि कन्डक्टर नहीं है। कभी कन्डक्टर नहीं है और

15/03/2017/1440/MS/AS/2

कभी बस नहीं है। भगवान ही जाने ये कैसा गोरखधन्धा है? यहां पर बड़े जोरों-शोरों से कहा गया है कि स्कूल के बच्चे के लिए निःशुल्क बस सेवा देंगे लेकिन कोई नई बस नहीं चलाई। वे पुरानी बसें इतनी ओवर-लोडिड हैं कि किसी दिन राम नाम सत हुआ तो पूरा-का-पूरा दायित्व मंत्री जी का और इस सरकार का होगा। कोई बताए कि बच्चों के लिए आपने कितनी स्पैशल बसें चलाईं? है कोई रिकॉर्ड? कोई बस नहीं चलाई। शून्य। उन्हीं बसों पर ओवर-लोडिंग हो रही है। ऐसी स्थिति बन गई है। कन्डक्टर कहां से मिलेंगे? यहां तो वह कहावत चरितार्थ होती है कि "अन्धा बांटे रेवड़ियां मुड़-मुड़ अपने को दे"। मैं वह

दिन भूला नहीं हूं और उपाध्यक्ष जी आप भी नहीं भूले होंगे, जब हमने यह कहा था कि लाहौल-स्पिति में तो कन्डक्टर्ज के इंटरव्यु ही अभी तक नहीं हो रहे हैं लेकिन यह सूची कहां से आ गई? तो मुख्य मंत्री जी ने उस तरफ से माइक का ध्यान नहीं किया तो बोला था कि मेरे रोहडू में भी आ गई है वहां भी अभी इंटरव्यु नहीं हुए। वहां यह सूची कौन देता था, इन बातों को कौन नहीं जानता? ऐसा लगता है कि जो हम बसों की बात करते हैं "न तो कभी नौ मन तेल जलेगा और न कभी राधा नाचेगी"। हम इंतजार करते रहेंगे और घोषणाओं-पर-घोषणाएं होंगी। कभी कन्डक्टर नहीं है, कभी ड्राइवर नहीं है, कभी ये नहीं है और कभी वो नहीं है तथा पांचवां वर्ष भी समाप्त हो जाएगा।

यहां अभी आम और लीची के बारे में बात कही गई कि इसलिए एक नई योजना आई है और कलस्टर बनाए जाएंगे। कहीं ऐसे ही कलस्टर तो नहीं बनाएंगे जैसे सेब वालों के लिए जो इटेलियन पौधे आए तो हमने कहा कि ये किसको मिलेंगे? तो कहा कि इसके लिए कलस्टर बने हैं। वे कलस्टर किसने बनाए? जगह-जगह फल उत्पादक संगठन हैं लेकिन किसी ने उनको नहीं पूछा और मनमाने ढंग से पता नहीं कहां दिन को या रात को कलस्टर बने। जहां पानी है, सिंचाई के लिए लोगों के पास पानी है उनके नाम ही कलस्टर में नहीं है। कलस्टर में उनके नाम हैं जो आपके चहेते हैं, चाहे पानी है या नहीं है। अब जो उन पौधों में वायरस की बात की जाती है तो मैंने अभी तक उसकी पुष्टि नहीं की है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

15.03.2017/1445/जेके/डी0सी0/1

श्री महेश्वर सिंहः--------**जारी**------

मैं पुष्टि किए बगैर उसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा सरकार सुनिश्चित करें कि ये जो पौधे आते हैा, वे सबको मिलें। क्लस्टर अगर बनाने हैं तो क्लस्टर को बनाने में कम से कम वहां के बागवानों को विश्वास में लीजिए।

पैरा-24, पृष्ठ-15 में "मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना" की बात कही गई है। सम्भवतः ये सौर ऊर्जा से जो करंट लगाना है उसके बारे में कही गई है लेकिन एक धर्म सत्य है। यह प्रोविजन पीछे भी था। केवल 2 प्रतिशत लोगों ने इससे लाभ उठाया। वह इतनी मंहगी पड़

रही है कि वह सम्भव ही नहीं है। माननीय कृषि मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए एक बात जरूर कही थी कि एक बात पर विचार करेंगे कि इसमें करंट लगाना जरूरी है या इसको थोड़ा ऊंचा करें, क्योंकि करंट तब लगता है जब बंदर छलांग लगा करके दूसरी तरफ उसमें टच करके गिरेगा तब उसको करंट लगेगा। करंट लगने से पहले वह खेत में हाजिर हो जाता है, यह मंत्री जी का कथन था। हम इस बात से सहमत है। इसलिए इस पर पुनर्विचार करें ताकि बाड़ बन्दी हो। परन्तु इतनी मंहगी न हो कि कोई इस पैसे का इस्तेमाल ही न कर पाए।

पीछे जो ग्रीन हाऊसिज थे उस वक्त पॉली हाऊसिज के लिए अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो सरकार ने 80 प्रतिशत सब्सिडी की बात कही थी और किसान को केवल 20 प्रतिशत देना पड़ता था। उसमें क्या हुआ कि जब प्राकृतिक आपदा का प्रकोप हुआ, जितने पॉली हाऊसिज बनें थे वे सब तहस-नहस हो गए, समाप्त हो गए। लोग उसमें राहत राशि के लिए इन्तज़ार करते रहे। एक फूटी कौड़ी की उसमें किसी को राहत नहीं मिली। आज फिर उस योजना को एक और नाम दिया गया। मुख्य मंत्री जी की अब एक घोषणा और है। क्या 50 प्रतिशत सब्सिडी उनको मिलेगी जिनके वे टूटे हैं और जिनमें शीट लगानी है? अच्छा होता अगर उस समय कम्पनी के माध्यम से इन्श्योरैंस का प्रावधान कर दिया होता तो जो क्षति हुई थी उसकी भी क्षतिपूर्ती हो जाती और सरकार को फिर इस प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं

15.03.2017/1445/जेके/डी0सी0/2

थी। अगर उसकी मुरम्मत हो जाती तब जो राशि पहले घोषित थी, जो 80 प्रतिशत का अनुदान था और 20 प्रतिशत किसान लगाता था, वही चल सकता था। इन ऐसी घोषणाओं को देख कर बड़ी हैरानी होती है कि हम कहां पहुंचेंगे? क्या केवल घोषणाओं के सहारे ही पहुंचेंगे? जो क्षति हुई उससे तो लोगों को फायदा नहीं मिला, कोई राहत राशि नहीं मिली। इसमें बिल्कुल सत्यता है। आज तक नहीं मिली है। यह घोषणाओं को देख कर मुझे लगता है कि आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे। एक बार दो शिकारियों ने सारा जंगल छान मारा कुछ

नहीं मरा। शाम के वक्त एक पेड़ के नीचे वे बैठ गए। कहने लगे कि आज तो भूखे मर गए, कुछ नहीं मरा। उतने में सामने आ करके एक घुग्घी बैठ गई। आप जानते हैं कि पेड़ में अगर लोहा भी लगा हो तो हम ऊपर के पहाड़ के लोग उसको भी देवता मानते हैं। एक शिकारी खड़ा हुआ, हे देवता, भूखे मर गए अगर एक घुग्घी मरेगी तो तुझे जोड़ी बकरे की देंगे। दूसरा बोलता है, क्या बोल रहा है चुप हो जा? एक मरेगी घुग्घी और बकरे देने है दो? वह कहता कि मैंने कौन से सच ही देने हैं। कहीं देवता न सुन ले , तू चुप रह। ये तो सिर्फ कहने के लिए बातें कहनी है। कहीं ये ऐसी घोषणाएं तो नहीं है कि मरनी नहीं घुग्घी और देने दो बकरे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।

जहां तक विधायक प्राथमिकताओं का सम्बन्ध है अनेकों बार यहां पर मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिए कि जो विलम्ब होता है वह एफ0सी0ए0 क्लीयरैंस और एफ0आर0ए0 क्लीयरैंस के कारण होता है। मुख्य मंत्री जी ने उस वक्त बड़ी कृपा करके एक बात कही थी कि इस सारी की सारी प्रक्रिया को मैं शॉर्ट कर दूंगा और कंज़र्वेटर की अध्यक्षता में सर्कल में ही नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा और सारे ऑफिसर बैठ कर समीक्षा करेंगे व समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार फोरैस्ट क्लीयरैंस होगी।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

15.03.2017/1450/SS-AS/1

श्री महेश्वर सिंह क्रमागतः

यह तो घोषणा हुई लेकिन मान्यवर मंत्री जी ने क्या किया। वन मंत्री जी ने क्योंकि इतनी प्रॅमोशन्ज़ की हैं और इतने ऑफिसर्ज़ की कतार है कि जहां हमने एक प्रिंसीपल सी0सी0एफ0 सुना था, आज एडिशनल के नाम से 12-13 लोग बैठे हैं। अब इनसे क्या काम लिया जाए? तो एक नोडल ऑफिसर टोलैंड में भी बिठा दिया कि केवल एफ0सी0ए0 और एफ0आर0ए0 क्लीयरैंस का काम देखो। अब उसने भी बैठकर कुछ काम करना है। उसने सब कुछ कम्प्यूटर में फीड कर रखा है। एक ही किस्म का ऑब्जैक्शन दस बार फील्ड को

जा रहा है कि यह सूचना नहीं आई और वही रिपीट होती है। मैंने तो प्लानिंग की मीटिंग में भी मान्यवर मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाई थी। एक ऑफिसर को एडजस्ट करने के लिए यह कार्यालय खोला, अब लास्ट में एक और चैनल खुला और यह प्रोसीजर है कि एफ0सी0ए0 क्लीयरैंस के समय पास होने से पहले वन मंत्री के पास भी फाइल जायेगी और वह दस बार जा रही है। प्रोसीजर में तीन सर्वे होते हैं और तीनों सर्वे का विवरण देना पड़ता है, जिसमें सबसे कम पेड़ लगते हों। जिसमें सबसे अच्छा सर्वे हो, उसकी अनुशंसा करके फील्ड से भेजते हैं। मंत्री जी के दफ्तर में तीन रोडों को लेकर दस बार फाइल जा चुकी है। मैंने नाम भी पूछे, उसके बारे में प्रश्न भी था। तो मंत्री जी ने उस पर लिखा कि इसमें पेड़ ज्यादा लग रहे हैं। इस संख्या में कमी करो। अरे बाबा, जो सड़क बननी है वह जनहित में है। उसमें जो पेड़ लगने हैं वे लगने हैं। काश आप इतनी चिन्ता तब करते जब आपके अवैध कटान में पेड़ कटते हैं। जब जंगल कट जाते हैं तो आप सुख की नींद सोये होते हैं और जब सड़कों की संस्तुति करनी है तो आप एक-एक पेड़ गिनते हैं। धन्य हो आपको। इसलिए आज तक वे सारी चीज़ें आपके पास लटकी हुई हैं।

महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। यहां कहा जा रहा है कि हम उधार लेकर भी काम चलायेंगे। जबकि कल यहां स्पष्ट हो गया कि जो उधार लेने की सीमा थी वह समाप्त हो चुकी

15.03.2017/1450/SS-AS/2

है। कहां से उधार लोगे? एक और बात भी आई है कि इस समय जो विकास के लिए पैसा उपलब्ध है वह 100 रुपये में से 12 प्वाइंट कुछ है। कहने का मतलब है कि 12 पैसे से क्या विकास करोगे? उसमें पैंशन का पैसा भी आना है। --(व्यवधान)-- 39 के आगे हिसाब आया तो साढ़े 12 रह जाता है। चलो 39 ही सही। वह भी कहा है कि हम उधार लेकर करेंगे। उधार तो मिलने वाला नहीं है, फिर कैसे करेंगे? कैसे होगा यह काम? कहां से होगा? केन्द्र इतना पैसा दे रहा है, उसके बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि घंटी बज चुकी है। केन्द्र बहुत पैसा दे रहा है। लेकिन कहीं धन्यवाद की बात नहीं, बस यही कि पैसा नहीं मिल रहा है। कैसे

पैसा नहीं मिल रहा है? अरे मिल नहीं रहा है तो कहां से इतने नेशनल हाईवे में पैसा मिला जैसा कि यहां कहा गया कि 9 हजार करोड़ रुपया मिला? कौन पैसा दे रहा है? यह तो ऐसी कहावत चरितार्थ होती है- गाठी नी लिद और थाणेदार सौगी जिद्द। एक बात सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। इनके क्षेत्र से संबंधित एक कहावत है। --(व्यवधान)--

मुख्य मंत्रीः अभी आपने कहा कि हमारी ऋण लेने की सीमा खत्म हो गई है। यह गलत ब्यानी है। पहले दो वर्षों के अंदर जब वह कमी आई और अभी 14वें फाइनेंस कमिशन का अवार्ड आया तो उसके बाद हमारी कोई कमी नहीं है। इसलिए आपको पहले तथ्य जानने चाहिएं और उसके बाद अपना मधुर भाषण देना चाहिए।

श्री महेश्वर सिंहः जो मान्यवर मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा है, उसको देखेंगे, तब फिर इस पर बात हो सकती है। धन्यवाद, आपने सूचना दी। महोदय, एक कहावत सुनाऊंगा। स्वास्थ्य मंत्री जी के क्षेत्र में एक बोटी था। खानसामा, जिसको हम बोटी बोलते हैं। उसकी एक प्रेमिका थी, उसका नाम शाड़ी था और जहां-जहां वह खाना बनाने जाता था तो शाड़ी ज़रूर पहुंचती थी क्योंकि वह उसका विशेष ध्यान रखता था

जारी श्रीमती ए0वी0

15.3.2017/1455/av/as/1

श्री महेश्वर सिंह ---------- जारी

क्योंकि कड़छी उसके हाथ में होती थी। उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि मीट और घी तो हम पहाड़ियों के प्राण होते हैं। द्रंग में मीट को शिखा बोलते हैं और घी को तार बोलते हैं। वहां पर शाड़ी चली गई और बोटी उसको ऐसी जगह छुपाकर बैठाता था जहां वह उसको पूरा खाना भी दे सके और कोई नोटिस भी न कर पाये। उसने उसके लिए भात (चावल) के नीचे सूखा देसी घी दबाकर लाना, हिस्से का घी चावल के ऊपर रखना और फिर कहना

कि ले शाड़िए तेरा बांडा (हिस्सा)। मीट के लिए भी बोटी-बोटी को नीचे दबाना और ऊपर से कड़छी से हिस्सा डालना और कहना कि ले शाड़िए तेरा बांडा। उसने इस तरह का ड्रामा 6-7 बार किया और सोचा कि अब तो यह शाड़ी संतुष्ट हो गई होगी। दूसरी दफा जब वह दाल लाया तो वह पूछती कि बोटिया क्या आन्दया शिखा या तार। वह हैरान हो गया और उसने बाटू नीचे रखा तथा कहा कि शाड़िए भी बोल। उसने पूछा कि क्या आन्दया शिखा या तार। बोटी ने बोला कि शाड़िए खाख ही की डुवार तू अब भी नहीं रजी। केंद्र सरकार इतना दे रही है और फिर भी कहा जा रहा है कि कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आपको कम-से-कम अब तो संतुष्ट होना चाहिए और अगर नहीं देगी तो आपका काम कैसे चलेगा।

जहां तक बंदरों के उत्पात की बात है उसके लिए मंत्री जी कभी उनकी संख्या बताते हैं, कभी गणना करते हैं, कभी वर्मिन घोषित करते हैं और कभी कुछ करते हैं मगर परिणाम शून्य ही निकलता है। अब कह रहे हैं कि आपने बंदरों के लिए भी एक वाटिका बनानी है। इसके लिए कहीं उसी जगह का चयन तो नहीं किया गया है जहां तारादेवी में जंगल कटा था। पहले जंगल इसीलिए काटा कि वहां वाटिका बनेगी? आपने यह घोषणा भी अनेकों बार की है। इसके अतिरिक्त आज आवारा पशुओं का इतना संकट है कि लोगों के खेत-के-खेत खाली हो गये हैं। इसलिए जागो और कुछ करो। (---व्यवधान---) बंदरों को किस चीज से मारे, डंडे से मारे? लाइसैंस तो आप (वन मंत्री) देते नहीं। कौन मारेगा? बन्दूक के लिए लाइसैंस फीस आपने ज्यादा कर दी फिर कहते हैं कि मारो। डंडे से मारे, क्या यह सम्भव है?

15.3.2017/1455/av/as/2

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और माननीय सदन का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपने स्थान को ग्रहण करता हूं।

15.3.2017/1455/av/as/3

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रोहित ठाकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 मार्च, 2017 को वित्तीय वर्ष 2017-18 के जो बजट अनुमान यहां पर रखे मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी की पूरे हिमाचल प्रदेश के विकास की जो वचनबद्धता है उस वचनबद्धता को दोहराया है। यह बजट जहां डवैल्पमैंट ओरिएंटिड है और विशेष रूप से युवाओं को समर्पित है। कांग्रेस पार्टी की एक वचनबद्धता थी कि हम बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे इसके लिए लगभग 150 करोड़ रुपये की राशि रखकर उस वचनबद्धता को दोहराया गया है। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष हम जो 100 करोड़ के लगभग राशि स्किल डवैल्पमैंट के लिए रख रहे हैं वह अलग से रखी गई है। रोजगार के लगभग 19000 के करीब नये पद आने वाले वित्तीय वर्ष में सृजित किए जायेंगे। जहां हिमाचल के विकास की बात आती है।

श्री वर्मा द्वारा जारी

15/03/2017/1500/टी0सी0वी0/ए0एस0/1
श्री रोहित ठाकुर.(मुख्य संसदीय सचिव)... **जारी।**

आज हमारे हर व्यक्ति की पर-कैप्टा इंनकम 1.47 लाख से अधिक हो चुकी है। एक हिमाचल 1950 के दशक में वह भी था, जब ये आंकड़ा मात्र 240 था। कांग्रेस के प्रगतिशील नेतृत्व के कारण आज हिमाचल प्रदेश में चाहे शिक्षा की बात हो, जिसके लिए अभी हाल में ही हमारे प्रदेश को प्राईज दिया गया है और सम्मानित भी किया गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। इसके अलावा चाहे स्वास्थ्य के इंडीगेटर्ज/पैरा मीटर्ज, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत ढ़ांचे को सुदृढ़ करने की बात हो, हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास हुआ है और विशेष करके हमारी

सरकारी की प्राथमिकता है कि हमारे जो दूर्गम ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको प्राथमिकता दी जाये। सड़कें जो हमारे पहाड़ी राज्य में एक तरह से जीवन रेखा का कार्य करती है, उसको भी प्राथमिकता दी गई हैं। इस क्षेत्र में लगभग 3400 करोड़ रूपये के आसपास प्रावधान रखा गया है। इन 4 वर्षों में लगभग 2000 किलोमीटर सड़कें और लगभग 204 पुल बनकर तैयार हुए हैं जो अपने-आप में विकास के मामले में एक मील पत्थर साबित हुए हैं। इसी तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश में वर्ड बैंक एडिड प्रोजैक्ट जो प्रारम्भ में मात्र 1365 करोड़ रूपये का था, आज उसकी लागत बढ़कर 1800 करोड़ से ऊपर हो गई हैं, उसमें उन 10 सड़कों में से 9 का कार्य मुकम्मल हो चुका हैं। ठियोग-खड़ा पत्थर हाटकोटी रोड़ जो ऊपरी शिमला की जीवन रेखा हैं, उसका भी 80 प्रतिशत् कार्य पूर्ण हो चुका है। मुझे याद है, पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में यह कार्य मात्र 18 प्रतिशत् हुआ था। आज यह बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत् हो गया है और इसी वर्ष ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की चार्ज़शीट देख रहा था, जो इन्होंने राज्यपाल महोदय को दी हैं। उसमें भी प्रमुख रूप से ठियोग-खड्डा पत्थर -हाटकोटी रोड के निर्माण में अनियमितताएं बताई गई हैं। कुछ वर्ष पूर्व 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक नाट्क 'सत्याग्रह' के रूप में इस सड़क से संबंधित निकाल रहे थे। इन्हें आशा नहीं थी कि यह सड़क मुकम्मल होगी। आज जब ये सड़क 80 प्रतिशत् के आसपास कंप्लीट हो चुकी हैं, अब इसे चार्जशीट में डाला जा रहा है। यही चार्जशीट हम जिला शिमला के ऊपरी क्षेत्रों की जनता जनार्दन के बीच ले जाएंगे और बताएंगे कि किसी तरह के दोहरे मापदण्ड भारतीय जनता पार्टी के हैं। मुझे याद है, वर्ष 2014 के फरवरी में सी0एण्ड सी0 कंपनी को यह कार्य दिया गया था और

15/03/2017/1500/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

6-7 महीने के अंदर ही वहां पर सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया गया। एक राजनैतिक रूप से इस मामले को तूल देने के लिए, इसे नाटक भी कहा जा सकता है और आज जब यह कार्य मुकम्मल हो चुका है, आज इसे चार्जशीट में डालने की बात कही जा रही है।

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

15/03/2017/1505/ एन0एस0/ए0एस0 /1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रोहित ठाकुर) ----- जारी

पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 36,000 किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार हुई हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश विकास के रास्ते में कितना आगे बढ़ा है। मात्र 288 किलोमीटर तक की सड़क किसी समय में हिमाचल प्रदेश में हुआ करती थी। आज इसकी लैन्थ लगभग 36,000 किलोमीटर हो गई है। यह हमारी प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। इसी तरह बागवानी क्षेत्र हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है, इसके लिए लगभग 1134 करोड़ रूपये का प्रोजैक्ट वर्ल्ड बैंक ऐडिड प्रदेश को मिला है। मैं समझता हूं कि यह प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमैंट है। इसके लिए मैं सरकार, माननीय मुख्य मंत्री और बागवानी मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। आज इस मान्य सदन में वायरस की बात आई है। मैं माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और वे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं तथा उन्होंने एक परिपक्व राजनीतिज्ञ की तरह यह बात कही कि जिस बात की मुझे जानकारी नहीं है, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार बागवानी के क्षेत्र में नये-नये आयाम स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। हमारा विदेशों से लगभग 2.23 लाख रूपये का इम्पोरटिड प्लांटिंग मैटीरियल आना एक बहुत बड़ी अचीवमैंट है। अगर हम पिछली सरकार यानि भाजपा की बात करें मात्र 10,000 के आसपास इम्पोरटिड प्लांटिंग मैटीरियल विदेशों से आया था। लेकिन आज यह संख्या लाखों में पहुंच गई है। हमारे विपक्ष के साथियों को इस बात को सराहना चाहिए था लेकिन वे राजनीति से प्रेरित हो करके उन्हें इसमें वायरस नज़र आ रहा है। मेरे पास Ministry of Agriculture जो केंद्र सरकार के अधीन है, उनके कागज़ात हैं। इसमें सही तरीके से सारे प्रोसीज़र को अडॉप्ट किया गया है चाहे उसमें मुम्बई की बात हो या फिर परवाणू की बात हो। आज मैं समझता हूं कि इस तरह की राजनीति से प्रेरित हो करके इन मामलों को तूल देना न तो प्रदेश हित में है और न ही किसानों और बागवानों के हित में है। माननीय धूमल साहब ने इस मान्य सदन में सी.एस.स्टोर की बात कही है। आज जितने भी

15/03/2017/1505/ एन0एस0/ए0एस0 /2

सी.एस.स्टोर हिमाचल प्रदेश में हैं इसका श्रेय भी कांग्रेस पार्टी को जाता है। यहां पर माननीय धर्माणी जी ने भी इस बारे में अपनी बात रखी है। हेपटा के माध्यम से जब केंद्र में यू.पी.ए. सरकार थी और माननीय आनन्द जी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर थे, उस वक्त लगभग 37 करोड़ के आसपास एच.पी.एम.सी. को राशि दी गई थी, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में एग्जिस्टिंग कोल्ड स्टोर्ज़ को contorlled atomospheric के रूप में स्तरोन्नत किया गया था। पूरे हिमाचल प्रदेश में चाहे वह गुम्मा हो, जरोल हो या फिर पतली कूहल की बात हो, जितना भी एग्जिस्टिंग एच.पी.एम.सी. का स्ट्रक्चर था उसको अपग्रेड करने के लिए कोई 11 योजनाएं यू.पी.ए. सरकार ने स्वीकृत की थीं। यह एक खेद का विषय है कि जब से केंद्र में हमारे अच्छे दिन आए हैं हमारे तीन कोल्ड स्टोर्ज़ जो अन्तिम चरण में पहुंच चुके थे और जिनकी लागत लगभग 16 करोड़ के आसपास थी उनका एम.ओ.यू. निरस्त किया गया है। हालांकि उसमें जो शेयर प्रदेश सरकार या एच.पी.एम.सी. के माध्यम से दिया जाना था वे सारी औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी थी लेकिन उसके बावजूद भी उसे निरस्त कर दिया गया। भेदभाव का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? हमारी केंद्र की सरकार ने किसानों और बागवानों के साथ एक कुठाराघात किया है। इसी तरह से मंडियों के निर्माण की बात भी इस मान्य सदन में आयी है। यहां पर एक इम्प्रेशन देने का प्रयास किया गया है कि मंडियां सिर्फ भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान बनी हैं। हालांकि, तथ्य इसके विपरीत हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र जुब्बल-कोटखाई की बात करता हूं। आज हमारे अणु में लगभग 6 करोड़ की लागत से मंडी का निर्माण हो रहा है और हमारा हर सम्भव प्रयास रहेगा कि सेब सीज़न से पहले यह कार्य मुकम्मल हो और हम किसानों और बागवानों को इस मंडी को समर्पित कर सकें। पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 20 के आसपास मंडियों का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। इसमें से कई तो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें आपके माध्यम से इस मान्य सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है। इसी तरह से यहां पर इम्पोरट डयूटी की बात कही गई है। मुझे याद है कि वर्ष 2014 में जब पूरे भारत वर्ष में चुनाव का कार्यक्रम चला हुआ था तब भी सोलन में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

15/03/2017/1510/RKS/DC/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री रोहित ठाकुर) .....जारी

उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित उम्मीदवार रखा गया था। एक बड़ी जनसभा में उन्होंने सेब की इम्पोर्ट ड्यूटि को तीन गुना बढ़ाने की बात कही थी। वर्ष 2014 के बाद लगभग तीन सेब सीज़न निकल चुके हैं, इम्पोर्ट ड्यूटि बढ़ाना तो दूर की बात है, रिकॉर्ड तोड़ इम्पोर्टिड सेब आयात किया जा रहा है। जो प्रण उन्होंने लिया था उसके विपरीत केन्द्र की 'मोदी सरकार' ने कार्य किया है। यहां पर भेदभाव की बात आई। केन्द्र द्वारा प्रदेश सरकार को सौगात देने की बात आई। हमारा सबसे महत्वपूर्ण विभाग, आई.पी.एच. विभाग है। NRDWP (नेशनल रुरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम) के माध्यम से लगभग 80-90 प्रतिशत आई.पी.एच. डिपार्टमैंट के कार्य चलते हैं। मैं तीनों वर्षों का विश्लेषण कर रहा था। चाहे वह हमारी केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार थी, चाहे वर्तमान में एन.डी.ए. सरकार है, लगभग 100 करोड़ रुपये के आसपास की कम राशि हमारे प्रदेश को दी गई है। हमारे बहुत से कार्य जो NRDWP के तहत पूरे प्रदेश में चल रहे थे, आज वे अधर में लटके हुए हैं। यह कहा जाता है कि बहुत सा पैसा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को दिया जा रहा है। पानी तो हमें पिला नहीं रहे हैं, बाकी बातें तो दूर की है। इसी तरह सिंचाई भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब केन्द्र में यू.पी.ए. सरकार थी तो सिंचाई के लिए रिकॉर्ड तोड़ पैसा दिया गया। चाहे प्रदेश में धूमल जी की सरकार थी या माननीय मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी। लेकिन जब से केन्द्र में बी.जे.पी/एन.डी.ए. की सरकार बनी है लगभग 1900 करोड़ रुपये के आसपास की डी.पी.आर्ज. केन्द्र में लम्बित पड़ी हुई हैं। यह भी वर्तमान केन्द्र सरकार की सोच को दर्शाता है। इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्ट्रैंथनिंग के लिए हर सम्भव प्रयास किया है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो विधायक निधि मात्र 25 लाख रुपये हुआ करती थी, अपने चुनावी वर्ष में उसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया था। आज यह राशि बढ़ाकर लगभग 1.10 करोड़ के आसपास की गई है। हमारे सभी

प्रतिनिधि चाहे वे भाजपा के प्रतिनिधि हो या कांग्रेस के प्रतिनिधि हो या फिर हमारे निर्दलीय सदस्य हों, माननीय मुख्य मंत्री जी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। 14वें वित्तायोग से हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधियों को क्षति हुई थी। इसमें जिला परिषद मैंबर्स, बी.डी.सी. मैंबर्स को जो फंड्स मिला करते थे, उसमें भारी कटौती कर दी

15/03/2017/1510/RKS/DC/2

गई थी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसके लिए लगभग 42 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। पंचायती राज ग्रासरूट की एक पार्लियामैंट होती है। उसका भी सशक्तिकरण किया गया। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी पिछेले 4 वर्षों में अभुतपूर्व विकास हुआ है। यू.पी.ए. सरकार के दौरान प्रदेश को 3-3 मैडिकल कॉलेज मिले। नेरचौक में ई.एस.आई. मैडिकल कॉलेज इसके अतिरिक्त मिला। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इन्हीं चार वर्षों के दौरान लगभग 500 से अधिक डॉक्टर्ज की पोस्टें क्रिएट हुई। अगर हम भाजपा सरकार के कार्यकाल की तुलना करें तो इन्होंने जो 19 प्राइमरी हैल्थ सैंटर खोले थे उनके लिए पोस्टें सृजित नहीं की गई थी। एक उदाहरण मैं अपने चुनाव क्षेत्र का भी देना चाहूंगा। पूरे 5 वर्ष में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल जर्जर हालत में रही। लेकिन जब वर्ष 2012 के अंत में चुनाव का समय घोषित होने की तैयारियां थी तो सितम्बर माह में कोई 3-4 हफ्ते के लिए आई.जी.एम.सी. शिमला से सिविल हॉस्पिटल जुब्बल जोकि हमारे चुनाव क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्टिपटल है, 6-7 स्पैशलिस्ट डॉक्टर नियुक्त कर दिए गए। उन डॉक्टरों की नियुक्तियां वोटिंग के एक दिन बाद तक की गई थी। मात्र 3-4 हफ्ते के लिए वे डॉकटर्ज वहां पर नियुक्त किए गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे चुनाव क्षेत्र में उस समय बहुत सी समस्याएं रही। क्योंकि उस वक्त ठियोग-खड़ापत्थर-हाटकोटी रोड़ की हालत भी बहुत खराब थी। सिविल हॉस्पिटल, जुब्बल में 3-4 हफ्ते के लिए आई.जी.एम.सी. के डॉक्टर्ज रखे थे और काउंटिंग के एक दिन बाद उन्हें वापिस रिपोर्ट करना था। इस तरह की बातें पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई है। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश का और हर क्षेत्र का विकास करने की वचनबद्धता को दोहराया है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 मार्च, 2017 को जो यह बजट अनुमान इस माननीय सदन में रखे हैं, मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

15.03.2017/1515/SLS-DC-1

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य डॉ0 राजीव सैजल जी चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ0 राजीव सैजल : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस सदन में जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए, मैं उस पर अपने विचार रखने क लिए खड़ा हुआ हूं।

निश्चित तौर पर माननीय मुख्य मंत्री जी की स्पीच बहुत लंबी रही। यह साढ़े चार घंटे लंबी थी। परंतु इतने लंबे समय में जो बजट यहां पर रखा गया; जो बातें कही गईं, मुझे लगता है कि उनमें बहुत ज्यादा कुछ प्रदेश के लिए नहीं था। यह बात ठीक है कि आंकडों के द्वारा, लुभावने आंकड़ों के द्वारा इस बजट को सजाया गया और शेरो-शायरी के द्वारा भी इसको सजाने का प्रयास हुआ। मैं समझता हूं, ये बजट वैसा ही है जैसे किसी जर्जर भवन को पेंट करके, उसको बाहर से सजाकर यह प्रस्तुत करने की कोशिश की जाए कि घर बहुत अच्छा है; घर बहुत बढ़िया है।

हमारी तरफ से जो अधिकांश लोग बोले हैं, तकरीबन सभी ने चिंता व्यक्त की है, और मैं स्वयं को भी उस चिंता में शामिल करता हूं, कि कर्ज़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट स्पीच में 'विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन', ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द इस्तेमाल करने का कोई औचित्य ही नहीं है क्योंकि अगर आज प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन हो रहा है तो वह ऋण के द्वारा हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी कई बार कह भी चुके हैं कि मैं इस सरकार को जुगाड़ के द्वारा चला रहा हूं। अच्छा होता, अगर मौजूदा संसाधनों से ही न्यूनतम ऋण लेकर प्रबंधन किया होता तो यह

हमारी आज की पीढ़ी के लिए भी अच्छा होता और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी अच्छा होता।

सड़कों की स्थिति प्रदेश में, और अगर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं, तो बहुत खराब है। चाहे वह प्लानिंग की मीटिंग हो, चाहे विधान सभा की बात हो, हमने बार-बार इस बात को रखा है और बार-बार उठाया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 2012 से लेकर अब तक जो प्राथमिकताएं मैंने सड़कों को लेकर दी थीं, बड़े दुःख से

15.03.2017/1515/SLS-DC-2

कहना पड़ता है और हमारे अधिकांश विधायकों ने यह बात यहां पर कही है कि उनकी डी.पी.आर्ज़. नहीं बन पाईं हैं। अब माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि आप हमें पत्र नहीं लिखते और मिलते नहीं हैं जबकि व्यक्तिगत तौर पर वर्ष 2013 से लेकर आज तक जितनी भी प्लानिंग की मीटिंग हुई हैं, उनमें हमने बार-बार माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया है कि हमारे चुनाव क्षेत्र की जो हमने सड़कों के लिए प्राथमिकताएं दी हैं, भवनों के लिए प्राथमिकताएं दी हैं, उनकी डी.पी.आर्ज़. तैयार की जाएं। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने तो माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था कि अगर इसमें कहीं अधिकारियों की ओर से कोई ढिलाई है, कोई कमी है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई हो, उनको कोई निर्देश गए हों, ऐसा लगता नहीं है।

मैं यहां पर भोजनगर से मल्ला सड़क का मैंशन करना चाहूंगा। शायद 2010 से इसका काम चला हुआ है लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सड़क की टारिंग एक बार ज्यादातर हो चुकी थी लेकिन वह अधिकांश टारिंग उखड़ चुकी है और इस रोड की स्थिति आज किसी कच्चे रोड से भी खराब है। कच्चे रोड भी इस पक्की सड़क से अच्छे होते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि इसमें काफी धांधली हुई है।

जारी ...श्री गर्ग जी द्वारा

15/03/2017/1520/RG/DC/1

डॉ. राजीव सैजल---जारी

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि इसमें काफी धांधली हुई है और इस सड़क का निर्माण कार्य जब से शुरू हुआ, वह ठीक प्रकार से नहीं हुआ। जैसे ही यह सड़क पक्की हुई, उसके बाद यह सड़क उखड़ गई, तो क्या जिसने इसका काम किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? या ऐसे ही चलता रहेगा और लोगों का पैसा ऐसे ही व्यर्थ होता रहेगा और लोग परेशान होते रहेंगे? मुझे लगता है कि इसमें कोई कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसा न हो। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में अनेकों स्कूल अपग्रेड किए। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी काफी स्कूल इन्होंने अपग्रेड किए जिसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। परन्तु ये जो अपग्रेड हुए स्कूल हैं और मेरे चुनाव क्षेत्र में जो ज्यादातर दस जमा दो स्कूल हैं वहां अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। अब लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि अध्यापकों की व्यवस्था करो, लेकिन अब विभाग तो मुख्य मंत्री महोदय के पास है, व्यवस्था इनको करनी है। स्कूल अपग्रेड करने से ही शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा। अगर हम गुणवत्तायुक्त शिक्षा की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अध्यापकों के पद तो भरे जाने चाहिए और स्कूलों में अध्यापक तो होने चाहिए, बिना अध्यापक के कैसे काम चलेगा? महाविद्यालय, धर्मपुर जोकि माननीय धूमल जी ने पिछली सरकार में मेरे चुनाव क्षेत्र को दिया था और जब नई सरकार सत्ता में आई, तो उस महाविद्यालय को बंद कर दिया गया। जब हमने उनको पूछा, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि दो कमरों में कॉलेज नहीं चलते। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आज भी उन्हीं दो कमरों में वह कॉलेज चला हुआ है जिसको इन्होंने उस आधार पर बंद कर दिया था कि उसकी बिल्डिंग नहीं थी और दो कमरों में वह कॉलेज चल रहा था। इस सरकार का कार्यकाल पूर्ण होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक उस कॉलेज का भवन बन नहीं पाया और बच्चे बहुत समस्या वहां झेल रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिमला और कांगड़ा में सॉफ्टवेयर टैक्नॉलॉजी पार्क स्थापित करने की बात की है। मुझे लगता है कि कांगड़ा और शिमला दोनों स्थानों का इसमें ध्यान रखा गया है। लेकिन सोलन जिला जो सबसे ज्यादा राजस्व प्रदेश को देता है और नालागढ़, बद्दी, परवाणु ये ऐसे तीन महत्वपूर्ण कस्बें हैं जहां हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उद्योग हैं।

15/03/2017/1520/RG/DC/2

यहां पर भी ऐसा टैक्नॉलॉजी पार्क हो सकता था, लेकिन ऐसी कोई घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि वे ऐसा कुछ मेरे चुनाव क्षेत्र में भी करने का प्रयास करें। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में पॉली हॉऊस निर्माण हेतु मात्र 15 करोड़ रुपये, किसानों के लिए क्रेट्स हेतु मात्र दो करोड़ रुपये का प्रावधान, कीवी फलोत्पादन हेतु प्रोत्साहन और पौध व लोहे के एंगल हेतु मात्र चार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मेरा कहना यह है कि यह इतनी कम राशि का प्रावधान किया गया है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। माननीय उपाध्यक्ष जी, नशे का कारोबार हमारे प्रदेश के लिए बहुत चिन्ता का विषय है और मैं समझता हूं कि पूरे देश में हमारा प्रदेश एक अनूठा प्रदेश है। चाहे वह हमारे स्वभाव या संस्कृति की बात हो। स्वभाव और संस्कृति के कारण ही हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रदेश के रूप में डॉ. वाई.एस. परमार के प्रयासों से अस्तित्व में आया। लेकिन काफी बुराइयां हमारे पड़ौसी राज्यों से यहां आ रही हैं। उसमें नशे की प्रवृत्ति मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बुराई है। आज स्कूलों के इर्द-गिर्द जितने यहां प्राईवेट कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं मुझे लगता है कि नशे के कारोबार का एक जाल सा बिछता जा रहा है। जो बहुत चिन्ता का विषय है और इस दिशा में सरकार की ओर से कोई बहुत ज्यादा सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं ताकि हमारा प्रदेश नशे के जंजाल से मुक्त हो और हमारे बच्चे भी बच सकें और इस प्रदेश का भविष्य खतरे में न पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन की दृष्टि से इस बजट में कोई बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं किया गया है। पर्यटन भी हमारे प्रदेश में इनकम का एक अच्छा साधन बन सकता है। प्रदेश

में जो हमारे बेरोजगार युवक हैं अब जब सरकार का कार्यकाल पूरा होने का आया है, तब सरकार ने भी बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है,

एम.एस. द्वारा जारी

15/03/2017/1525/MS/AS/1

डॉ0 राजीव सैजल जारी-------

तो क्यों न पर्यटन को हम यहां पर इतना विकसित करें ताकि हमारा जो बेरोज़गार नौजवान है वह इसमें अपना रोज़गार पा सके। ऐसा कुछ इस बजट में नहीं है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी कोई बहुत ज्यादा करने का संकल्प इस बजट में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद और पर्यटन, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रदेश की आर्थिकी को बदल सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ इस बजट में नहीं है। इस बजट बुक में माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी शेरो-शायरी की है और इसमें लिखे एक शेर का मैं उल्लेख करना चाहूंगाः

अपनी उलझनों में ही, अपनी मुश्किलों के हल मिलते हैं।
जैसे टेढ़ी-मेढ़ी शाखाओं पर ही, रसीले फल मिलते हैं।

मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार में दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी वह है जो उलझनों, मुश्किलों और चुनौतियों में है और दूसरी कैटेगरी वह है जो रसीले फलों का उपभोग कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं। मेरा उपाध्यक्ष जी आपके माध्यम से सम्माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि ये जो रसीले फल खाने वाले लोग हैं, इन पर चैक हो और इनके ऊपर कोई रोक लगे। जो अच्छे लोग हैं उनको आगे प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि हमारा यह प्रदेश अच्छा हो। अंत में मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस बजट में ऐसा कुछ है जिसका मैं समर्थन कर सकूं। अतः मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

15/03/2017/1525/MS/AS/2

उपाध्यक्षः अब चर्चा में मुख्य संसदीय सचिव श्री मनसा राम जी भाग लेंगे।

श्री मनसा राम (मुख्य संसदीय सचिव):उपाध्यक्ष जी, बजट पर चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष जी, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हैं। जो विपक्ष है वह पक्ष के लिए कुछ-न-कुछ बोलता रहता है लेकिन हमें गर्व है कि श्री वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के नव-निर्माता है। मुझे करसोग की जनता ने इस विधान सभा में आने का मौका दिया और वर्ष 1967 में मैं इस विधान सभा में पहली बार आया। वर्ष 1972 में मुझे डॉ0 वाई0एस0 परमार जी ने अपने मंत्रि-मण्डल में शामिल किया। उस जमाने में मैं मण्डी जिला से एक ही मंत्री होता था अब तो वहां से काफी सारे हैं। मुझे खुशी है कि यह बहुत ही बढ़िया बजट है क्योंकि मैंने बहुत बजट देखे हैं। विपक्ष तो अपना कर्त्तव्य निभा रहा है कि इस बजट के बारे में भी आप संतोष नहीं रख रहे हैं लेकिन यह बहुत बढ़िया बजट है। मैंने सारी बजट की किताब पढ़ी है। मैं तो कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को हिमाचल प्रदेश के सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। जब ये किसी मुश्किल में आते हैं तो देवी-देवता स्वयं प्रकट हो जाते हैं। साढ़े चार घण्टे इस उम्र में कोई आदमी खड़े होकर भाषण नहीं दे सकता है। इनको देव शक्ति प्राप्त है। आप जितना मर्जी नाराज होते रहो, जो मर्जी करते रहो लेकिन जो सेवा इन्होंने हिमाचल प्रदेश के गरीबों, हिमाचल प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के लोगों और देवी-देवताओं का जो हिमाचल प्रदेश में इन्होंने मान बढ़ाया है, जो सारे प्रदेश में इन्होंने मंदिरों का निर्माण किया है, वह ऐसी शक्ति है कि इनसे जो मर्जी नाराज हो लेकिन इनको आशीर्वाद मिलता है। हमें गर्व है कि हिमाचल प्रदेश को एक ऐसे मुख्य मंत्री प्राप्त हुए हैं जो दिन-रात हिमाचल प्रदेश के गरीबों और हिमाचल प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। हमने बहुत से मुख्य मंत्री देखे हैं। उपाध्यक्ष जी, मैंने 4-5 मुख्य मंत्रियों के साथ काम किया है लेकिन जिस तरह से ये परिश्रम करते हैं, डॉ0 वाई0एस0 परमार के बाद इस प्रदेश में ऐसा कोई मुख्य मंत्री नहीं आया जो इनके मुकाबले में काम

करे। हमें गर्व है कि हमें इनका नेतृत्व मिला है। यह इतना बढ़िया बजट है कि यदि मैं इस सारे बजट का

15/03/2017/1525/MS/AS/3

बखान करूं तो मुझे भी साढ़े चार घण्टे लगेंगे लेकिन मैं साढ़े चार घण्टे तक खड़ा नहीं रह सकता। मैं चाहे मुख्य मंत्री जी से छोटा हूं लेकिन मैं एक घण्टा भी खड़ा नहीं रह सकता। वास्तव में इनको देव-शक्ति प्राप्त है और यह हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए गौरव की बात है। उपाध्यक्ष जी, मैं इन पंक्तियों के साथः-

खुशहाल होगा हिमाचल, आधुनिक निर्माता श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में, बहारें लाएगा बजट मुख्य मंत्री जी के कठिन परिश्रम में।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

15.03.2017/1530/जेके/डी0सी0/1

मुख्य संसदीय सचिव (मनसा राम):------**जारी**-----

इन्होंने बहुत परिश्रम किया है। उस परिश्रम से ही इतना बढ़िया बजट तैयार हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बजट में प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका इसमें वर्णन नहीं है और जिसको इससे फायदा न हो, चाहे माननीय सदन के सदस्य ही क्यों न हो? आप लोगों को भी इन्हीं मुख्य मंत्री ने इतना पैसा दिया है, पहले क्यों नहीं मिलता था? आपको इस बात का एहसान नहीं है लेकिन चाहे विधायक हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो , चाहे प्रदेश का कोई भी आदमी हो ये उसके हित में सोचते हैं। इसलिए जब विधान सभा में चुनकर बी0डी0सी0 के मैम्बर आए थे और जो जिला परिषद के मैम्बर आए थे तो भारत सरकार को भी क्या मुश्किल थी? वे भी उनके लिए कुछ देते। लेकिन वे दे नहीं पाए। उनको भी श्री वीरभद्र सिंह जी की दया से सब कुछ मिला है। वे लोग परेशान थे

क्योंकि वे चुने हुए लोग थे। वे सभी परेशान थे। उनको भी इन्होंने खुश किया। इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। मैं तो यह कहूंगा कि गरीब लोगों के आर्शीवाद से और भगवान की कृपा से इनकी उम्र लम्बी हो, इनका भविष्य उज्जवल हो और इनको हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक काम करने की भगवान शक्ति दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं करसोग चुनाव क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि 1200 करोड़ रूपए का बकाया, जो कि गरीब लोगों का पैसा है, जिन्होंने मज़दूरी का काम किया है, उनका वह पैसा है और कुछ ऐसे ठेकेदार भी हैं । वह 1200 करोड़ रूपया पीछे नहीं दिया गया इसलिए करसोग की सारी सड़कों के काम ठप्प हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान करसोग विधान सभा क्षेत्र की ओर खींचना चाहता हूं। वैसे तो मैं मुख्य मंत्री जी से इस बारे में हमेशा बोलता रहता हूं लेकिन मैं यहां पर भी बोल रहा हूं और इसलिए भी बोल रहा हूं कि करसोग में लोग कहते होंगे कि मैं चुपके से मुख्य मंत्री जी से बात करता हूं। अब बोल रहा हूं तो खुल के बोल रहा हूं और मीडिया वाले भी लिखेंगे कि मनसा राम ने मांग की कि मज़दूरों को पैसा मिलना चाहिए। जो छोटे ठेकेदार हैं इनके लिए

15.03.2017/1530/जेके/डी0सी0/2

छोटे टेंडर नहीं लगाते और इनको काफी मुश्किल आती है। जो बड़े-बड़े ठेकेदार हैं उनको तो बड़े- बड़े टेंडर लगते हैं। उनमें से कुछ तो काम करते हैं लेकिन कुछ काम भी नहीं करते । करसोग की सड़कों के काम को करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी हम पर कृपा रख रहे हैं लेकिन फिर भी सड़कों का काम वहां कछुआ चाल से चला है। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि करसोग की तरफ भी ये अपना ध्यान ले जाएं और उसके लिए मैं इनका बहुत आभारी रहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, ये जब करसोग आए थे तो लोगों ने मांग की कि करसोग ऐसा क्षेत्र है जो शिमला से 120 किलोमीटर दूर है, मण्डी से 122 किलोमीटर पड़ता है और हम बीच में हैं। मण्डी की तरफ से जिले के लोग हैं, वहां तो उनका ध्यान रहता है लेकिन हम इंटीरियर में रहते हैं, हमारी तरफ कम ध्यान जाता है। मुख्य मंत्री जी कई बार वहां

आए हैं। एक बार इंदिरा गांधी जी भी करसोग में आई थी। तब कॉलेज ग्राऊंड में हेलिकॉप्टर उतरता था। अब कोई भी वी0वी0आई0पी0 यदि करसोग आए तो उन्हें या तो सुन्नी से बाई रोड़ आना पड़ेगा या सुन्दरनगर से आना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, लोगों की मांग है और माननीय मुख्य मंत्री जी को करसोग के लोगों ने करसोग में भी बोला है और फिर वहां पर कार्रवाई भी शुरू हुई है। मैं इनसे प्रार्थना करता हूं कि मैंने अभी इनको करसोग ले जाना है लेकिन अभी तो इनको बाई रोड़ ही जाना पड़ेगा लेकिन हम चाहते हैा कि कभी न कभी तो वहां पर हेलिकॉप्टर उतरे । वहां पर एक कुन्नो नाम की जगह है। वह बहुत ही सुन्दर जगह है, जो कि कामाक्षा माता के निकट है और करसोग के भी निकट है। वह बहुत बढ़िया ग्राऊंड है। उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी हमारी मदद करेंगे कि वहां पर हेलिपैड हो। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि करसोग में बहुत ज्यादा देवी-देवता हैं। बड़योगी देव है जिनको द्रोणाचार्य कहा जाता है। माँहूनाग जिनका राजा कर्ण कहा जाता है। कामाक्षा माता मन्दिर, ममलेश्वर महादेव मन्दिर, महामाया पांगणा मन्दिर, चिंडी माता मन्दिर, तत्तापानी में झील, होटल्ज और पर्यटन की दृष्टि से इनका विकास होना चाहिए, ऐसी लोगों की मांग है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने तत्तापानी का नक्शा बदला है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

15.03.2017/1535/SS-AS/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री मनसा राम) क्रमागतः

और वहां पर लोग इतने प्रसन्न हुए हैं कि इनकी दीर्घ आयु और उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। तत्तापानी एक बहुत पुराना तीर्थ स्थान है। जगदम्नी ऋषि ने वहां पर पूजा की थी। उनके तप और शक्ति से वहां पर गर्म पानी के चश्मे फूटे थे। लेकिन जब कौल डैम में बहुत बड़ी झील बनी तो वे चश्मे गुम हो गए। क्योंकि वह गरीबों का हरिद्वार है, इसलिए गांव के लोग बड़े परेशान हुए। वे वहां नहाते थे और तीर्थ पर जाने की आदत थी। लेकिन

माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से उन्होंने बड़ी तेज़ गति से चश्मे को ऊपर उठाया और बड़ा अच्छा गर्म पानी लोगों को नहाने को मिला। इस बार भी वहां बहुत लोग नहाये। लोग इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इनको शक्ति मिले और इनकी उम्र लम्बी हो।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर तो काफी सदस्यों ने बोल दिया। मैं तो अब अपना ही रोना रोऊंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि करसोग टूअर पर इन्होंने मुझको पॉलिटेक्निक कॉलेज देने के लिए आशीर्वाद दिया और इसको शुरू करने के लिए 220 करोड़ रुपया इस डिपार्टमैंट को दिया है जहां-जहां ये काम शुरू होने होंगे। उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं, उसके लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण आशा है कि मेरा यह काम पूरा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, चिंडी एक स्थान है जहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सब्जी मण्डी की स्थापना की। हमें खुशी है कि वहां पर सेब और सब्जियां इतनी बिकती हैं कि जो दिल्ली में रेट मिलते हैं वही यहां मिलते हैं। लोग इतने खुश हुए कि वे भी इनके लिए भगवान् से प्रार्थना करते हैं। इन्होंने चिंडी माता के पास जो एक सब्जी मण्डी का काम चलाया, उसमें बहुत बढ़िया बिक्री भी हुई है और लोग उससे प्रसन्न भी हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती विद्या स्टोक्स जब करसोग आईं तो इन्होंने वहां पर इमला-बिमला खड्डों के लिए पैसा देने की घोषणा की। तो लोगों ने इनका नाम वहां जल देवी रख दिया। करसोग में इन दोनों खड्डों में इतना पानी था कि सिंचाई का काम खत्म हो गया था क्योंकि नदियां सूख गई थीं। लेकिन अब जब इसका चैनेलाइजेशन होगा तो सारे किसानों को पानी मिलेगा और उनका भविष्य बदलेगा। इसलिए ये भी बधाई की पात्र हैं।

15.03.2017/1535/SS-AS/2

माननीय मुख्य मंत्री जी जब करसोग आए थे तो इन्होंने आई0पी0एच0 की 76 करोड़ की स्कीमों का शिलान्यास किया था। आपने बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता और युवकों को कौशल विकास भत्ता दिया है और सब गरीब लोगों की मदद की है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि इनकी हमेशा मुझ पर कृपा रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

15.03.2017/1535/SS-AS/3

उपाध्यक्षः अब श्री बलदेव सिंह तोमर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलदेव सिंह तोमरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, 10 मार्च को जो माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उस पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने साढ़े चार घंटे जो बजट भाषण यहां पढ़ा उस पर सभी लोगों की मेजरिंग थी कि शायद इस बार का बजट चुनावी वर्ष का बजट है और प्रदेश के सभी वर्गों को कुछ-न-कुछ मिलेगा। लेकिन प्रदेश की जनता को मात्र इसमें निराशा ही हाथ लगी है। बजट में पहला वाक्या लिखा गया है कि पूरा हिमाचल प्रदेश बाह्य शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया है। 28 अक्तूबर, 2016 को केन्द्रीय मंत्री को बुलाकर इसकी घोषणा भी करवा दी गई। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप मेरे विधान सभा क्षेत्र में आईये या किसी को वहां पर भेजिये

जारी श्रीमती ए0वी0

15.3.2017/1540/av/as/1

श्री बलदेव सिंह तोमर---------- जारी

मेरे विधान सभा क्षेत्र में 48 पंचायतें पड़ती है। उनमें से अगर एक पंचायत भी पूरी शौच मुक्त है तो बता दें। पंचायत की बात तो आप दूर रखें अगर पूरे क्षेत्र में एक भी गांव ऐसा हो कि जो पूरी तरह शोच मुक्त हुआ है तो आप बताएं। इस बजट बुक में इस तरह के झूठे आंकड़े दिए गए हैं। दूसरी बात कही गई कि हमने प्रदेश में बहुत सारे संस्थान खोले हैं। हम

उन संस्थानों को खोलने का स्वागत करते हैं। सब-तहसीलों को तहसील का दर्जा दिया गया। कुछ सब-तहसीलें और एस0डी0एम0 कार्यालय खोले गए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक सब-तहसील को तहसील का दर्जा दिया गया। उस तहसील को बने लगभग 6 महीने का समय हो गया है लेकिन वहां पर अभी तक तहसीलदार नहीं आया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक और सब-तहसील रोनाट है और उस सब-तहसील में पिछले एक साल से कोई भी तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है और लोगों को शिलाई आना पड़ता है। उनको 100 रुपये से 500 रुपये तक किराये पर खर्च करना पड़ते हैं। आप ऐसे संस्थान खोलकर प्रदेश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? मात्र स्थानीय नेताओं के कहने पर जहां-जहां जनता खड़ी हो जाती है माननीय मुख्य मंत्री जी उनके कहने पर हर जगह कह देते हैं कि यह भी हो जायेगा और वह भी हो जायेगा। लेकिन उन संस्थानों का क्या फायदा? आपने स्कूल अपग्रेड किए तथा बहुत सारे कालेज भी बनाए। यहां पर लिखा गया है कि हमने प्रदेश के अंदर इतने नये कालेज बनाये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कफोटा में एक डिग्री कालेज खोला गया। वहां इस वक्त 113 बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पर हिन्दी और इंगलिश के मात्र अभी दो ही प्रोफैसर है। अब इन 113 बच्चों का इन दो सब्जैक्ट्स के सहारे क्या भविष्य होगा? दूसरा डिग्री कालेज शिलाई में है। वहां पर भी लगभग 6-7 पोस्टें प्रोफैसर की खाली पड़ी है। हमारे जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से पढ़कर आयेंगे आखिकार वे इस कम्पीटिशन के जमाने में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग कैसे लेंगे जब उनकी शिक्षा ही अच्छी नहीं होगी? वहां पर जब पढ़ाई करवाने

15.3.2017/1540/av/as/1

के लिए अध्यापक ही उपलब्ध नहीं होंगे। प्रदेश में बहुत सारे स्कूल अपग्रेड किए गए मगर आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 60 प्रतिशत स्कूलों में पूरे अध्यापक नहीं है। टी0जी0टी0 के पद खाली पड़े हैं लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार कह रही है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। हमारी प्रदेश सरकार समान विकास की बात करती है मगर कल हंस राज जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हमारे दूरदराज के क्षेत्र चाहे चम्बा के हैं या जिला

सिरमौर के हैं। उनके लिए कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद हिमाचल प्रदेश के नक्शे में ही नहीं है। हमारे क्षेत्रों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। एस0एम0सी0 से बहुत सारी भर्तियां की गई। उसके अंतर्गत जिला सिरमौर में भी आपने अपने बहुत सारे चहेतों को नौकरियां दी। एस0एम0सी0 के अंतर्गत सही अध्यापक का चयन नहीं किया जा रहा है। दसवें नम्बर पर आने वाले लड़के का चयन किया जाता है और पहले नम्बर या मैरिट पर आने वाले लड़के को नहीं लगाया जाता तो इससे पता चलता है कि हमारे स्कूलों में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है।

यहां पर कानून-व्यवस्था की बात भी कही गई कि प्रदेश सरकार ने राज्य में अच्छी कानून-व्यवस्था दी है। मैं उससे सम्बंधित एक उदाहरण अपने विधान सभा क्षेत्र का देना चाहता हूं। मेरी विधायक प्राथमिकता की आई0पी0एच0 की स्कीमें थी और हमारे क्षेत्र के बोर्ड के चेयरमैन वहां दो स्कीमों के शिलान्यास के लिए जा रहे थे। हमारे नौजवान और युवा मोर्चा के साथी वहां उनका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे। उन्होंने सड़क के किनारे खड़े होकर उनको काले झंडे दिखाने का निर्णय लिया था। माननीय चेयरमैन जी शिलान्यास करके चले गये। शिलान्यास के बाद रात को सात बजे थाने में जाते हैं और स्वयं तीन घंटे वहां पर बैठे रहते हैं तथा 21 लड़कों के ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज करवाते हैं। हम इस प्रदेश के अंदर ऐसी कानून-व्यवस्था दे रहे हैं। क्या हम लोकतंत्र के अंदर अपनी बात भी नहीं रख सकते? दूसरा उदाहरण यह है कि पांवटा साहब में मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक लड़के की दो-तीन लड़कों ने पिटाई करके उसकी गाड़ी तोड़ दी।

श्री वर्मा द्वारा जारी

15/03/2017/1545/टी0सी0वी0/ए0एस0/1
श्री बलदेल सिंह तोमर.... जारी।

वे थाने में गये, उसकी वाकायदा एम0एल0सी0 हुई। उसकी टांग में चोट थी और उसका दांत टूटा हुआ था। लेकिन आज तक वह एफ0आई0आर0 दर्ज़ नहीं हुई हैं, क्योंकि उसमें दूसरी पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं के बच्चे शामिल थे। ऐसी कानून व्यवस्था हम इस प्रदेश के अन्दर देना चाह रह हैं। यहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की गई कि हमने बहुत सारे डॉक्टर्ज़ इस प्रदेश के अंदर लगाये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सी0एच0सी0 और 6 पी0एच0सीज़ हैं और 27 हैल्थ सब-सेंटर्ज़ हैं। एक सी0एच0सी0 में मात्र एक डॉक्टर हैं। 6 पी0एच0सीज़ में से 2 में न कोई डॉक्टर हैं और न ही कोई स्टॉफ हैं। इनमें ताले लगे हुए हैं। हैल्थ सब-सेंटर 27 में से 17 जगह बिल्कुल खाली हैं और उस क्षेत्र के हारे हुए नेता हैं, जिन बिल्डिंग्ज़ को हमारी सरकार के समय में बजट मिला था और वे बनकर तैयार हो गई है, वे उनके उद्घाटन करने में मस्त हैं। वहां स्टॉफ की उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। आज ऐसा विकास हम इस प्रदेश में कर रहे हैं। प्रदेश में नोटबंदी के ऊपर इस बज़ट में लिखा है कि बिना किसी प्रबंधन के नोटबंदी देश के अंदर की गई। नोटबंदी का जवाब इस देश की जनता ने 11 तारीख और उससे पहले जो भी इस देश के अंदर चुनाव हुए है, उसके परिणाम के रूप में दे दिया है। आज इस देश के प्रधान मंत्री ने जिस तरह से देश में विकास की गति को आगे बढ़ाया है, उसका परिणाम इस देश की जनता ने दिया है। उनके लिए दो लाईनें में अर्ज़ करना चाहता हूंः

तेरी इस जीत के चर्चे अब सारे जहां हुए,

जो समझते थे, मसीहा खुद को वो अब बदनाम हुए।
तुने छू लिया है आसमान, जहां परिन्दें भी पहुंचने में नाकाम हुए।।

यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में जो लैंडलेस लोग हैं, उनके लिए 2-3 बिस्वा ज़मीन दे रहे हैं। पिछले दिनों मैंने विधान सभा के अंदर प्रश्न लगाया था, बजट में भी चर्चा की थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील कमरूऊ में एक श्माह गांव पड़ता है और उस गांव के नीचे कटाव लग गया और वह गांव गिरने

के कगार पर था। वहां पर सर्वे हुआ और उसके बाद इस माननीय सदन के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको भूमि देने की बात कही थी। जब माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे क्षेत्र में आये तब उन लोगों को भी वहां पर बुलाया गया और पट्टे के रूप में कागज़ उनको दिए गए, लेकिन उसके बाद एक साल से ऊपर का समय हो गया है, आज तक उन लोगों को न तो ज़मीन मिली है और न उनके रहने की व्यवस्था हुई है। अगली बरसात आने वाली है, उनका क्या होगा। वे इस बात से परेशान हैं कि हम अब आने वाली बरसात के मौसम में कहां जाएंगे? प्रदेश में मात्र ठगने के लिए लोगों को बुलाया जाता है। मेरे क्षेत्र में बिजली की बहुत ज्यादा समस्या हैं। यहां पर पांवटा साहिब के माननीय विधायक कह रहे थे कि पांवटा साहिब में 1000 पोल और 100 ट्रास्फार्मर आये। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारा जो इलैक्ट्रिसिटी/आई0पी0एच0 का डिविज़न है, वह पांवटा विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। जो सामान वहां पर आता है, वह पांवटा में खत्म हो जाता है। जब तक शिलाई का नम्बर आता है वह सामान खत्म हो जाता है। आज ऐसी परिस्थिति हमारे क्षेत्र में हैं कि बहुत पुराने-पुराने पोल लकड़ी के लगे हैं और कई बार घटना भी घट चुकी है। कई लोगों की मृत्यु करंट लगने से हो चुकी हैं। ट्रास्फार्मर की वज़ह से बिजली वहां पर कई-कई दिनों तक नहीं आती है। आज भी मुझे सुबह फोन आया था कि कोटा-बाग गांव में पिछले 15 दिन से लाईट नहीं हैं। कल मैं रेणुका विधान सभा क्षेत्र की ख़बर पड़ रहा था, संगड़ाह में 3 दिनों से 3 पंचायतों में लाईट ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति आज हमारे जिला के अंदर हो गई है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया इस तरह के क्षेत्रों की ओर भी ध्यान दें। माननीय उद्योग मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। हमारे यहां आधे क्षेत्र में खन्न का कार्य होता हैं, वहां पर लाइम स्टोन की माइन्ज हैं। लेकिन पिछले 4 साल से उस एरिया में माइन्ज़ के क्षेत्र में ग्रहण लगा हुआ है।

श्रीमती एन0एस0 .... द्वारा जारी ।

15/03/2017/1550/ एन0एस0/डी0सी0 /1

श्री बलदेव सिंह तोमर ----- जारी

11 माइन्ज़ ऐसी हैं जो रिन्यूबल के लिए थीं और बंद होने के कगार पर थीं। यह पहले माइनर मिनरल्ज़ में थी। इन्होंने रिन्यूबल के लिए अप्लाई किया और प्रदेश सरकार ने उनको लैटर ऑफ इनडैंट दे दी। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश सरकार ने यह नहीं देखा कि उससे पहले केंद्र सरकार का खनन के ऊपर एक कानून आया है। माननीय मोदी जी ने रिन्यूबल का चक्कर खत्म करने के लिए जो मेज़र माइन्ज़ थी उनको 50 साल के लिए रिन्यू कर दिया है। 50 साल तक उनको रिन्यूबल की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश सरकार ने इस ऑर्डर के आने के बाद कुछ माइन्ज़ रिन्यू कर दीं लेकिन उस कानून के लागू होने से वे उसको इम्पलीमैंट नहीं कर पाये। प्रदेश सरकार ने उनको कहा कि केंद्र सरकार से बात कीजिए। जब वे केंद्र सरकार के पास गए तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर के बाद आपको रिन्यूबल मिली है। इसकी वजह से आज वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है। सैंकड़ों ट्रक्स सड़कों पर खड़े हैं। उसमें जो ड्राईवर्ज़ और कंडक्टर्ज़ थे, वे बेरोजगारी के कगार पर खड़े हो गए हैं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष यह विषय प्लानिंग की बैठक में भी उठाया था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां पर कहा था कि एक घंटें के अंदर फाईल आप मेरे टेबल पर लाईए। आज इतना समय बीत गया है लेकिन फिर भी वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस विषय में कोई-न-कोई निर्णय अवश्य लें। इस बजट में बेरोजगारी भत्ते की भी बात आई है और इस मान्य सदन में उसकी चर्चा भी हो रही है। वर्ष 2003 में जब विधान सभा के चुनाव हुए थे तब इन्होंने (कांग्रेस) प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा शिगुफा छोड़ा था कि हम हर परिवार को रोजगार देंगे। उस समय भी नौजवानों को ठगा गया। इनकी (कांग्रेस) सरकार आई लेकिन पांच सालों में कितने नौजवानों/परिवारों को रोजगार दिया गया, वे आंकड़े आज सबके सामने हैं। वर्ष 2012 में इन्होंने कहा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आज सवा चार साल सरकार के हो गए हैं तब इनको ध्यान आया कि हमने बेरोजगारी भत्ता देना है। इस

15/03/2017/1550/ एन0एस0/डी0सी0 /2

प्रदेश के अंदर 12 लाख से अधिक बेरोजगार रहते हैं और 150 करोड़ रूपये की राशि मात्र दी गई है। उसमें भी अभी नियम बनने हैं। कब यह नियम/कानून बनेंगे और कब बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा? एक बार फिर से इस प्रदेश के बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी विधायक निधि बढ़ाई है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि यह विधायक निधि थोड़ी और बढ़ाई जाए। कम-से-कम 1.50 करोड़ रूपये की राशि विधायक निधि की होनी चाहिए। हमें उम्मीद थी कि शायद इस वर्ष ऐच्छिक निधि जो कि हम जरूरतमंद लोगों को अपने क्षेत्र में देते हैं उसका भी कोई प्रावधान यहां पर किया जाए। हमारी विधायक प्राथमिकता की स्कीमज़ जो हम हर साल प्लानिंग की बैठक में देते हैं, मैंने पिछले चार सालों से पी.डब्लयू.डी. में जो भी स्कीम डाली है, आज तक एक भी स्कीम की डी0पी0आर0 पी.डब्लयू.डी. विभाग ने नहीं बनाई है। हम इसके लिए अधिकारियों से बात करते हैं और हर बार प्लानिंग की बैठक में इस बात को रखते हैं। जब प्लानिंग की बैठक खत्म होती है और माननीय मुख्य मंत्री जी आदेश भी करते हैं लेकिन वे आदेश इम्पलीमैंट नहीं होते हैं और फाईलें वहीं पड़ी रहती हैं। मैंने प्लानिंग की बैठक में पी.डब्लयू.डी. विभाग की सड़कों की बात भी रखी थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र की लगभग 15 सड़कें पिछले 7-8 सालों से बनकर तैयार हैं लेकिन विभाग उनको पास नहीं करवा रहा है। मैं नहीं जानता कि विभाग उनको पास क्यों नहीं करवा रहा है? इस बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो 15 सड़कें हैं, उनमें बसें चलने चाहिए लेकिन उनमें यूटिलिटी चलती है। वहां पर एक यूटिलिटी में 50-50 लोग बैठ करके आते हैं। इतनी सारी दुर्घटनायें मेरे क्षेत्र में हो चुकी हैं। इन सड़कों के पास न होने के कारण सैंकड़ों जानें जा चुकी हैं और वहां के लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। इस मान्य सदन में पिछले कल परिवहन मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया और कहा कि हमने बहुत सारे बस-अड्डों के लिए पैसा दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी बस-अड्डा नहीं है, वहां पर बसों के खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है। मेर क्षेत्र में एच.आर.टी.सी. की जो बसें चलती हैं,

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी

15/03/2017/1555/RKS/DC/1

श्री बलदेव सिंह तोमर...जारी

वे भी मात्र दो या तीन ही चलती हैं। यहां पर इतनी बसों की बात करते हैं कि हमने सैंकड़ो/हजारों बसें प्रदेश के लिए लाई हैं। पता नहीं वे बसे कहां चलती हैं? उन दूर-दराज क्षेत्रों में जहां लोगों को मुश्किल होती है वहां पर वे बसें क्यों नहीं चलती हैं? पांवटा साहिब में एक बस अड्डा पड़ता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र से हर रोज़ 25-30 प्राइवेट बसें लोगों से भरकर पावंटा जाती है। लेकिन उसकी हालत आप देखेंगे तो उस बस अड्डे में गड्ढे-ही-गड्ढे हैं। यात्रियों को वहां पर बैठने की कोई सुविधा नहीं है। मैंने कई बार अखबारों में पढ़ा कि वहां पर मंत्री जी आए और उन्होंने बस अड्डे का निरीक्षण किया। कभी कहते हैं कि बी.ओ.टी. मोड़ पर बनाने जा रहे हैं और कभी कहते हैं पी.पी.पी. मोड़ पर बनाने जा रहे हैं। सवा चार वर्ष का समय बीत गया है लेकिन आज तक वहां पर कोई व्यवस्थता नहीं हो पाई है। इस बजट में कोई विशेष बात इस प्रदेश की जनता के लिए नहीं है। मैं इस बजट का विरोध करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद। जय हिन्द।

उपाध्यक्षः अब श्री रवि ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

15/03/2017/1555/RKS/DC/2

श्री रवि ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 10 मार्च, 2017 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में बजट पेश किया, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया वह बहुत ही लोकप्रिय है। यह बजट जनता के हित में है और प्रदेश में जितने भी वर्ग हैं, चाहे वे बुढ़े, नौजवान, बच्चे या महिलाएं हो सबके हित में यह बजट है। इस बजट की पूरे प्रदेशवासियों ने सराहना की है। अभी माननीय महेश्वर सिंह जी कह रहे थे कि दिल्ली सरकार से भी हमें बजट आता है। मगर वह थाली में डालते-डालते भरता

नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट कोई जेब से नहीं देता है। यह लोकतांत्रिक प्रणाली है। इसमें जब जनता हाथ काट कर वोट देती है तो दिल्ली या किसी राज्य के अंदर सरकार बनाती है। बजट का प्रावधान संसाधनों से होता है। महासागर के भीतर से भी बहुत से संसाधन जुटाए जाते हैं। जैसे कि मोती या तेल निकलता है। जितना भी हमारा हारवेस्ट होता है, जितना भी हमारा फूड है, जैसे मछली के रूप में या जो खाने के पदार्थ होते हैं, समुद्र से निकाले जाते हैं। इसी तरह से हमारी सोने या तेल की खानें हैं, जो रेगिस्तान में मिलती हैं। बहुत ज्यादा जंगलों से भी संसाधन जोड़े जाते हैं। उद्योगपति जो टैक्स देते हैं, सारे प्रदेशों से केन्द्र सरकार को टैक्स जाता है। चाहे वह एक्सरसाइज टैक्स हो, लग्जरी टैक्स हो, सेल्ज़ टैक्स हो या इनकम टैक्स हो। जो ए.टी.एम्ज, चल रहे हैं, जो भारत सरकार ने कैशलैस नीति चलाई है,उससे भी टैक्स कटता है। कारखानों में जो टैक्स लगता है उसमें भी केन्द्र सरकार का हिस्सा होता है। दुकानदारों पर जो टैक्स लगता है उससे भी केन्द्र सरकार को टैक्स जाता है। इसी तरह से जो गरीब लोग दाल,चीनी, नमक लेते हैं, जो हमारे मार्किटयार्ड हैं उसका इस्तेमाल होता है। उससे भी इनडायरेक्टली टैक्स जाता है। जो डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होते हैं, नेटबैंकिंग होती है उससे भी केन्द्र सरकार को टैक्स जाता है। जो टेलिफोन लग रहे हैं और जितने भी टैक्सिज हैं पूर भारतवर्ष से इक्ट्ठे होकर केन्द्र में जाते हैं। हम शरीर का एक हिस्सा है। प्रदेश भी एक हिस्सा ही है। यदि किसी शरीर में कोई कमी है तो वहां पर संसाधन देने की जरूरत है। शरीर हमेशा सोचता है कि यदि एक हाथ बीमार है तो उसको भी कुछ-न-कुछ दिया जाए ताकि वह हाथ ठीक चले। इसलिए जो देना है उसके लिए केन्द्र सरकार का दायित्व बनता है।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

15.03.2017/1600/SLS-AS-1

श्री रवि ठाकुर.... जारी

हमारी सरकार ने सोच-समझकर समझ-बूझ के साथ जो बजट का आबंटन किया है, मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए किया है। जो चुनिंदा लोग यहां पर चुन कर आए हैं, जैसे कि हमारे विधायक हैं, उनके लिए विधायक निधि 1.10 करोड़ रुपये

कर दी है। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार और माननीय मुख्य मंत्री को बधाई दूंगा। नाबार्ड में अब एक विधायक 80 करोड़ रुपये तक की राशि के लिए अपनी पॉवर इस्तेमाल कर सकता है और अपने चुनाव क्षेत्र में बजट दे सकता है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। इन्होंने पंचायती राज को भी मज़बूती दी है। जैसे समिति के सदस्य हैं या जिला परिषद के सदस्य हैं, 14वें वित्तायोग ने इसके लिए ज्यादा बजट नहीं दिया था लेकिन हिमाचल सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया है।

मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह बजट प्रदेश के लोगों को आधुनिक युग के साथ जोड़ने के लिए रखा है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिमाचल प्रदेश कंधे-से-कंधा मिलाकर चलेगा, मेरा ऐसा मानना है क्योंकि जो स्मार्ट सिटी की योजना धर्मशाला और शिमला के लिए बनाई गई है, यह एक अच्छा कदम है जिसमें केंद्र सरकार की भी पूरी मदद ली जा रही है, मैं ऐसा मानता है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। सॉफ्टवेयर, टैक्नोलोजी पार्क्स, हास्पिटल्ज, स्कूल्ज आदि के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो रहा है। प्रदेश में एच.आर.टी.सी. के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है और इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने जो बजट प्रावधान किया है, यह एक अच्छी बात है।

हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी हमारे किसान और बागवान हैं। उनके लिए उत्पादन हेतु जो उपकरण दिए जा रहे हैं, जैसे सेव, सब्जियों, फलों और अनाज आदि के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उपकरणों पर जो सब्सिडी दी जा रही है, वह एक अच्छा कदम है। कीटनाशक स्प्रे के उपकरणों के लिए भी हर जगह सब्सिडी दी गई है। इसी तरह पॉवर टिल्लर, स्प्रिंकलर, खाद, बीज, फ्लोरिकल्चर और

15.03.2017/1600/SLS-AS-2

ट्रांसपोर्टेशन पर भी सब्सिडी दी जा रही है और सब्जी मण्डियां भी कई जगह खोली गई हैं। अभी लाहौल स्पिति में अस्थाई रूप से खोली गई है और उसे इसी साल स्थाई रूप में

चला दिया जाएगा। उसके लिए बहुत ज्यादा बजट का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश में पॉली हाऊसिज भी बन रहे हैं।

विभागों में भी बहुत ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। चाहे आई.पी.एच. विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, शिक्षा विभाग हो; इन सबमें बजट का इज़ाफा हुआ है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं।

मज़दूरों, आंगनबाड़ी वर्कर्ज़, कंप्यूटर टीचर्ज़ आदि के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। PTA, SMCs, आंगनबाड़ीज से विशेषकर हमारे लोगों को बहुत लाभ हुआ है। जिन्हें इसमें नौकरियां मिली हैं, उनको भी लाभ हुआ है। जब भी PTAs और SMCs की बात चलती है तो जनता इससे बहुत खुश दिखाई देती है। लाहौल-स्पिति के अंदर जितनी भी खाली सीटें थीं वह SMCs के माध्यम से भरी गईं हैं। इससे, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा आने वाला कल है, उनको बहुत ज्यादा लाभ हुआ है।

अनेक वर्गों के लिए अलाउंसिज का प्रावधान किया गया है। जैसे जन जाति क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अलाउंस, कैपिटल भत्ता, राशन अलाउंस, वाशिंग अलाउंस और अन्य अलाउंसिज का भी प्रावधान किया गया है, इसके लिए भी इस बजट को हिमाचल की जनता ने सराहा है।

जहां तक उद्योग और पर्यटन की बात है, हिमाचल सरकार ने इससे बहुत अधिक फायदा उठाया है। हिमाचल में ईको टूरिज्म शुरू करने की भी योजना है और खास तौर पर लाहौल-स्पिति में एक मास्टर प्लान बनाकर इसकी नींव रखी गई है। इससे सैलानियों के लाहौल-स्पिति में आने में बहुत ज्यादा इज़ाफा हुआ है। उद्योग और पर्यटन के माध्यम से सरकार ने बहुत-सा बजट बढ़ाया है और इसे सरकार की आमदनी में जोड़ा है। इसी तरह ऊर्जा और वनों के माध्यम से भी हिमाचल सरकार की आमदनी में बहुत ज्यादा इज़ाफा हुआ है।

जारी ...श्री गर्ग जी द्वारा

15/03/2017/1605/RG/DC/1
श्री रवि ठाकुर---जारी

उपाध्यक्ष महोदय, स्पीति में जो मजदूर लगे हुए थे उनकी दिहाड़ी इस सरकार ने पक्की कर दी है और उनको पक्का रोजगार दिया गया है जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करुंगा। इसके अतिरिक्त इस बार के बजट में पूरे जनजातीय क्षेत्र के लिए काफी बढ़ौत्तरी हुई है इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करुंगा। हिमाचल प्रदेश एक शांतप्रिय प्रदेश होने के कारण यहां काफी ज्यादा तरक्की हो रही है और उद्योग के क्षेत्र में भी काफी बढ़ावा हुआ है। उद्योगों पर यहां जो विभिन्न टैक्स लगते हैं उनमें छूट दी गई है उसके कारण प्रदेश की आय में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इसी कारण से पंजाब जैसे प्रदेश से बहुत ज्यादा उद्योगपति हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में अपने उद्योग लगाने के लिए आए हैं और उन्होंने यहां उद्योग शुरू किए हैं। इसी प्रकार से हमारे यहां जो कम दरों पर बिजली मिलती है उससे भी यहां उद्योगों में काफी इज़ाफा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है और होटलों में बढ़ोत्तरी हुई है। कुल्लू, मनाली, लाहौल-स्पीति, शिमला, धर्मशाला इत्यादि में प्राइवेट होटलियर्ज बहुत आए हैं जिससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है और लोगों को कई तरह के रोजगार मिले हैं। जबकि हमारे साथ लगते पंजाब के हालात देखें, तो उसमें ज्यादातर चीजें मॉर्टगेज की हुई हैं या रहन पर दी गई हैं। उनकी जो सरकारी इमारतें, सर्कट हॉऊसेज या दूसरे भवन हैं उन्हें रहन पर रखा है। तो यह बहुत अच्छी बात नहीं है। जबकि हिमाचल प्रदेश में इन सभी चीजों का बहुत अच्छी तरह संचालन किया जा रहा है और इनके ऊपर बजट काफी है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम पूरे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो यदि पूरे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा विभाग का बजट खत्म कर दिया जाए, तो पूरे विश्व में खाने की कमी खत्म हो जाएगी। यह बिल्कुल निश्चित बात है। लाखों करोड़ों रुपयों का बजट रक्षा मंत्रालय को दिया जाता है। मैं कहना चाह रहा हूं कि केन्द्र के निर्देश पर जो सर्जिकल स्ट्राईक हो रही है और इतने ज्यादा नौजवान हमारे मर रहे हैं, इससे पहले कभी भी इतने ज्यादा नौजवान इतने कम समय में हमारे यहां नहीं मरे। तो यह बहुत दुखद घटना है और एक-एक सर्जिकल स्ट्राईक पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होता है। इसलिए इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि एक बैलेंस तरीके से बजट केन्द्र में होना चाहिए। ये जैसा कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री

15/03/2017/1605/RG/DC/2

जी ने हमारे प्रदेश में इतने स्कूल खोल दिए हैं या इतनी तहसीलें खोल दी हैं, तो इन पर जो खर्चा हो रहा है वह जनता के फायदे के लिए हो रहा है। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राईक हो रही है या अनचाही चीजें हो रही हैं जिसमें देश के बहुत अधिक नौजवान मर रहे हैं, तो उन चीजों पर लगाम लगनी चाहिए। इन चीजों को ईगो बनाकर सरकार नहीं चलानी चाहिए। मेरा यही कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा था कि अभी ऐस्टीमेटेड जी.डी.पी. ग्रोथ आ रहा है। मेरा यह मानना है कि ऐस्टीमेटेड जी.डी.पी. ग्रोथ फैब्रिकेटेड भी हो सकता है। हिन्दुस्तान सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है कि जी.डी.पी. ग्रोथ ऐस्टीमेटेड आ रहा है या फैब्रिकेटेड आ रहा है। भारत सरकार में Statistical Officers भी इसमें दवाब महसूस कर रहे हैं, तो यह भी अच्छी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है वहां इनकम टैक्स लगता है। अब जैसे पूवोत्तर भारत और लद्दाख में इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लग रहा है मगर हमारे हिमाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, यहां हमें इनकम टैक्स भी लग रहा है और कोई किसी प्रकार की छूट नहीं है। जितने भी हमारे सरकारी मुलाजिम लगे हैं उन पर भी इनकम टैक्स लग रहा है और जो केन्द्र सरकार से स्पेशल बजट पूर्वोत्तर भारत और लद्दाख में जाता है हमें उस तर्ज पर इसका फायदा यहां नहीं पहुंच रहा है। तो यह भी हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए एक दुखद बात है। ऐसा देखने में आया है कि इनफ्लेशन रेट यानि डेफिशिट भी हमारे यहां ज्यादा बढ़ रहा है।

एम.एस. द्वारा जारी

15/03/2017/1610/MS/AS/1

श्री रवि ठाकुर जारी-------

इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार को कुल-मिलाकर मिलकर चलना चाहिए और जनता के फायदे के लिए चलना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि जो केन्द्र से पैसा आ रहा है उसे कोई अपनी जेब से दे रहा है and just by renaming, जो कोई हमारी योजना चल रही है उसका दुबारा से नामकरण करके यह कहना कि यह योजना हमने चलाई है, यह भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि यह बहुत ज्यादा देखने में आया है कि सड़कों, भवनों और योजनाओं के नाम बदले गए हैं। इस प्रथा को भी बन्द करना चाहिए। पूरे देश में कई ऐसी जगहें हैं जिनके बेसिक नाम ही चेंज कर दिए हैं। जो इतिहास है वह तो इतिहास ही रहता है और जो इतिहास बनता है वह किसी नींव पर बनता है। अगर आप यह सोचेंगे कि आप इतिहास को मिटा देंगे तो यह भी अच्छी बात नहीं है, ऐसा मेरा मानना है।

मेरे छोटे भाई श्री हंस राज जी इस समय सदन में मौजूद नहीं है। वे शायद बाहर चाय की चुस्की ले रहे होंगे। मैं उनकी गैर-हाजिरी में यही कहना चाहूंगा कि आप भी अनुसूचित जन-जाति से संबंध रखते हैं। एक हिन्दु नागरिक और भारतवर्ष का नागरिक होने के नाते हमारी यह रीत है कि हम बुजुर्गों का मान-सम्मान करते हैं। खासतौर पर ग्रंथों में यह भी लिखा हुआ है कि घर में कोई 70 वर्ष की आयु से बड़ी उम्र का हो तो उसकी सेवा करना एक देवी-देवता की सेवा करने के समान है। इस बात पर हमारे संत कबीर दास जी के दोहे जो स्कूल में हमने पढ़े थे, उनकी एक-दो पंक्तियां मैं यहां कहना चाहूंगा।

मीठे बोल बोलिए मन का आपा खोए,
औरों को शीतल करे आपु शीतल होए।
और यह भी नहीं करना चाहिए कि-
रात गवाए सोकर, दिवस गवाय खाए,
हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए।
इसी तरह से -
बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर,
पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर।

15/03/2017/1610/MS/AS/2

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

-(व्यवधान)-मैंने सोचा कि कुछ हमारी तरफ से भी हो जाए। हर कार्य जो भी हम करते हैं उसका कोई लक्ष्य या कारण होता है और यदि कोई भी घटना घटती है तो उसका भी कोई कारण होता है। अभी यदि मैं अपने कान में भी खारिश करूंगा तो उसके लिए भी हाथ उठाना पड़ेगा। अगर मैंने ये टोपी पहनी है जैसे रविन्द्र सिंह जी ने भी पहनी है तो उसका भी कोई अर्थ है। मैं महात्मा गांधी जी के आदर्शों को याद करने के लिए यह टोपी पहनता हूं। आप लोगों ने मुझे पिछले सत्र में इस बारे में पूछा था। लेकिन अभी बात माननीय हंस राज जी की चल रही थी। -(व्यवधान)-बजट के लिए मैं हिमाचल सरकार को बधाई दे चुका हूं। अन्त में मैं एक बात यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारा बजट है, ये जो सांसारिक जीवन हम अभी जी रहे हैं तो जैसे मैं अभी माननीय हंस राज जी की बात कर रहा था लेकिन वह बात बीच में कट गई। अभी माननीय संजय रतन जी के जन्म दिवस पर हम इकट्ठे हुए थे तो वे पूछ रहे थे कि आपने यह तगमा अपने आपको सेग्रीगेट करने के लिए लगाया है? मैं उनसे यही कहना चाहता था कि इस तगमे में यह लिखा है कि वीर पुरूष ही इस धरती का सुख भोग सकता है। परन्तु मैं यह समझता हूं कि वीर पुरूष वह पुरूष है जिसने सबसे उत्तम और श्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है और वह महात्मा बुद्ध थे। हजारों-लाखों दुश्मनों से लड़ाई करके, उनको मारकर जिसको हीरो बोलते हैं वह हीरो नहीं होता है। दूसरे के मन पर जो राज करता है और शासन करता है उसको मैं हीरो समझता हूं। तो गौतम बुद्ध जी भी एक राज-घराने के क्षत्रिय परिवार से थे। इसलिए मैंने यह तगमा लगाया है। मैं यही कहना चाहता हूं। जो आज हम यहां बैठे हैं और बजट की बात कर रहे हैं तो बजट का जो हमारा वितरण होना है यह सब सांसारिक चीजें हैं। गौतम बुद्ध ने हमें माध्यमिक मार्ग बताया था और उस मार्ग में ये जो मटीरियल चीजें हैं इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि पांच इन्द्रियां जिन पर हम काबू पाते हैं और इन्द्र देवता भी काबू पाते हैं। -(व्यवधान)- यह बात मैं माननीय हंस राज जी के लिए कह रहा हूं। वे मेरे छोटे भाई हैं।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा------

15.03.2017/1615/जेके/ए0एस0/1

श्री रवि ठाकुर जारी----

मैं इनको यही कहना चाहता हूं कि इतना उतावला न हो। मैं उनको छोटे भाई के नाते कुछ बताना चाहता हूं।

Speaker: Hon'ble Member, please don't indulge in direct conversation.

श्री रवि ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध ने तो यह कहा था कि पांच इन्द्रियों पर तो काबू पाया है मगर मध्य मार्ग तो यह है कि मैटिरियल वर्ल्ड में भी रहना है परन्तु जब यहां से मैटिरियल वर्ल्ड जब छोड़कर आपने जाना है तो मोक्ष की जब प्राप्ति होती है तो आपने अपने अन्दर देखना है। उसमें रेडियंट क्लीयर लाईट आपको मिलेगी। वह महात्मा बुद्ध ने कहा है। तो गौतम बुद्ध का लक्ष्य बताते हुए एक शान्ति का प्रतीक है, यही मैं माननीय हंस राज जी को बोलना चाहता हूं। अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और हिमाचल सरकार का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने खासतौर पर कबायली क्षेत्रों में, अनुसूचित जन-जातीय क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा बजट दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करुंगा और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

15.03.2017/1615/जेके/ए0एस0/2

अध्यक्षः अब श्री इन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगें।

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में बजट चर्चा पर जो बहस चल रही है, उसमें भाग लेने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई उस समय यह फाईनैंशियली वायबल स्टेट नहीं था। हमारी सारी इकोनॉमी मनीऑर्डर इकोनॉमी होती थी लेकिन इतने साल गुज़रने के बाद भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर वही है जो उस समय थी। आज 100 रुपये में से केवल 39 रुपये ही प्रदेश के विकास के लिए मौजूद है

और मैं ऐसा समझता हूं कि यह प्रदेश के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। प्रदेश की स्थापना के बाद अधिकतर शासन कांग्रेस पार्टी का रहा। अगर संसाधनों में कमी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है क्योंकि आपने रिसोर्स मोबलाईजेशन के बारे में सोचा ही नहीं। आप प्रदेश को स्विटजरलैंड बनाना चाहते थे लेकिन आपने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है। आपने टूरिज्म और हाईड्रो पावर, जो हमारे दुधारू सैक्टर्ज़ हैं, उनकी पोटैंशियल को ठीक से टैप नहीं किया। आपने आर्थिक दृष्टि से सॉफ्ट ऑप्शन अपनाया और सॉफ्ट ऑप्शन था, कर्ज लेना। कर्जा लो और आनन्द करो, मौजां करो। बिलासपुर में एक कलाकार होते थे, बम्बर जी के चुनाव क्षेत्र के थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली को देखकर एक बड़ा अच्छा गाना बनाया था। मुझे भी उस गाने को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गाना क्या था- खाना, पीना नन्द डवानी हो गम्बरिए। आप कर्जा लेते रहे और आनन्द उड़ाते रहे, इसके फलस्वरूप आज प्रदेश पर 45 हजार 213 करोड़ रुपये का कर्जा है और यह शोचनीय विषय है। बच्चा पैदा होता है तो उस पर पैदा होते ही 50 हजार का कर्जा है। अधिकतर आपकी ही वजह से यह हो रहा है। माननीय धूमल जी के पिछले पांच साल के कार्यकाल में केवल आठ हजार करोड़ रुपये का कर्जा लिया गया था। आपने इन चार सालों में 16 हजार 506 करोड़ रु0 का कर्जा ले लिया। Where is the limit? There has to be some limits.

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

15.03.2017/1620/SS-AS/1

श्री इन्द्र सिंह क्रमागतः

आज अधिकतर आपके सारे बोर्ड और कारपोरेशन घाटे में चल रहे हैं। आज फाइनेंशियल डिसीप्लन की ज़रूरत है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बड़ी फौज चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन की खड़ी कर दी है, काम कुछ नहीं। प्रदेश की जनता ने आपको विकास के लिए मैनडेट दिया था। ये बार-बार हारे हुए लोगों के रिहैब्लिटेशन के लिए आपको मैनडेट नहीं दिया था। यह आपको बहुत महंगा पड़ेगा। I know, it is the prerogative of the Hon'ble Chief Minister to place anybody, to raise anybody to any position. But he has got no moral right to waste public money like this. कितने बड़ी फौज

चेयरमैनों और वाइस-चेयरमैनों की खड़ी कर दी। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं। छठी बार मुख्य मंत्री बने हैं we are proud of it that he has got more than 60 years of political experience. मुख्य मंत्री जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अपने दिल पर हाथ रखो कि क्या आपको पॉलिटिकल सलाहकार की ज़रूरत है? मैं पॉलिटिकल सलाहकार से ज्यादा इफैक्टिड हूं। क्या आज तक आपको उन्होंने कोई सलाह दी और आपने ली? तो आपका जवाब होगा "नहीं"। तो फिर यह लोड हमारे सिर पर क्यों रखा हुआ है? इसको उतारो। मेरे ख्याल में आपसे ज्यादा उसको पॉलिटिकल सलाहकार की ज़रूरत है। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप उसके बारे में सोचिये। It is wastage of money and you have to think over it. आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। रवि जी, आप पांच इंद्रियों की बात कर रहे थे। यह भी एक इन्द्री है उसमें से। Don't waste and squander the money like this. You are wasting out the meager resources of the State. किस लिए बनाए हैं ये 40-45 चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन? बाली जी, यहां नहीं हैं। इनकी दुकान तो बंद होने वाली है। 1200 करोड़ रुपये का घाटा है। आपके पावर सैक्टर में 2400 करोड़ का घाटा है। आप घाटे पर चल रहे हैं। माननीय नरेन्द्र ठाकुर जी ने कहा था कि जो टेंटिड अधिकारी हैं उनको आप अच्छी पोस्टों पर रख रहे हैं। संवेदनशील पोस्टों पर रख रहे हैं। उससे अपना भी बेड़ागर्क और संस्थान का भी बेड़ागर्क। You have to think over it. माननीय धर्माणी जी, पैरा-79 पर बात कर रहे थे। आप

15.03.2017/1620/SS-AS/2

एजुकेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में कह रहे थे। मैं एजुकेशन की बात करूं तो आपने गिनाए कि बहुत से स्कूल खोल दिए, यह खोल दिया और वह खोल दिया। Where are the teachers and other infrastructure? धर्माणी जी, आप एक इंजीनियर कॉलेज में स्टूडैंट हैं suppose you are an engineer. वहां पर एडिक्वेट स्टाफ नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, will you not curse yourself, if yes, then you will be with me on this issue? आपने 1328 स्कूल खोले और अपग्रेड किये, आपने गिनती की लेकिन स्टाफ नहीं दिया

तो you are diluting and spoiling every system. आप सिस्टम के मुताबिक चलिये। मापदंड के मुताबिक स्कूल खोलिये। हैल्थ मिनिस्टर साहब मैंने तो आपके विभाग के बारे में बात करनी थी। थोड़ा-सा सदन में रूक जाते तो अच्छा था। आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। It is not an inclusive growth, it is an exclusive growth. आप हमको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। यह इंक्लूसिव ग्रोथ हरोली की है। मंत्री जी यहां नहीं हैं। यह ग्रोथ धर्मशाला की हो सकती है, मंत्री जी यहां नहीं हैं। हमारी क्या इंक्लूसिव ग्रोथ है? हमारे बारे में तो आप देखते ही नहीं हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में जो बुरी हालत है मैं उसके बारे में क्या बयान करूं। चार सालों में एक सड़क की डी0पी0आर0 नहीं बनी। --(व्यवधान)-- सर सुनिये। वह मेरी देन है।। am not telling the truth. मैं रवि ठाकुर जी की बात से सहमत हूं कि अपनी इन्द्रियों पर कंट्रोल रखो। ये रखें या न रखें, यह इनकी मर्जी है। करनी-कथनी में फ़र्क भी होता है। लेकिन हम कंट्रोल रखते हैं। मेरी एक सड़क की डी0पी0आर0 चार सालों में बनी और माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी 18 सड़कों की डी0पी0आर0 बन गई। आपके ज्यादा जंगल हैं या मेरे ज्यादा जंगल हैं? यह कौन-सी इंक्लूसिव ग्रोथ है? This is an exclusive growth for certain people.

जारी श्रीमती ए0वी0

15.3.2017/1625/av/as/1

श्री इन्द्र सिंह---------- जारी

आप सबकी भी नहीं आई यह मैं जानता हूं। इसलिए आप जो कहते हैं कि नाबार्ड से 80 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 सैंक्शन हो गई। जब डी0पी0आर0 ही नहीं बन रही है तो मैंने 80 करोड़ रुपये की राशि से क्या करना है? आप डी0पी0आर0 बनाइए। चार वर्ष के कार्यकाल में एक डी0पी0आर0 बनी है तो आप सोच सकते हैं कि आपका इस तरह का क्या रिकार्ड है? आपने ऐसा सलाहकार दिया है कि वहां हर 6 महीने के बाद आप ऐक्सियन चेंज कर देते हैं। पानी के व्यवस्था के ऊपर बोलूं तो I think, this is totally

wastage of time. मैंने प्लानिंग की मीटिंग में इस पर बात की थी और यहां पर अपने भाषणों में बार-बार बोलता हूं। सबसे डिसमल पोजिशन अगर किसी क्षेत्र की है तो वह पानी के सैक्टर की है। यह सरकार पानी देने में अक्षम रही है। मेरे ख्याल में यहां सरकार को बैठने का हक ही नहीं है। आप लोगों को 15-15 दिन तक पानी ही नहीं दे पा रहे हैं। आपकी कोई रीमोडलिंग स्कीम नहीं है, प्लानिंग नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। I don't know, आपकी सरकार कैसे काम कर रही है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने ब्यास नदी से पानी की स्कीमें लाई हैं। उन तीन स्कीमों का 70 प्रतिशत काम हो चुका था मगर पिछले चार साल से उसका बाकी बचा 30 प्रतिशत काम नहीं हुआ। डैहर से उठाऊ पेयजल योजना लाई है उस पर भी धीमी गति से काम चल रहा है। सिंचाई की बात तो छोड़ ही दीजिए। मेरे पास माननीय धूमल जी की कृपा से तीन सिंचाई की स्कीमें हैं। मगर वे तीनों-की-तीनों स्कीमें बंद कर दी गई और कहा जा रहा है कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है। (---व्यवधान---) आप (श्री राजेश धर्माणी) झूठ मत बोलिए। Kindly listen to me. 90 प्रतिशत ग्रेविटी की स्कीमों में फिल्टर नहीं है और आप लोगों को सीधे पानी सप्लाई कर रहे हैं। सीर खड्ड की चैनेलाईजेशन के लिए पता नहीं 15 साल से (---व्यवधान---) के0डी0 धर्माणी जी रिटायर भी हो गये। यह काम उन्होंने शुरू किया था। (---व्यवधान---) आप (श्री राजेश धर्माणी) भी रिटायर हो जायेंगे औरा मैं तो आप से पहले रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन उस सीर खड्ड की चैनेलाईजेशन का काम नहीं हुआ। मैंने सरकार से रिक्वैस्ट की कि वलनर्बेल प्वाईंट को आइडैंटिफाई कीजिए। क्या आपने वह प्वाईंट आइडैंटिफाई किए? Why don't you take steps to block those weak points. आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। It is really a pathetic state. मेरे पास राजस्व रिकार्ड में 52 कूहलें हैं और उसमें से 17 चल रही हैं तथा वह भी आधी-अधूरी। आप किस विकास की

15.3.2017/1625/av/as/2

बात कर रहे हैं? You have already wasted four and a half year and you are going to waste another six months. मैं अब स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर रहा हूं। My God, Shri Dharmani took five minutes to list out that कितना अपग्रेड किया, कितनी सी0एच0सी0,पी0एच0सी0 और सिविल होस्पिटल बनें। we have total 18 posts of doctors और उसमें से आपने 6 दिए हैं। Give us doctors. मैंने फट्टे लगाकर क्या करना?

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपसे कब से रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि वहां पर स्पैशेलिस्ट भेजिए। we have no other dependability. डिपैंडेबल सिस्टम नहीं है और सरकारी क्षेत्र के बाद प्राइवेट क्षेत्र में भी कोई सिविल होस्पिटल नहीं है। हमारी टोटल डिपैंडेंसी आपके सरकारी होस्पिटल्स पर हैं जो कि खाली पड़े हैं। Have pity on us. आप (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री) गर्दन तो हिलाते हैं मगर मेरा काम नहीं बन रहा है। Sir, I am sorry. ---(---व्यवधान---) बिल्डिंग को मैंने चाटना नहीं है वहां पर आप डॉक्टर बिठाओ। I don't know. आपने 14 एस0डी0एम0 बिठा दिए, तहसील 16, सब-तहसील 31; मेरे पास सरकाघाट और बलद्वाड़ा में दो तहसीलें हैं और उनमें तहसीलदार ही नहीं है। I am surprised. राजस्व मंत्री जी से इस बारे में कितनी रिक्वैस्ट की है कि भेजिए, भेजिए मगर नहीं भेज रहे हैं। आपने अनेकों इनस्टिच्यूशन्स अपग्रेड किए हैं मगर उनमें स्टाफ की कोई व्यवस्था नहीं की गई और न ही उसके लिए कोई परवाह की है। इसके अतिरिक्त मैं कानून-व्यवस्था पर बोलना चाहता हूं। धर्माणी जी कल बड़े जोर-शोर से बोल रहे थे कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। (---व्यवधान---) मैं सरकाघाट की बात कर रहा हूं और धर्माणी जी, आप मेरे पड़ोसी है। सरकाघाट में एक होमगार्ड को ड्यूटी पर रात को पीट-पीटकर मार दिया। He was murdered. उसका केवल यह कसूर था कि उसने शराबियों को बोला कि रात के 1130 बज गये हैं आप लोग घर जाइए और यहां पर शोर मत कीजिए। इतना बोलने पर उसको मार दिया। आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने यहां पर 30 गाड़ियो की बात की है। वह गाड़ियां किस की थी? वह गाड़ियां किस-किस की चल रही थी? मेरे क्षेत्र बलद्वाड़ा में भी वह गाड़ियां चली। बिल्कुल नई गाड़ियां थी। (---व्यवधान---) हां, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है उन गाड़ियों को वह लोग चला रहे थे।

श्री वर्मा द्वारा जारी

15/03/2017/1630/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री इंद्र सिंह ठाकुर.... जारी।

वे गाड़ियां किस-किस की चल रही थी, मेरे क्षेत्र बलदवाड़ा में भी वे गाड़ियां चली। ये नई-नई गाड़ियां थी। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था वे लोग उन गाड़ियों को चला रहे

थे और एकाएक वे गाड़ियां गायब हो गई। मैंने पूछा कि वे गाड़ियां कहा चली गई? पता चला कि ये चोरी की गाड़ियां थी। ये चोरी की गाड़ियां महीनों तक सड़क पर चलती रही। उन गाड़ियों में कितने पुराने नोट इधर-से-उधर हुए होंगे किसको पता? ये आपकी कानून व्यवस्था है। माननीय धर्माणी जी नोटबंदी के बाद सारा पैसा बैंकों में चला गया और वे अब भेड़-बकरियां चुरा रहे हैं। लोगों ने अपनी भेड़-बकरियां ही बेच दी। ताकि कुछ पैसे तो मिलेंगे। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। There is no doubt, you come to carry out the study of my PWD Division, Sarkaghat Division, you will come to know कि भ्रष्टाचार किस लैवल तक जा सकता है और उसकी आवाज़ ये विधायक चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने 89 ठेकों में से 34 ठेके लिए उसने काम नहीं किया। It is all paper work and he collected money on papers. माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं इनक्वायरी करवाऊंगा। मैंने कहा- वह आपका ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आप उसकी इनक्वायरी नहीं करवा सकते हैं। वह इनक्वायरी कहां हैं? Where is that enquiry? ये सब चोरी का धन्धा है, आप प्रदेश के अंदर कुछ नहीं करना चाहते हैं। 'परिवहन फ्री फैसेलिटी टू स्टूडैंटस', लेकिन किस रूट पर कौन-सी बस चल रही है। ये सब गपौडशंख की बात है। श्री राकेश कालिया जी बात कर रहे थे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने रूरल रोड रिपेयर के लिए 20 करोड़ रूपये दिये हैं, लेकिन ये कम हैं। जो लिंक रोड़ हम विधायक निधि या अपने संसाधनों से बनाते हैं, उनकी रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता हैं। आपने बेरोज़गारी भत्ता दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इस पर आप जितना कम बोलें, उतना अच्छा रहेगा। आपने 150 करोड़ रूपया दिया, वह भी तब जब आपकी सरकार जाने वाली हैं। लेकिन इससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपने 150 करोड़ रूपया दिया अगर आप एक साल के लिए भी देंगे तो you can serve only 1,25,000 unemployed people. कांग्रेस यू0पी0ए0 सरकार जाते-जाते 500 करोड़ रूपये दे गई थी और कह दिया कि हमने वन-रैंक-वन पेंशन दे दिया। जबकि चाहिए था 12 हजार करोड़ रूपया। वह मोदी जी ने दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। इस बात को नेता प्रतिपक्ष ने पहली बार संसद में रखा

15/03/2017/1630/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

था कि वन-रैंक-वन पेंशन होनी चाहिए। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। ये जो 150 करोड़ रूपया रखा गया है यदि आपने पूरे लोगों को देना है, तो आपको 12,000 करोड़ रूपया 5 साल में देना पड़ेगा, जैसी कैल्कूलेश माननीय धूमल साहब ने की है। He cannot be

wrong. आपने महंगाई भत्ता +2 और उससे ऊपर वालों को दिया। क्या दसवीं पास बेरोज़गार नहीं है या 8वीं फेल बेरोज़गार नहीं हैं। You are fishing in muddy water and you will not catch any fish. इसमें कोई दो राय नहीं है और बेरोज़गारी भत्ता देना in ultimate analysis it is harmful. You are giving fish to eat, instead of that you teach them how to fish, that should be your aim. न आप खाने के लिए दे रहे हैं और न पकड़ने की विधि बता रहे हैं। आप बीच-बीच से चल रहे हैं। सर, आपने आवारा पशुओं की बात की। उनसे किसान खेती के लिए पेरशान हैं। 40 प्रतिशत किसान अपना पेशा बदलना चाहते हैं। वे कहां जाएंगे? आप बाड़बंदी की बात कर रहे हैं, आज किसानों का नुकसान करने के लिए आवारा पशु, बंदर, सुअर, नीलगाय और क्या-क्या नहीं घुम रहे हैं। आपने बाड़बंदी की बात की और पहले आपने 60-40 की स्कीम कर दी लेकिन उसको किसी ने नहीं लिया। आपने उसको 80-20 कर दिया है। यह अच्छी बात है, लेकिन आपने इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया। आपने किसानों को इसका डेमोस्ट्रेशन नहीं दिया। यदि आप देते, तो शायद किसान इसको अडोप्ट करते, लेकिन आप चाहते ही नहीं हैं कि किसानों को यह फ़ायदा मिलें।

श्रीमती एन0एस0.... द्वारा जारी।

15/03/2017/1635/ एन0एस0/डी0सी0 /1

श्री इन्द्र सिंह ----- जारी।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार से छात्र नाराज हैं। आपने रूसा लागू करके छात्रों को गुस्सा दिला दिया है। आपने छात्रों को बर्दियां और किताबें समय पर नहीं दी हैं। छात्रों को परिवहन की सुविधा नहीं दी जाती है। जिसकी वजह से छात्र इस सरकार से नाराज हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार से युवक भी नाराज हैं क्योंकि आपने लिमिटिड नम्बर्ज़ को बेरोजगारी भत्ता दिया है जो कि आपने सबको देने का वायदा किया था। इस सरकार से किसान भी नाराज हैं क्योंकि उनको समय पर खाद् और बीज़ नहीं मिलता है। उनको

नकली बीज दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार क्या दे रही है? यहां पर आप बाड़बंदी की बात कर रहे हैं। इस सरकार से एस0सी0, एस0टी0 और अन्य जातियां भी नाराज हैं क्योंकि आपने रोस्टर फोलो नहीं किया है। इस सरकार ने भर्तियों के लिए रोस्टर फोलो ही नहीं किया है। आपसे परिवहन विभाग वाले कर्मचारी भी नाराज़ हैं क्योंकि आपने उनको पेंशन नहीं दी है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपसे सब नाराज़ हैं। नोटबंदी जब हुई तब आपने कहा कि जी0डी0पी0 बहुत गिर जाएगी। इसका रिजल्ट आपको मिल गया है। देश की जी0डी0पी0 आज 7.1 है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसका नतीजा आपने देख लिया है कि वहां पर आपका (कांग्रेस) क्या हाल हुआ है। आजकल लोग बहकावे में नहीं आते हैं। इस मान्य सदन में ओ.डी.एफ. की भी बात आई थी। आप कहते हैं कि प्रदेश में ओ.डी.एफ. हो गया है। जब हम गांव में जाते हैं तो हमारे पास 5 से 10 एप्लीकेशन्ज़ हर गांव से आ रही हैं और वे लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें टॉयलैट की सुविधा दीजिए। हमारे जाहू क्षेत्र में माईग्रेटिड लेबर के 500-600 आदमी हैं वे खुले में शौच करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार कह रही है कि खुले में शौच करना बंद है। यह भी इन्होंने श्रेय लेने के लिए नकली रिपोर्ट बना करके दे दी है। सर, मैंने जिलाधीश, मण्डी से बात की है। कमेटी को you can take to anywhere, जहां आपको सूट करता है। अगर वे हमें बोलते हैं तो हम उनको गांव में ले जाते हैं।

15/03/2017/1635/ एन0एस0/डी0सी0 /2

Speaker: Please try to wind up

Sh. Inder Singh: Sir, I will take 2 minutes. माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जिलाधीश, मण्डी से पूछा कि आपने पूरे जिला मण्डी को ओ.डी.एफ. किया है तो आप इनको पैसा दो। जिलाधीश महोदय ने जवाब दिया कि पहले आप टॉयलैट बनाईए और फिर मुझे फोटो भेजिए तब मैं उनको reimburse करूंगा। अगर उनकी ऐसी स्थिति होती तो वे टॉयलैट पहले ही बना देते। आपने इस मान्य सदन में एक बहुत अच्छी बात कही है। आपने भेड़-बकरियों की artificial insemination की बात की है। यह एक वंडरफुल आइडिया है।

What is this tamasha , आपने गऊओं का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, this is one of the reason. उनको तो आप artificial insemination से आप सड़कों पर ले आए हैं, what is this thought? People don't know how to do it. क्या आप भेड़-बकरियों को भी सड़क पर लाना चाहते हैं? इस मान्य सदन में अभी एक नया thought श्री रवि जी ने दिया है। उन्होंने कहा कि रक्षा बजट होना ही नहीं चाहिए। It is an Utopian idea. माननीय रवि जी, स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने वर्ष 1961 में कहा था कि सैनिकों को रविवार की तनख्वाह क्यों देते हैं? इनसे भवनों का निर्माण करवाओ। जब 1962 की लड़ाई हुई तब पता चला कि फौज क्या है। अगर 1962 की लड़ाई नहीं होती और 1965 की लड़ाई होती तब पता नहीं पाकिस्तान कहां पहुंच जाता।

Speaker: Please wind up.

श्री इन्द्र सिंह : ये जो आपने रक्षा बजट पर विचार रखे हैं वह अत्यन्त निंदनीय हैं। मैं एक सेवानिवृत फौजी हूं। यह देश रहेगा हम तब रहेंगे। जब यह देश ही नहीं बचेगा तो हम कहां से बचेंगे? आपने यह बात चाहे जिस मर्जी भावना से कही हो लेकिन मैसेज across गया है। You don't want Raksha Budget और जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कहते हैं कि यह तो फिजूल में हुई है। You tell Pakistan that don't encroach upon our interests.

श्री आर0के0एस0-----जारी

15/03/2017/1640/RKS/AG/1

श्री इन्द्र सिंह...जारी

इसलिए एक सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं बनता है तो हम दस सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। Our Centre is capable of doing it. Our Prime Minister and Defence Minister are capable of doing it. वह मौनी बाबा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी बोलने के लिए बहुत कुछ था। यह जो बजट है this is much ado about nothing. 'ऊंची दुकान, फीका

पकवान।' आप विपक्ष की चिंता मत करिए। आप अपनी चिंता करिए। विपक्ष हमेशा फिट है और जो फिट रहेगा वह हिट करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह जो आपका बजट है जिसको पढ़ने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने साढ़े चार घंटे का समय लिया और most of the Speakers from the Treasury Benches, ट्रैज़री बेंचिज़ से जितने बोले उन्होंने बजट की चर्चा कम की और एंडयूरैंस की ज्यादा चर्चा की। मुख्य मंत्री जी जवान हैं, साढ़े चार घंटे खड़े रह सकते हैं। You can't delay the system. You can't delay the system to that extent. यह आपकी फिज़ूल सोच है, आप सातवीं बार नहीं आएंगे। इस बजट में 'ऊंची दुकान, फीका पकवान' वाली बात है। इसलिए मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं। जय हिन्द।

15/03/2017/1640/RKS/AG/2

अध्यक्षः अब श्री किशोरी लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च, 2017 को विधानसभा में प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी द्वारा बजट वर्ष 2017-18 प्रस्तुत किया गया। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जो बजट आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है वह विकासोन्नमुखी, हर वर्ग को राहत देने वाला, जन-जन का हितैषी बजट है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। यह उन्हीं के राजनीतिक तजुर्बे का पहलू है। सरकार द्वारा 4 साल में 14 नए उप-मंडल, नागरिक, 16 तहसीलें, 31 उप-तहसीलें खोली गई। मेरे बैजनाथ क्षेत्र के चढ़ियार में भी उप-तहसील, पुलिस चौकी खोली गई, जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। क्योंकी यह वहां की जनता की पुरानी मांग थी और मुख्य मंत्री जी ने इस मांगा को पूरा किया। वहां पर तहसील व पुलिस चौकी में पुरा स्टाफ उपलब्ध है। विपक्ष का यह कहना निंदनीय है कि संस्थान खोले गए और वहां पर कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध नहीं है। जो अच्छे काम होते हैं उनका विरोध

करना विपक्ष का काम है। क्योंकि आपके पास अच्छा बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। इसलिए आप विरोध करेंगे। लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि इस प्रदेश को किसने संवारा, किसने बनाया और किसने प्रदेश का विकास किया। आपकी सरकारें भी रही, वह बात आप याद करिए। चार वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात कर रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे चुनाव क्षेत्र में जो आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणाएं की सभी इम्प्लीमैंट हुई। वहां चार मिडल स्कूलों को अपग्रेड कर हाई बनाया गया और चार स्कूल प्लस टू किए गए। बैजनाथ कॉलेज सन् 1962 का कॉलेज था, वहां पर एम.ए. की क्लासिज़ चलाई गई।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

15.03.2017/1645/SLS-AG-1

श्री किशोरी लाल.... जारी

इसकी जितनी सराहना की जाए, कम है। क्या 1962 के बाद सरकारें नहीं आईं?...(व्यवधान)...भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी आईं, उन्होंने क्यों पी.जी. कॉलेज नहीं दिया? इसलिए मुख्य मंत्री जी की जितनी तारीफ़ की जाए, कम है। मेरे क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में काफी विकास हुआ। दूर-दराज के क्षेत्रों में प्लस टू स्कूल खुले। जहां साईंस क्लासिज नहीं थीं वहां साईंस क्लासिज चलाई गईं। हमारे धौलाधार क्षेत्र के उतराला में प्लस टू स्कूल में साईंस क्लासिज चलाई गईं। वहां पर भवन का निर्माण भी हो रहा है। दयोल में साईंस की क्लासिज हैं और भवन निर्माण हो रहा है। संसाल में भवन का निर्माण करवाया जा रहा हैं और वहां साईंस की क्लासिज शुरू हुईं। कोठी-कोढ में साईंस की क्लासिज शुरू हुईं और भवन बन रहा है। लुहारड़ी में साईंस की क्लासिज शुरू हुईं, भवन बन रहा है। वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। वहां के गरीब लोग कहां पढ़ें? मुख्य मंत्री जी ने

यह नब्ज टटोली और वहां ये शिक्षण संस्थान खोले। इसी तरह से आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने बैजनाथ मुल्थान में प्लस टू स्कूल दिया। मुल्थान में डिग्री कॉलेज भी दिया और बजट में बिल्डिंग के लिए प्रावधान भी किया। यह सब आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किया। क्या यह छोटी बात है? इसका विरोध करेंगे। कॉलेज क्यों खोल दिए? अरे, जिनको ज़रूरत है, उनको जाकर पूछो। वहां के बच्चे 70-80 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ते थे। किराये के मकानों में रहते थे। उनके कितने पैसे लगते थे? सब लोग नहीं पढ़ सकते थे। गरीब बेटियां नहीं पढ़ सकती थीं। उनको आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने सहूलियत दी। आप इस बात का विरोध करते हैं? अच्छी बात को तो अच्छी कहिए या विरोध ही करना है।

मैं पिछली सरकार के कार्यकाल के बारे में बताना चाहता हूं। उस वक्त श्री सुधीर शर्मा जी विधायक थे। गुनेड़ में स्कूल मिडल से हाई हुआ। आपकी सरकार ने वह डी-नोटिफाई कर दिया। शर्म आनी चाहिए। बाद में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वह हाई स्कूल हुआ और अब वहां बिल्डिंग बन रही है। बैजनाथ चुनाव क्षेत्र में 8-10 स्कूलों के भवन बन रहे हैं और करोड़ों रुपये वहां ख़र्च हो रहे हैं। आप इसका

15.03.2017/1645/SLS-AG-2

विरोध कर रहे हैं कि हमारी डी.पी.आर्ज़ ही नहीं बनती। चार सालों तक आप सरकार का विरोध करते रहे। सदन में बैठे नहीं, सरकार को चलने नहीं दिया और वॉक आऊट करते रहे। फिर आपकी डी.पी.आर्ज़ कहां बनेगी? हिमाचल प्रदेश में 75 डी.पी.आर्ज़. बनीं जिनमें से मेरी 15 मंजूर हुईं। यह बाबा बैजनाथ की कृपा है। साथ में मुख्य मंत्री जी की कृपा है। एक चुनाव क्षेत्र में एक साथ 15 डी.पी.आर्ज़. मंजूर होना, यह भगवान् की कृपा नहीं है तो और क्या है? आज बैजनाथ चुनाव क्षेत्र की सारी सड़कें बन रही हैं। आप यहां बैठकर रोना रो रहे हैं कि हमारी डी.पी.आर्ज़. नहीं बनती। वहां आपके लोग कहते हैं कि यह प्रधान मंत्री सड़क योजना है।...(व्यवधान)...मेरी एक सड़क बीड-बिलिंग-राजगुण्डा-बड़ागांव 24.71 करोड़ रुपये की मंजूर हुई। कंदराल पंचायत का एक सुडु गांव है और एक बाड़ है, वहां के लिए 3.20 करोड़ रुपया मंजूर हुआ। 35 करोड़ की सड़कें अभी मंजूर हुई हैं।

...(व्यवधान)...भाई साहब, यह सब इंपलीमैंट होंगी। आप कहते हैं कि हमारी डी.पी.आर्ज़. ही नहीं बन रही हैं। आप सदन में नहीं बैठे तो आपकी डी.पी.आर्ज़. कैसे बनेगी? ...(व्यवधान)...आप बैठे ही नहीं और मुख्य मंत्री जी का विरोध करते रहे। यहां **गला फाड़-फाड़ कर बोलते थे** कि वकामुल्ला कौन है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कौन निकला और क्या हुआ? ...(व्यवधान)... आप कहते थे कि अभी सरकार गिरने वाली है या कल सरकार गिरने वाली है। अरे, सवा चार साल हो गए और पांच भी पूरे हो जाएंगे। आप चिल्लाते रहे। चिल्लाते रहो। रौला डालते रहो, फिर यह सरकार सत्तासीन होगी क्योंकि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने विकास के आयाम कायम किए हैं।

इस पुस्तक के आंकड़े बताते हैं कि विकास हुआ है। यह आप भी मानेंगे। जो पिछले चार साल निकले, उनमें विकास हुआ है। आप भी मानो, आप भी मानो।

जारी ...श्री गर्ग जी द्वारा

15/03/2017/1650/RG/AG/1

श्री किशोरी लाल---जारी

अध्यक्ष महोदय, इनके समय में विधायक क्षेत्र विकास निधि सिर्फ 25,00,000/-रुपये मिलती थी, बहुत मुश्किल से पांच सालों में 50,00,000/-रुपये हुई और आज यह बढ़कर 1,10,00,000/-रुपये हो गई है। क्या यह अपने आप ही हो गई? इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करो। 5,00,000/-रुपये की विधायक ऐच्छिक निधि आपके समय में नहीं मिलती थी, लेकिन राजा वीरभद्र सिंह जी ने यह शुरू की। आज हम जहां जाते हैं, पैसे बांटते हैं। इसमें आपको भी फख्र होना चाहिए और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करिए। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि ये चीजें आपके ध्यान में नहीं हैं। आपने तो हमेशा विरोध करना है।

अध्यक्ष महोदय, ये हमेशा किसानों की बात करते हैं। किसानों की हितैषी कांग्रेस पार्टी है। मुजारों को मालिक किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जिन लोगों के पास एक मिर्च उगाने के लिए जमीन नहीं थी उन्हें 10-10 कनाल जमीन स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के समय में मिली। यह सोचने वाली बात है। यह किसने दी, कांग्रेस पार्टी ने दी। यहां मेरे भाई एक बड़ा मुद्दा लेकर आते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नियमित सेवाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है? उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अगर नहीं है, तो कोर्ट में जाइए। इसके अतिरिक्त आप जीतकर कैसे आए? अगर सीट आरक्षित नहीं थी, तो आप वहां से विधायक कैसे बने? आप कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करिए। कांग्रेस ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान रखा है तभी आप भी विधायक बनकर आ गए। अगर यह प्रावधान संविधान में नहीं होता, तो किशोरी लाल भी नहीं आता और आप भी नहीं आते। आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? हम लोग उस आरक्षण के कारण आ गए और डॉ. भीमराव अम्बेडकर की कृपा से आ गए। नहीं तो आपने भी नहीं आना था और मैंने भी नहीं आना था। वहीं रहने थे।

अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार राम मंदिर का मुद्दा उठाते रहे। लेकिन मंदिर कहां बना? अब चुनावों में फिर मुद्दा लेकर आ जाएंगे, राम का मंदिर बनाएंगे। क्या आप ही राम भगत हैं और हम नहीं हैं। लेकिन ये हर बार झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं लेकिन बनता इनसे कुछ भी नहीं है। ये तो भगवान को भी नहीं बख्शते, तो हमें कहां बख्शेंगे? जो इस प्रदेश में आज तक विकास की गंगा बही है वह कांग्रेस के कारण है।

15/03/2017/1650/RG/AG/2

ये स्वयं मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा राज किया। कांग्रेस पार्टी ने राज किया, तो विकास भी किया। ये लोग जब भी आते थे, तो कई लोग पांच साल भी पूरे नहीं करते थे और अढ़ाई साल में इनकी छुट्टी हो जाती थी। उसकी क्या वजह थी? अढ़ाई साल में इनकी सरकार क्यों गई? क्योंकि ये काम नहीं करते थे। इन्होंने वर्ष 1990 में एक बहुत बड़ा वायदा किया था, बड़े-बड़े कैलेण्डर छाप दिए थे, ये क्या कहते थे कि 'हर हाथ को काम देंगे', हर खेत को जल देंगे, हर रसोई में नल देंगे, सस्ता राशन गांव-गांव में देंगे, लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या हुआ? कहां गया हर घर का नलका, हर हाथ को काम कहां है, झूठे वायदे करने वालों से पूछो कि सस्ते राशन की दुकान कहां है? मुझे बताइए। बड़े-बड़े वायदे किए थे। हर

रसोई में नल, नल तो लग गए, लेकिन उनमें पानी नहीं था और उनमें फुस-फुस की हवा आती थी। इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर होता है। ये लोग केवल झूठे वायदे, झूठे नारे, झूठे लारे में बहुत माहिर हैं। इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। जितना झूठ ये बोलते हैं उतना मुकाबला हम नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे ज़हन में झूठ बोलना नहीं है। ये तो हर बार नया नारा लेकर आ जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, जो बजट आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पेश किया वह हर वर्ग के लिए और हर वर्ग के विकास के लिए है। ये जो खाद्यान सस्ती दालें नमक, तेल हमें सस्ता मिल रहा है, आदरणीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने वर्ष 2007 में इस योजना को शुरू किया था। इसके लिए भी 220 करोड़ रुपये बजट प्रस्तावित है। ये भी इसका फायदा लेंगे, सिर्फ कांग्रेस के लोग ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोग इसका फायदा लेंगे। इसमें आय की कोई लिमिट नहीं है, डॉक्टर, इंजीनियर और मजदूर सभी इसका फायदा लेते हैं। इसलिए यह योजना जारी है और इसका फायदा लोगों को मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, पेन्शन में किसी समय में बिल्कुल कम पैसे मिलते थे। कितने और किनको ये पैसे मिलते थे? यदि किसी को पेन्शन लगी हुई है और दूसरे व्यक्ति ने पेंशन लेनी है, तो जब वह आदमी मर जाता था उसके बाद दूसरे व्यक्ति का नंबर आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।

एम.एस. द्वारा जारी

15/03/2017/1655/MS/AS/1

श्री किशोरी लाल जारी-------

वह सामाजिक सुरक्षा पैंशन 450/-रुपये से 650/-रुपये हुई और अब बढ़कर 700/-रुपये हो गई है। इसी तरह से 80 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों की पैंशन 1200/-रुपये से 1250/-रुपये हो गई है। यह स्कीम भी कांग्रेस पार्टी ने और राजा वीरभद्र सिंह जी ने उन

लोगों के लिए चलाई है जो बिल्कुल असहाय और निर्धन हैं तथा इसका फायदा लोग ले रहे हैं। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि बजट में कुछ नहीं है। किसानों के लिए विशेष योजना-(व्यवधान)-आप लोग सुन लीजिए। आप लोग तार का विरोध कर रहे हैं कि तार नहीं लगनी चाहिए? अरे, क्या आवारा पशु आज ही आए या पहले भी थे? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये आज ही सारे आवारा पशु तैयार हुए हैं? कर्नल साहब भी बजट का विरोध करके गए कि प्रदेश में बहुत आवारा पशु हैं। क्या ये आवारा पशु पहले नहीं थे? इसी तरह से बंदरों के बारे में भी कहा, क्या बंदर भी पहले नहीं थे? -(व्यवधान)-हां, इन सालों में ही आए पहले तो कुछ नहीं था। पांच साल आपकी सरकार रही, तब कुछ नहीं था। मैं कहता हूं कि आवारा पशु और बंदर तब भी थे लेकिन उस वक्त अगर बंदरों को मारने के लिए कानून बनाते तो आपने जय श्रीराम का नारा लगाते हुए आ जाना था कि ये राम के भक्त हैं इनको मत मारो। पहले भी बंदर थे लेकिन किसान स्वयं उनके लिए खेतों में पहरा देते थे। किसान खेत में झुग्गियां डालकर रात को भी पहरा करते थे। आज कौन करता है? आज तो वे अपने खेत में पानी ढूंढते हैं कि वह भी हमें सरकार ही लाकर दे। मैं भी किसान हूं और खेती-बाड़ी करता हूं। आप लोग चलिए मैं आपको फसल दिखाता हूं कि कितनी अच्छी फसल है। मेरे भाइयो, खेतों की सुरक्षा के लिए बाड़ लगानी पड़ती है और पहरा देना पड़ता, बातें करके थोड़े ही होगा। आज हर किसान चाहता है कि मेरे खेत में पानी पहुंच जाए और पॉलिटिशियन ही घर में अच्छी-अच्छी खाद और बीज रखकर जाए बल्कि सोचते हैं कि आप ही खेत में बीजाई भी करके आओ और वे फिर फसल ही काटने जाएंगे। जब हम स्वयं काम करेंगे तब कुछ होगा। बातों से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस सरकारों ने किसानों के खेतों की सुरक्षा करने के लिए बहुत कुछ दिया है। बाड़बन्दी पर 80 प्रतिशत सब्सिडी है और किसान को केवल 20 प्रतिशत लगाना पड़ेगा। इसमें क्या बुरी बात है? किसान अपने खेतों में तार लगाए, मैं भी लगाऊंगा बल्कि मैं आपको नमूना पेश करूंगा कि मैंने तार लगाई है। मेरा घर नजदीक ही है, आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैं लगाकर बता दूंगा। इस योजना का भी किसान को फायदा मिलेगा।

15/03/2017/1655/MS/AS/2

आज किसानों के लिए पावर टिल्लर हैं और उसके लिए भी सब्सिडी रखी हुई है। इसी तरह से बीज के लिए भी सब्सिडी है। हम खेतों में स्प्रे करते हैं उसके लिए भी सब्सिडी है।

किसानों के लिए ये लाभकारी योजनाएं हैं और किसान/बागवानों के लिए साथ में मण्डियां हैं। वे मण्डियों में अनाज पैदा करके बेच सकते हैं। बे-मौसमी सब्जियां उगाकर भी किसान फायदा ले रहे हैं। उसके लिए बजट में प्रावधान है। जैविक खेती के लिए भी प्रावधान है और यह आज की जरूरत भी है क्योंकि जो हमें दूसरे फर्टिलाइजर मिलते थे उससे खेती कम होने लगी है। इसलिए जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहन योजना सरकार ने शुरू की है। इसी तरह से उत्तम चारा योजना है वह भी किसानों के लिए ही है और किसानों को उसका लाभ लेना चाहिए।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो पशु हैं वे कैसे निकम्मे हुए? सरकारों ने ऋण देकर पशु दे दिए लेकिन जिन लोगों के पास चारे के लिए पैसे नहीं थे वे उस चारे को पूरा नहीं कर सके। तूड़ी का भाव 8/-रुपये और 10/-रुपये किलो है। इसलिए पशु पालने में लोग असमर्थ हुए। साथ में जब पशु का गर्भाधान होता है तो अनट्रेंड लोग भर्ती होकर आ गए। -(व्यवधान)-यह बी0जे0पी0 के समय में हुआ है। कई फार्मासिस्ट लग गए जिनको टीका लगाना नहीं आता था। उस वजह से आज गायें सड़कों पर आ गई हैं। गाय दूध दे तो हमारी और सूख जाए तो सरकारी। इसलिए गायें बाजारों में घूम रही है। ये गायें किसने छोड़ी, ये हमारे लोगों ने छोड़ी। अब वह नारा कहां है कि गाय हमारी माता है? अरे, हिन्दुओं को शर्म आनी चाहिए। कहां गई वह माता? 84 हजार देवी-देवताओं का वास गाय में बताते थे। ये गायें भी हमारी हैं। अगर एक-एक किसान एक-एक आवारा पशु को बांध ले तो सारी समस्या का हल हो जाएगा लेकिन कौन बांधे, कोई नहीं बांधता।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री किशोरी लालः दूध निकालकर गाय को बाजार में छोड़ जाएंगे और जब दुबारा,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

15.03.2017/1700/जेके/डी0सी0/1

अध्यक्षः-----**जारी**------

अध्यक्षः अभी चार माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। आप लोग कितने बजे तक बोलेंगे? छः बजे तक बोलेंगे?

अब इस सभा की बैठक का समय 6.00 बजे तक बढ़ाया जाता है। Kindly try to wind up.

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं गाय के बारे में बात कर रहा था। गाय तो छोड़ी ही लेकिन बैल भी लोगों ने छोड़ दिए। जो गाय बछड़ा देती है उसको कोई नहीं पालता, क्यों नहीं पालता क्योंकि पॉवर ट्रिलर आ गए। अब बैलों का ज़माना नहीं रहा। नैचुरली बैल फिर बाज़ारों में आएंगे। इसके लिए कोई योजना बनाई जाए जहां पर बैलों का इस्तेमाल हो। (व्यवधान) बजट में प्रावधान होगा या नहीं होगा लेकिन बैल कहां जाएं? वे हम लोगों के बैल हैं, वे कहां जाएं? उसमें आप लोग भी शामिल हैं। आपकी गाय भी जब बछड़ा देती होगी तो आप लोग भी छोड़ देते हैं। ये समस्या हम लोगों ने पैदा की है। इसमें सरकार का दोष नहीं है। कोई चार सालों में ही गाय और बैल नहीं आ गए, ये पहले से ही थे। चार सालों में बन्दर भी नहीं आ गए, पहले भी बन्दर हुआ करते थे। लोग उनको छलियां व चने डालते थे। आज उनको कोई नहीं डालता है। उन्होंने भी तो पेट भरना है और उनको भी जीने का अधिकार है। इसी तरह से मैं अब रिजर्वेशन पर आ रहा हूं। मेरे भाई हंस राज जी और दूसरे मेरे एस0सी0 साथी, वे सभी मेरे भाई हैं। आपके जो भारतीय जनता पार्टी के आर0एस0एस0 के प्रमुख थे, मोहन भागवत जी वे रिजर्वेशन के विरोधी थी। वे कहते थे कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि अगर कोई गरीब ब्राह्मण है, गरीब राजपूत है, उसको भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। गरीब कोई भी परिवार है, उसको आगे बढ़ने का अधिकार है। उसको क्यों न रिजर्वेशन मिले ? मैं तो इस हक में हूं कि सबको रिजर्वेशन मिले। उसका विरोध आप लोग क्यों करते हैं? मैंने वह

15.03.2017/1700/जेके/डी0सी0/2

सरकारें देखी हैं, जब किसानों का यहां पर विरोध होता था। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता था और किसानों के ऊपर घोड़े दोड़ाते थे। वह कौन सी सरकार थी? 27 परसेंट रिजर्वेशन ओ0बी0सी0 को मिलनी थी। वर्ष 1990 में वी0पी0 सिंह जी प्रधान मंत्री थे। यहां पर किसकी सरकार थी, क्या उसका विरोध हुआ? आप किसके हितैषी हैं? आप न तो एस0सी0 के हितैषी हैं, न ओ0बी0सी0 के हितैषी हैं । आप लोग तो हर बात का विरोध करते हैं। यहां पर जो अच्छी बातें हैं उनका भी आप विरोध करते हैं। पैंशन बढ़ी है, आप नहीं कहेंगे कि अच्छा हुआ। आप लोग किस वर्ग के हितैषी हैं। आप किसी भी वर्ग के हितैषी नहीं है। आप तो सिर्फ कुर्सी के हितैषी हैं। जब कुर्सी मिल जाती है तो उस वक्त सब कुछ भूल जाते हैं। उस वक्त यह कहावत चरितार्थ होती है कि अंधा मांगे रेवड़ियां मुड़-मुड़ कर अपनों को दें। उस वक्त यह कहावत याद आती है। मैंने भाजपा की सरकारें भी देखी हैं। मुझे बहुत सी सरकारों को देखने का मौका मिल गया है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक गरीबों का उत्थान किया है। गरीबों को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी ने समाज में एक समानता लाई है। यह बजट जो आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है इसका मैं समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ।

15.03.2017/1700/जेके/डी0सी0/3

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य, आप समय का ध्यान रखें। अभी तीन लोग और बोलने वाले हैं।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, परन्तु कुछ चन्द बिन्दु जो सत्ता में बैठे हैं, इनको बताना चाहता हूं। रवि ठाकुर जी बोल रहे थे कि यह बजट लोगों के दिलों में राज करता है । लोगों के दिलों में राज करना तो मोदी जी से सीखो। आप लोग सुनो ज़रा। नोट फेंक कर तो सब वोट लेते आए हैं, परन्तु नोट बन्द करके वोट लेना कोई सीखे तो मोदी जी से सीखे। आप लोग कहां रहते हैं? बुरा नहीं

मानना बजट है। मेरे बड़े भाई किशोरी लाल जी कह रहे थे कि राशन सस्ता दे रहे हैं और यह योजना चलाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह योजना किसने पहले चलाई थी? हिन्दुस्तान में इस योजना को ले कर कौन आया था? आप लोग भूल गए। आदरणीय शांता कुमार जी जब केन्द्र में खाद्य मंत्री हुआ करते थे उस समय यह योजना आई थी।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

15.03.2017/1705/SS-DC/1

बिक्रम सिंह जरयाल क्रमागतः

आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। --(व्यवधान)-- यह बजट एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 विरोधी है और जनरल विरोधी भी है। निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग, नौजवान वर्ग, कर्मचारी वर्ग, किसान वर्ग, बागवान वर्ग, व्यापारी वर्ग, सभी वर्गों का विरोधी बजट पेश किया है। क्यों? अभी किशोरी लाल जी जनरल की बात बोल रहे थे। मैं आपको बताता हूं कि जब पिछली मर्तबा धूमल साहब सी0एम0 थे तो जनरल कैटेगिरी के आदमी जो आई0आर0डी0पी0 और बी0पी0एल0 परिवार में थे तो घर-मकान बनाने के लिए पैसा मिलता था। आपको यह याद होना चाहिए। आज उनको पैसा नहीं मिलता। जनरल कैटेगिरी के लोग गरीब होते हैं, मैं इस बात को मानता हूं। परन्तु आज तक उनको न एक पैसा रिपेयर के लिए मिल रहा है और न घर बनाने के लिए मिल रहा है। उनके लिए इस बजट में भी कुछ प्रावधान नहीं है। सर, जनरल के लिए नहीं मिल रहा है। जनरल को अगर मिल रहा है तो वह 2 परसैंट सैंटर दे रहा है। अब हिमाचल प्रदेश की जनता और नौजवान का भरोसा इस सरकार से उठ गया है। बुरा न मानना, बजट है, मैं दो शब्द कहूंगा। मैं भरोसा उठने की बात कर रहा हूं। याकूब को फांसी हुई तो सुप्रीम कोर्ट से आपका भरोसा उठ गया। याकूब को माफी नहीं मिली तो आपका राष्ट्रपति से भरोसा उठ गया। सर्जिकल स्ट्राईक के सबूत नहीं दिए तो आपका आर्मी से भरोसा उठ गया। चुनाव में हार गए तो

ए0वी0एम0 मशीन से भरोसा उठ गया। कमाल है, क्या बात है। अब इस बजट से हिमाचल प्रदेश की जनता का भरोसा उठ गया है। इसलिए अगली बार कांग्रेस से भी भरोसा उठ जायेगा।

सर, जंगली जानवरों की बात हो रही थी। किशोरी लाल जी बोल रहे थे। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग सरकार में बैठे हैं लेकिन जंगली जानवरों, आवारा पशुओं के लिए इस बजट में कोई योजना नहीं बनाई। इस बजट में कुछ नहीं है। किशोरी लाल जी ने खुद बोला कि इस बजट में कुछ नहीं है। उन्होंने बोला है। रिकॉर्ड में आया है। अध्यक्ष महोदय से रिकॉर्ड चलाकर देख लो। उसमें यह आया है।

15.03.2017/1705/SS-DC/2

कोई योजना नहीं बनाई। यहां तक बोलते हैं कि जंगली जानवर को मार दो। परन्तु आप लोगों ने गन के लाइसैंस बंद कर दिए हैं। आप लोगों की यह योजना है। किसानों के प्रति आपकी यह वफादारी है। आप लोग किसानों को क्या देना चाहते हैं? जिनके पास गन लाइसैंस हैं उसको रिन्यू करने की आप लोगों ने फीस बढ़ा दी। इस बजट में यह ज़रूर किया।

अभी पीछे गौसदन बनाने की बात हुई। सैंटर से वित्तायोग का पैसा आया। जो बेचारे नए बी0डी0सी0 मेम्बर जीत कर आए थे, उनको कहा कि गोसदन बनाने के लिए पैसा देने के लिए साइन करो, उन्होंने साइन कर दिए। परन्तु गौसदन आज तक नहीं बने। इससे ज्यादा फेल्योर का उदाहरण और क्या हो सकता है।

एजुकेशन की बात बताता हूं। गप्पे मारने से प्रदेश नहीं चलता। सब कुछ आउटसोर्स से, जुगाड़ से, माफिया और कर्ज़ के सिर पर सरकार चल रही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। अगर मैं बोलता हूं तो बुरा मत मानना क्योंकि बजट है। अगर मंत्रियों, विधायकों, आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 और मास्टरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो अपने आप एजुकेशन का

स्टैंडर्ड बढ़ेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी। लाओ कानून, हम उसका समर्थन करते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आदरणीय धूमल जी ने एक यूनिवर्सिटी ककीरा-भड़ेला में दी। आपकी सरकार आई तो बंद कर दी ।

जारी श्रीमती ए0वी0

15.3.2017/1710/av/as/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल---------- जारी

मैं मान्य न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि हम वह केस जीत गये परंतु सरकार चुप बैठी है। यह सरकार नहीं चाहती कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लें और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको रोजगार मिले। यहां पर स्कूल/कालेज को अपग्रेड करने की बात कही गई, कोई फायदा नहीं है। एक बच्चा ग्रेजुएशन करके क्या करेगा? यहां पर तकनीकी शिक्षा पर जोर देने की जरुरत है। तकनीकी शिक्षा की बात करूं तो आदरणीय धूमल जी के समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक आई0टी0आई0 खुली थी जिसमें तीन ट्रेड शुरू किए गए थे मगर आज भी वहां पर वही ट्रेड चले हैं। इस सरकार ने ऐजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। स्कूल खोल दिए मगर वहां पर मास्टर नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। यहां पर कर्नल साहब ठीक बोल रहे थे। मुझे भी कालेज दिया और उसके लिए मैंने मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद किया तथा रिक्वैस्ट भी की कि पहले बजट का प्रावधान कीजिए। बिल्डिंग का प्रावधान कीजिए उसके बाद कालेज खोलना मगर नहीं, एक कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कालेज खोल दिया। वहां पर पढ़ रही कन्याएं डिस्टर्ब हुई और फिर उनको दूसरे प्लस टू स्कूल में भेजा गया। वहां पर न तो वे कन्याएं पढ़ सकीं और न ही वे बच्चे जिन्होंने उस कालेज में ऐडमिशन ली। वहां पर लोग उसके लिए भूमि डोनेट करते रहे मगर नहीं ली गई। वहां मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कमाऊ पुत्र बना रखा है उसकी जगह के साथ भूमि का चयन किया ताकि उसकी लैंड वैल्यू बढ़ जाए।

वहां पर न तो कोई रोड कनैक्टिविटी है, स्लाइडिंग एरिया है और जंगल में जाकर कालेज खोल रहे हैं। बड़े शर्म की बात है और आप यहां पर शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बातें करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि बातें कम करो और काम ज्यादा करो, इसलिए ही आपकी वाहवाही होगी। अब आने वाले समय में वोटों के नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है और फिर आप बोलेंगे कि यह क्या हो गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 13 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। 77 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास बिल्डिंग तो है मगर उसके नाम पर जगह

15.3.2017/1710/av/as/2

नहीं है। स्कूलों में लाइट और बैठने की व्यवस्था नहीं है। मैं उसके लिए कई बार रिक्वैस्ट कर चुका हूं।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है, आप मुझे सुन लेना। मेरी एक 1964 की पी0एच0सी0 समोठ है वह कम-से-कम 17 पंचायतों को फीड करती है। उसके लिए लोग बहुत बार मिले, डेपुटेशन मिले। हमने रिक्वैस्ट की और उस बारे में विधान सभा में प्रश्न भी लगाये मगर उसमें लिखा है कि अब प्रस्ताव आया है क्योंकि अब चुनाव आ गये हैं। जब चुनाव नजदीक है तो प्रस्ताव तो आना ही था। अभी तो प्रस्ताव ही पहुंचा है और मगर वह बनेगी नहीं। मैंने कुछ और जगह पर भी सब हैल्थ सैंटर मांगे थे। जदरोग-परसयारा, कथयाड़ी, कुफरी, धांगग्रा, रखेड़-चक्की; इन जगहों पर भी उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए जाएं तो लोगों को सुविधा प्राप्त हो सकती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस समय स्वास्थ्य क्षेत्र में 76 पद खाली चले हुए हैं। चुवाड़ी सिविल होस्पिटल है और वहां पर 8 पोस्टें सैंक्शन्ड हैं मगर वर्तमान में केवल तीन डॉक्टर उपलब्ध है। (---व्यवधान---) नहीं सर, एक ने वहां पर क्लिनिक खोल रखा है। उसकी लिखित शिकायत भी हुई मगर आपने उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया। उसने अपना क्लिनिक खोल रखा है और उधर देखता है। वह कहता है कि उधर आना और वहीं पर आपरेशन होगा यहां नहीं होगा। यहां पर आई0पी0एच0

मिनिस्टर नहीं बैठी हैं। यहां पर किशोरी लाल जी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा प्रावधान है। मैं किशोरी लाल जी से पूछना चाहता हूं कि यह आई0पी0एच0 विभाग किसने खोला? भूल जाते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। वहां सोर्स से 100 प्रतिशत पानी चलता है और जहां वह पानी पहुंचना होता है वहां दस प्रतिशत भी नहीं पहुंचता क्योंकि जगह-जगह से पाइप लाइन्ज टूटी हुई हैं। पाइपें जंग खा गई है। मेरी 177 स्कीमें ग्रेविटी लाइन्ज की हैं और उनमें कोई फिल्टर बैड नहीं है। दो स्कीमें डब्ल्यू0एस0एस0 की हैं मगर उनमें कोई ट्रीटमैंट प्लांट नहीं है। यहां पर आप अच्छी सुविधा की बात कर रहे थे। यहां पर शिमला यानि राजधानी में अश्वनी खड्ड का पानी पिलाया गया।

श्री वर्मा द्वारा जारी

15/03/2017/1715/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल.... जारी।

रोड बनाने के नाम पर ठेकेदार 66 करोड़ रूपये का चुना लगा गया, उसने कुछ भी काम नहीं किया। वह अपना आदमी था। अब वोट भी अपनों से ही ले लेना, जनता से मत मांगना। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार ,चोरियां, रेप, देशद्रोही, महिलाओं से छेड़छाड़ के मकदमें पिछली साल से 40 परेंसट बढ़े हैं। मैं आपको कानून-व्यवस्था का एक उदहारण देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पंडित रतन चन्द था, उनको मार कर फेंक दिया गया। उनकी डैडबॉडी 8 दिन के बाद मिली। ये बात दिनांक 28 मार्च, 2015 की है और इसका एफ0आई0आर0 नम्बर- 13/15 है। आज तक उस केस को दबाकर रखा गया है। वहां पर जो आई0ओ0 था उसको वहां से बदल दिया गया। ये लोग अच्छे ऑफिसर को रहने नहीं देते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी चोरियां हुई हैं, उनमें से एक भी चोरी आइडैंटिफाई नहीं हुई हैं, क्योंकि उसमें पुलिस वाले पहले ही मिल जाते थे। और जो चेयरमेंन बनाया होता था, वह कह देता था कि चोरी कर लेना, 20 परसेंट मुझे दे देना और 20 परसेंट आप ले लेना और केस को दबा देना। मेरे चवाड़ी थाने में एक अच्छा एस0एच0ओ0 आया और उसने

शराब की 2 गाड़ियां पकड़ी, लेकिन वह अपना आदमी था, उसका केस दबा दिया गया और एस0एच0ओ0 की बदली कर दी गई। मैं आपको शिमला के बारे में बताना चाहता हूं। यहां के जो एस0पी0, डी0डब्ल्यू नेगी हैं, उन्होंने मेरे लड़के की गाड़ी रोकी, उसको नीचे उतार कर डराया-धमकाया। आप एम0एल0ए0 के लड़के हो, युनिवर्सिटी में आप दादागिरी कर रहे हो। पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा। बाद में कहने लगे कि हाईकोर्ट के आदेश हैं, नहीं तो आपको जेल में डाल देता। ये हाल, इनके एस0पी0, शिमला का है। जब वह किन्नौर में एस0एच0ओ0 था, आने-जाने के साधन नहीं थे तो उनको खर्चा हमारा परिवार देता था। आज वह भूल गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उनके ऊपर हाथ हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तहसीलें दी हैं, मगर तहसीलदार/स्टॉफ नहीं दिया, सिर्फ फ़टा लगा दिया। हम कई बार मांग कर चुके हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सिविल कोर्ट होना चाहिए। सर्दियों में बर्फ पड़ने के कारण डलहौजी और चम्बा नहीं जा सकते हैं। मैंने प्रश्न लगाया, तो जवाब आया इस पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

15/03/2017/1715/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

मैंने फायर स्टेशन की बात की तो कहने लगे कि नुरपूर/डलहौजी में हैं, उधर से मंगवा लो। फिर कहते हैं विकास हुआ है। सड़कों का हाल देखो। सड़कों में खड्डे नहीं खड्डों में सड़क हैं। मेरा एक चवाड़ी सब-डिविज़न है, उसको जाने के लिए एक मात्र रास्ता कालीधार से हैं। मुझे प्रश्न लगाते-लगाते 4 साल हो गये हैं कि इसको थोड़ा तो ठीक करो, कॉलेज उधर हैं, हैड क्वॉटर वहां पर है, लोगों का आना-जाना बंद हो जाता है, लेकिन उस पर सरकार ने कोई गौर नहीं किया। जहां तक डी0पी0आरज0 की बात है, मेरी आज तक पिछले 4 सालों में आई0पी0एच0/पी0डब्ल्यू0डी0 या कोई अन्य डी0पी0आर0 नहीं बनी हैं। हिमाचल प्रदेश का 75 प्रतिशत बजट हिमाचल प्रदेश का जो हारे हुए लोग हैं, क्योंकि मुख्य मंत्री जी को मंत्रियों और विधायकों पर भरोसा नहीं है। इसलिए रिटायर्ड ऑफिसर लगाये हुए हैं, उन पर खर्च किया जा रहा है। लोगों को कहां से सड़कें बनेगी, कहां से शिक्षा/स्वास्थ्य का सुधार होगा, कहां से लोगों को ठीक पीने का पानी मिलेगा? मेरा अनुरोध रहेगा,

श्रीमती एन0एस0... द्वारा जारी।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल ----जारी

माननीय मंत्री जी आप भी यहीं बैठे हैं और मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस फौज़ को थोड़ा कम कर दो। आपको अपने वर्तमान अफसरों के ऊपर विश्वास होना चाहिए। मुख्य मंत्री महोदय को आप विधायकों और मंत्रियों के ऊपर विश्वास ही नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बाईंड अप करने की कोशिश कीजिए। आप बोलिए मगर थोड़ा संक्षेप में बोलिए।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : जहां तक पर्यटन की बात है तो हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत सौंदर्यशील प्रदेश है। जिला चम्बा में डलहौजी और खजियार पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छे पर्यटक स्थल हैं लेकिन इस बजट में इन क्षेत्रों के लिए कोई राशि नहीं दी गई है। मुझे नहीं पता कि यह बजट कहां जाता है? मेरे क्षेत्र में बिजली का भी बड़ा बुरा हाल है। अभी तक पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली की तारें पेड़ों के साथ लगी हुई हैं। वहां पर थोड़ी-सी हवा चलती है तब पेड़ हिलता है और बिजली चली जाती है। मैंने यह बात लिख करके भी दी है कि कई जगहों पर 4-4 फुट के खम्बें हैं। पीछे मेरे क्षेत्र में एक खच्चर मर गई तब बिजली बोर्ड वालों ने कहा कि यह खच्चर हमारी लाईन से नहीं मरी है। मैंने बिजली बोर्ड वालों को पूछा कि यह लाईन कहां से आई है, क्या यह लाईन आपने नहीं बिछायी है। अध्यक्ष महोदय, परिवहन की दृष्टि ये लोग बोलते हैं कि हमने बहुत बसें लगाई हैं। बसों के लिए केंद्र सरकार ने बहुत पैसा दिया है। वर्तमान सरकार ने बसें खरीदी हुई हैं लेकिन उन बसों को चलाने के लिए इम्पलायीज़ नहीं हैं। कई सड़कें भाजपा के समय की बन करके तैयार हुई हैं लेकिन वहां पर बसों की सुविधा नहीं है। मैं आदरणीय प्रो0 धूमल जी और माननीय श्री शान्ता कुमार जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने महिलाओं के लिए काफी अच्छी योजनाएं शुरू की थीं। इन्होंने महिलाओं के लिए रक्षा बन्धन और भाई दूज की छुट्टी भी दी

है और प्रदेश की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी है। पीछे मेरे क्षेत्र से मेरे पास एक कम्पलेंट आई कि हम बस के लिए

15/03/2017/1720/ एन0एस0/ए0एस0 /2

खड़ी थीं और ड्राईवर ने बस नहीं रोकी। इसके लिए ड्राईवर बोलता है कि ये मुफ्त की सवारियां हैं इनको ले करके नहीं जाना है। आपने छात्रों को परिवहन की सुविधा दी है। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्कूल के छात्रों के लिए कोई बस लगी ही नहीं है, उन्हें इस सुविधा का कोई फायदा नहीं है। यह सब झूठी घोषणायें हैं और कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस मान्य सदन में रोज़गार के ऊपर बोलूंगा। इस मान्य सदन में आदरणीय श्री इन्द्र सिंह जी ने ठीक कहा है कि नौजवानों के साथ धोखा किया है। इस सरकार ने लोगों को बैक-डोर से रोजगार देने की भरपूर कोशिश की है। 'No Roster, No Merit' अगर रोस्टर नहीं था तो मेरिट के हिसाब से उम्मीदवारों को रखना चाहिए था। मुझे इस बात का बहुत दुःख है। इसमें दलित, एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 और जनरल सब आते हैं। आप जनरल कैटेगिरी वालों को मेरिट पर तो रखते आपने वे भी नहीं रखे। आपने भाई-भतीज़ावाद के आधार पर ही भर्तियां की हैं। आप कहते हैं कि ये भर्तियां परमानैंट हुई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भर्तियां परमानैंट नहीं हैं सबको आउटसोर्स पर रखा गया है। आउटसोर्स के ठेके यह सरकार अपने खास आदमियों को देती है। उनको केंद्र सरकार बीस हजार रूपया देती है और वे दस हजार उन आउटसोर्स कर्मचारियों को देते हैं और बाकी पैसा अपनी जेब में डालते हैं। ये लोग प्रदेश को लूट रहे हैं। ये लोग नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने बजट में सब कुछ दिया है।

Speaker: Please, wind-up now.

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने आंगनबाड़ियां कहां खोली हैं? इन्होंने आंगनबाड़ियां ऐसी जगह पर खोली हैं जहां पर एक घर है और वह कार्यकर्त्ता

कांग्रेसी है। उसे इन्होंने चार लाख का मकान भी दे दिया है और साथ में आंगनबाड़ी भी दे दी है लेकिन वहां पर कोई बच्चा नहीं है। लोगों ने बच्चों को वहां डाला है जहां से गांव 6 किलोमीटर दूर है। क्या सरकार ने आंगनबाड़ी खोलने के लिए

15/03/2017/1720/ एन0एस0/ए0एस0 /3

क्राईटीरिया पूरा किया है? मैंने बहुत बार इसके लिए प्रश्न लगाया है। कई बार मैंने माननीय मंत्री जी को लिख करके भी दिया है। No action has been taken ttill date. इस सरकार का बड़ा बुरा हाल है और फिर कहते हैं कि हमने यह किया, वो किया मेरे पास इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको लेआउट कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम बात बोलना चाहता हूं कि इस सरकार ने चम्बा का शिकरी धार प्लांट वर्ष 2014 में डिनोटिफाई कर दिया था। यह बहुत शर्म की बात है।

श्री आर0के0एस0 -----जारी।

15/03/2017/1725/RKS/As/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल...जारी

अगर चम्बा के शिकरी धार में सीमेंट प्लांट लग जाएगा, वहां पर अच्छी क्वालिटी का लाईम-स्टोन भी है, तो जिला चम्बा की पूरी बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। इसके लिए सैंटर ने पैसा देना है और आप डी.पी. आर. बनाने का काम करो।

Speaker: No more recording, please. Because you are not going to stop There is a limit. ...(Interuption)..... No recording.

15/03/2017/1725/RKS/As/2

अध्यक्षः अब श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अध्यक्ष महोदय, जो 10 मार्च, 2017 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किये हैं, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा जो छठी बार प्रदेश के मुख्य मंत्री बने और उन्होनें अपने जीवनकाल का 20वां बजट पेश किया। साथ ही जो उन्होंने साढ़े चार घंटे खड़े होकर इस सदन में बजट प्रस्तुत किया उसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं। यह सबसे बेहतरीन बजट है। इसमें सभी वर्गो, विभागों, कर्मचारियों और यहां तक कि विधायकों का भी हित रखा गया है। मेरे से पूर्व पक्ष और विपक्ष के कई वक्ताओं ने बजट पर काफी विस्तार से चर्चा की है। मैंने विपक्ष के तकरीबन सभी वक्ताओं को बोलते हुए सुना। कुछ विधायकों ने इस बजट में कुछ बातों पर, जैसे एम.एल.ए. फंड जो बढ़ा, उसका धन्यवाद किया। परन्तु कुछ सदस्यों ने तो किसी भी बात की तारीफ नहीं की। उनका कहना है कि यह बजट तो बेस्ट पेपर है, यह गलत बात है। मेरे से पूर्व जरयाल जी बोल रहे थे और मैं सोच रहा था कि वे जो एम.एल.ए. फंड बढ़ा, नाबार्ड की बात आई जिसमें 70 करोड़ से 80 करोड़ रुपये की बात हुई उसका धन्यवाद करेंगे। लेकिन इन्होंने भी धन्यवाद नहीं किया। मुझे याद है श्री गोविन्द राम शर्मा जी और कुछेक माननीय सदस्यों ने एक-दो बातों के लिए धन्यवाद किया था। जहां तक विपक्ष की बात है, आप अवश्य विरोध करें। यह आपका राइट है। लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो सभी के हित की हैं, उन बातों का आपको धन्यवाद करना चाहिए। बजट भाषण के पैरा 98 में जो 61 नेशनल हाईवे की बात का जिक्र किया गया है, जो नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश को दिए गए हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने इसमें स्पष्ट कहा है My Government is grateful to the Union Government for the 'in-principle' approval for declaration of 61 roads as National Highways with certain conditionalities. मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को भी अच्छी बातों का धन्यवाद करना चाहिए। जो हमारा एम.एल.ए. फंड है, वर्ष 2012-13 में हमें 50 लाख के करीब मिलता था, जिसको पिछले चार वर्षों में 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया गया है। यह माननीय राजा साहब के आशीर्वाद से ही हुआ है।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

15.03.2017/1730/SLS-DC-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा... जारी

इस बजट में इसमें 10 लाख रुपये और बढ़ा दिए। आप इसका तो धन्यवाद करते, लेकिन आपने नहीं किया। इसमें राशि बढ़ाने के अलावा रिलैक्सेशन भी दी गई है। इससे पूर्व हम इस राशि से स्कूलों के लिए, स्टुडैंट्स के लिए, स्पोर्ट किट्स के लिए तथा यूटैंसिल और फर्निचर खरीदने के लिए राशि नहीं दे सकते थे जबकि अब इसमें रिलैक्सेशन दी गई है। इससे हमें लाभ होगा और इसके लिए हमें माननीय राजा साहब का धन्यवाद करना चाहिए था।

नाबार्ड में भी अब डवलपमैंट के लिए धनराशि को 70 करोड़ से 80 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है। इसके लिए भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। मेरे ख़याल में अभी तक जितने भी सदस्यों ने यहां पर चर्चा की है उनका कहना है कि 4 सालों तक उनकी एक भी डी.पी.आर. नहीं बनी। मुझे पता नहीं यह बात सत्य है या गलत है। मैं नहीं कह सकता कि ऐसा हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ होगा तो इसके लिए इनका अपना कोई दोष होगा या कोई कमी रही होगी। इसमें सरकार का क्या दोष है इसलिए इस बारे में सरकार को नहीं कोसना चाहिए।

मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय धूमल जी यहां पर नहीं हैं। मैं उनका आदर और सम्मान करता हूं। कुछ दिन पहले यहां पर बात आई थी कि रोहड़ू में एजिटेशन चला था और उस समय राजा साहब वहां के एम.एल.ए. थे। वहां ऐसा कहा गया कि सेव आलु उगाओ, कांगड़ियों को भगाओ। कह रहे थे कि मल्होत्रा कमीशन की रिपोर्ट में लिखा था कि वहां 22 दुकानदारों की दुकानें खाली करवाई गई थीं या उनको छोड़नी पड़ीं। उस समय मैं चुप रहा और इसलिए चुप रहा क्योंकि मुझे फैक्चुअल पोजिशन का ज्ञान नहीं था। सोचा कि शायद ऐसा हुआ होगा। आज मैंने वैरिफिकेशन की है और मुझे बताते हुए खुशी

होती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज मैं इस सदन में बताना चाहता हूं कि जहां तक रोहडू बाजार की बात है, रोहडू बाजार में जो मैज़ोरिटी

15.03.2017/1730/SLS-DC-2

शॉपकीपर हैं they belong to Kangra, ---(interruption)--- कांगड़ा और दूसरी जगह के हैं। ऊपरी शिमला के बहुत कम हैं। ...(व्यवधान)... यह गलत बात थी। मैंने वैरिफाई किया है, ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है कि कोई छुटपुट घटना हुई हो, लेकिन यह बात गलत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बजट की बात है, इसमें मुख्य कार्य बेरोज़गारों को भत्ता देने का है। इससे हमारे हजारों बेरोज़गारों को लाभ मिलेगा। इसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 10+2 के बेरोज़गारों को 1000 रुपये और डिसएब्लड परसन को 1500 रुपया भत्ता दिया है। यह बहुत सराहनीय कदम है। साथ-ही-साथ इसमें 19000 से अधिक संख्या में नौकरियां देने का वायदा किया गया है जो कि एक सराहनीय कदम है।

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय राजा साहब के पिछले 4 सालों की परफार्मैंस है, इसमें हजारों की संख्या में नौकरियां दी गई हैं। इसका भी खासकर विपक्ष के सदस्यों ने कोई ज़िक्र नहीं किया; सिर्फ़ अपोज किया। आप हर बात में अपोजीशन, हर चीज में अपोजीशन कर रहे हैं। जब मैं शुरू में एम.एल.ए. बन कर आया था, मैंने सोचा था कि शायद ऐसा करना पड़ता होगा; अपोजीशन का काम अपोज करना ही होता होगा। लेकिन ये तो हर चीज में अपोजीशन ही कर रहे हैं। हो सकता है कि मुझे इतना ज्यादा ज्ञान न हो और ऐसा करना ही पड़ता हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 सालों में 3 मैडिकल कॉलेज नाहन, चम्बा और हमीरपुर में खोले गए। इसका भी किसी ने धन्यवाद नहीं किया। यहां पर बोलते हैं कि मैडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं लेकिन पी.एच.सी., सी.एच.सी. में डॉक्टर्ज़ नहीं हैं।

जारी ...श्री गर्ग जी द्वारा

15/03/2017/1735/RG/DC/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा---जारी

हो सकता है कि कहीं छोटी-मोटी ऐसी जगह बची होगी जहां डॉक्टर न हों। हमारे क्षेत्र भी हैं। मेरे यहां भी कई जगह ऐसी हैं जैसे सिविल अस्पताल, रोहड़ू है वहां भी पूरे डॉक्टर्ज नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं डॉक्टर्ज या टीचर्स हैं ही नहीं। यह सारी बात गलत है।

अध्यक्ष महोदय, जब नोटबन्दी की बात आई, तो ये विपक्ष वाले चाहे कुछ भी कहें, उत्तर प्रदेश के चुनाव या उत्तराखण्ड के चुनाव कहें, लेकिन जो असली बात है और जो यह डिमॉनेटाईजेशन हुई है, यह बहुत गलत हुई है। यह इनकी सोची-समझी साजिश थी। यह हमारे सामने रिकॉर्ड है, हमने टेलीविजन में देखा है और समाचार-पत्रों में भी पढ़ा है कि लोग लाईनों में लगे रहते थे और कइयों की तो इससे मृत्यु भी हुई है। लोगों के घरों में शादियां थीं जिसमें उन्हें बहुत परेशानी हुई। जो मेरा अपना विचार है, तो यह केन्द्र सरकार का कोई अच्छा कदम नहीं था। चुनाव की अलग बात है चाहे ये उत्तर प्रदेश या उत्तराखण्ड में जीते। लेकिन ये पंजाब में क्यों नहीं जीते? पंजाब में इनके बुरे हाल हुए। इसलिए नोटबन्दी कोई अच्छा कदम नहीं था।

ऀअध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां सदन में कहना चाहूंगा कि जहां तक केन्द्र सरकार की बात है, तो वर्ष 2014 में जब चुनाव हुए थे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और इनके दूसरे वक्ताओं ने 3-4 बातें तो ऐसी कही थीं जिसमें कहा गया था कि हमें एक बार सत्ता में लाओ, तो बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी और बेरोजगारी दूर की जाएगी। मेरे ख्याल से केन्द्र सरकार को बने हुए आज अढ़ाई वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है,

मेरे चुनाव क्षेत्र से आज तक केन्द्र सरकार की सेवा में एक भी व्यक्ति नहीं लगा। यदि और जगहों से लगा हो, तो अलग बात है। साथ ही चुनावों के समय यह भी कहा गया था कि 15-15 लाख रुपये सबके खातों में आ जाएंगे। वे भी इन्होंने सपने दिखाए। यह भी कहा गया था कि महंगाई खत्म होगी, लेकिन महंगाई तो दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। कहां खत्म हुई? इसके अतिरिक्त हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी सोलन में एक रैली में आए थे, तो उस समय कहा गया था कि हिमाचल के सेब को स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा और बागवानों के साथ ऐसा कहकर खिलवाड़ किया गया क्योंकि आज तक वह भी नहीं मिला। ऐसी-ऐसी नीति है।

15/03/2017/1735/RG/DC/2

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार की बात है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है वहीं मेरे चुनाव क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास पिछले चार सालों में हुआ है। लेकिन जब इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे माननीय धूमल साहब मुख्य मंत्री थे, मैं यह तजुर्बे की बात बता रहा हूं बल्कि मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी से संबंधित विधायक हूं! जहां तक रोहड़ू विधान सभा चुनाव क्षेत्र की बात है, तो वहां उन पांच वर्षों में एक भी पत्थर नहीं हिला। मैं यहां उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि रोहड़ू में बस स्टैण्ड बन रहा था, वर्ष 2007 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय उसका काम चला हुआ था। उसके पश्चात इनकी सरकार आई और वर्ष 2010 में उसका काम बंद कर दिया। अब हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी छठी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं, तो आज उस बस स्टैण्ड का काम जोरों पर चला हुआ है। मुझे पूर्ण आशा है कि एक-दो महीने में उसका काम पूर्ण हो जाएगा। --(व्यवधान)---अध्यक्ष महोदय, मैं भारद्वाज जी को कन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता। इस समय मैं सदन में बजट पर बोल रहा हूं। मैं भारद्वाज जी को याद दिलाना चाहूंगा कि ये भी रोहड़ू से बिलांग करते हैं और ये भी हमारे बागवान हैं। वर्ष 2010 की बात मैं यहां सदन में बताऊंगा कि जो हमारा मेन रोड है ठियोग-हाटकोटी-रोहड़ू। सेब सीजन में उसकी क्या दशा हुई, यह आप भी जानते हैं और आपसे भी छिपा नहीं है। 2-2 और 3-3 रातें यात्रियों के बसों, गाड़ियों और ट्रकें में बुरे हाल हुए। मैं दावे के साथ यह बात कहता हूं और हर जगह बताता हूं। लेकिन आज जो ठियोग-हाटकोटी-रोहड़ू सड़क बन रही है वह

राजा साहब के आशीर्वाद से और उनकी बदौलत यह बन रही है। अगर राजा साहब मुख्य मंत्री न बनते, तो वह सड़क हमारी कभी नहीं बनती।

श्री सुरेश भारद्वाज : वह तो हाई कोर्ट के डायरैक्शन पर बन रहा है।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं , मैं भारद्वाज जी को बताना चाहता हूं कि

एम.एस. द्वारा जारी

15/03/2017/1740/MS/AG/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी-------

25 दिसम्बर, 2012 को राजा साहब ने छठी बार मुख्य मंत्री की शपथ ली और उसके तुरन्त बाद राजा साहब ने शायद 30 दिसम्बर, 2012 को लोक निर्माण विभाग के सारे आला अधिकारियों की बैठक बुलाई जिसमें मुझे और रोहित ठाकुर जी को भी बुलाया गया था। फिर उसकी समीक्षा ली कि क्या बात है इसमें काम क्यों नहीं हो रहा है। कारण कुछ भी रहे हों, राजा साहब ने सीधे आदेश किए कि मुझे यह रोड चाहिए। आज राजा साहब के आशीर्वाद से वह रोड बन रहा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि रोहडू से शिमला अढ़ाई से तीन घण्टे के बीच में पहुंच जाते हैं और एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारे कर्मचारी रोहडू और शिमला हररोज आएंगे-जाएंगे। ऐसी स्थिति हो रही है।

अध्यक्ष जी, यहां पर इस बजट में महिलाओं के लिए भी एक प्रावधान रखा गया है जिसमें रेजिडेंशियल परपज के लिए लैण्ड परचेज करने पर स्टाम्प ड्युटि 6 प्रतिशत से 3 प्रतिशत घटाई गई है। यह भी एक सराहनीय कदम है। इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा पैंशन को भी बढ़ाया गया है और इसको 650/-रुपये से 700/-रुपये प्रतिमाह किया गया है। मंदबुद्धि बच्चों तथा व्यस्कों को बिना किसी आय सीमा के पैंशन देने की भी घोषणा की गई है। बजट में ऐसी-ऐसी कई बातें हैं जिनको मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मुझसे पूर्ववक्ताओं ने उन पर काफी डिटेल में चर्चा कर दी है। इसी तरह से 80 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के

व्यक्तियों की पैंशन को 1200/-रुपये से बढ़ाकर 1250/-रुपये प्रतिमाह किया गया है। Nautor to be sanctioned in all the scheduled areas of the State. स्वतंत्रता सेनानियों की पुत्रियों के विवाह के समय दी जाने वाली विवाह अनुदान राशि को 21000/-रुपये से बढ़ाकर 31000/-रुपये किया गया है। यह भी इस बजट में एक सराहनीय कदम है। दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में भी बढ़ौत्तरी की गई। हमारी सरकार ने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी को पहले 150/-रुपये से बढ़ाकर 200/-रुपये किया था और अब 210/-रुपये किया गया है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपये तहसील, उप- तहसील तथा राजस्व भवनों के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। यहां पर विपक्ष

15/03/2017/1740/MS/AG/2

की तरफ से बात आई थी कि राजा साहब अस्पताल खोल रहे हैं, स्कूल अपग्रेड कर रहे हैं, तहसीलें और उप तहसीलें खोल रहे हैं तथा तहसीलों के लिए इस बजट में तहसीलदार वगैरह का प्रोविजन नहीं रखा गया है। मेरी जानकारी के अनुसार उसकी इसमें मैंशन करने की जरूरत नहीं होती है। यह अलग प्रोसैस है। जो यहां पर 19000 पदों का जिक्र किया गया है उसमें कई ऐसे पद हैं जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अलग पद हैं उसको भी इस बजट में दर्शाने की जरूरत नहीं है। उसका प्रोसैस कुछ अलग है। एग्जैक्ट तो क्या है मुझे भी पता नहीं है लेकिन जो मैंने पता किया था उसके अनुसार उसकी इसमें जरूरत नहीं है। इसी तरह से,

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मोहन लाला ब्राक्टाः अध्यक्ष जी, जो यह बजट वर्ष 2017-18 का है यह माननीय मुख्य मंत्री महोदय का 20वां बजट है और यह बहुत बढ़िया बजट है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि यह राजा साहब का आखिरी बजट है, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहीं पर होंगे और आप विपक्ष में उसी जगह पर होंगे। राजा साहब सातवीं बार मुख्य मंत्री बनेंगे यह मैं दावे के साथ कहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बजट का पूरे जोरों से भरपूर समर्थन करता हूं।

15/03/2017/1740/MS/AG/3

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेश कुमारः अध्यक्ष जी, 10 मार्च, 2017 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो साढ़े चार घण्टे का समय लेकर बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, किसी भी सरकार का बजट आने वाले समय में वह सरकार क्या करने जा रही है, इस ओर इशारा करता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने न केवल इस वर्ष का बल्कि पिछले चार वर्षों का व्याख्यान भी इसमें किया है। जो बजट भाषण 40 मिनट में पूरा हो सकता था,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-

15.03.2017/1745/जेके/एजी/1

श्री सुरेश कुमार **.....जारी**----

उसको पढ़ने में साढ़े चार घंटे लगा दिए। अगर देखें तो एक कहावत भी है कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। ऐसा बजट इस सदन में प्रस्तुत किया। सत्ता पक्ष के जो माननीय विधायक हैं, ये यहां पर सरकार की उपलब्धियों का, इस बजट का बड़ा व्याख्यान कर रहे हैं लेकिन अगर इस बजट को देखें तो इसमें ऊंची दुकान फीका पकवान के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे सत्ता पक्ष के साथी मुझसे पूर्व जो वक्ता यहां पर बोल रहे थे, बहुत सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया। विशेष रूप से यहां पर नोट बन्दी के ऊपर भी चर्चा कर रहे थे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जो नोटबन्दी का असर आप लोगों ने देखा होगा। यू0पी0 में तो कांग्रेस के लिए वोट की नसबन्दी साबित हुई। इनकी स्थिति आज ऐसी हो गई कि एक इनोवा में बैठो और कहीं का भी चक्कर लगा

दो, 10 का आंकड़ा भी नहीं छूं सके। ऐसी स्थिति नोटबन्दी ने इनकी कर दी। इनोवा की सवारियां यहां तक सीमित हो गए। यही स्थिति उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में भी मात्र 11 सीटें इनको मिली। आप देख सकते हैं प्रदेश की जनता ने किस प्रकार से नोटबन्दी का समर्थन किया। आप लोगों को भी इसका समर्थन करना चाहिए नहीं तो कहीं यह आंकड़ा यहां पर भी लागू न हो जाए। इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहां पर अभी भाई रवि ठाकुर जी सर्जिकल स्ट्राईक की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि रक्षा बजट नहीं होना चाहिए। रवि जी, अगर रक्षा बजट नहीं होगा तो शायद हम भी यहां पर नहीं होंगे। ये तो उन फौजियों की बदौलत है जो हम आज आराम की नींद सो सकते हैं। नहीं तो जो स्थिति हमारे देश की हो रही थी और यह सर्जिकल स्ट्राईक इसकी वजह से ही है कि आज देश के हालात सुधर रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तानी कभी भी हमारे देश में आते थे और हमारे सैनिकों के सिर काट कर ले जाते थे। आज किसी पाकिस्तानी की हिमाकत नहीं है ।अब हमारे देश की ओर आँख उठा कर नहीं देख सकते । भाई कह रहे थे कि रक्षा बजट ही नहीं होना चाहिए।,ऐसी स्थिति हमारी है। किशोरी लाल जी यहां पर बैठे हैं। अभी ये बात कर रहे थे कि रोस्टर नहीं होना

15.03.2017/1745/जेके/एजी/2

चाहिए। ये कह रहे थे। जिस प्रकार से पीछे पी0टी0ए0 की भर्ती हुई, चाहे एस0एम0सी0 की भर्ती हुई और आज कल आऊट सोर्सिंग से भर्ती हो रही है। उसमें कहीं पर भी रोस्टर का प्रावधान नहीं है। किशोरी लाल जी आप तो अनुसूचित जाति के विधायक हैं। इस बात को सदन में रखना चाहिए और आप तो रोस्टर से ही आए हैं। आपको तो इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप ही रोस्टर का विरोध कर रहे हैं? आज जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, उसमें कहीं भी रोस्टर नहीं है। पी.टी.ए. में रोस्टर का प्रावधान नहीं था। उनको कॉंट्रैक्ट में लिया गया। अब वे रैगुलर भी हो जाएंगें लेकिन जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और चाहे एस.सी., एस.टी. या ओ.बी.सी. हैं, उनको इसमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया। उनके अधिकारों का हनन किया गया और आप कह रहे हैं कि रोस्टर की आवश्यकता नहीं

है। आऊटसोर्सिंग में भी यही स्थिति है। आज चोर दरवाजे से भर्तियां हो रही है। ऐसी स्थिति हमारे प्रदेश की है।

इसके अलावा यहां पर बहुत सारी बातें हुई। बेरोज़गारी भत्ते के बारे में कहना चाहूंगा। आपने अपने घोषणापत्र में इसकी बात की। पहले तो यह ही तय नहीं हो पाया कि इसकी घोषणा हुई भी थी या नहीं हुई क्योंकि बाली जी कह रहे हैं कि हमने घोषणा पत्र में इसकी घोषणा की। सुखविन्द्र सुक्खु जी भी कह रहे हैं और आनन्द शर्मा जी जिन्होंने घोषणा पत्र बनाया, शिमला पहुंचे और मुख्य मंत्री जी बार-बार इस बात को दोहराते रहे कि हमने बेरोज़गारी भत्ते की बात नहीं की। मुख्य मंत्री जी, अब क्या हुआ? जब आपने इसकी घोषणा नहीं की थी, आपने घोषणा पत्र में नहीं कहा था फिर आज यह कैसे लागू हो गया? आज भी जो बेरोज़गारी भत्ता था,

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

15.03.2017/1750/SS-AS/1

श्री सुरेश कुमार क्रमागतः

पहले तो चार साल आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, पहले तो बेरोजगारों के साथ अन्याय किया और आज उनके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। केवलमात्र +2 पास लोगों को एक हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। एक साथी कह रहे थे कि एक हजार रुपये में वह क्या अपने इंटरव्यू के फार्म भरने जायेगा? एक हजार रुपये में वह क्या करेगा? इसके अलावा क्या केवल +2 पास ही बेरोजगार हो सकता है? क्या दसवीं, आठवीं पास बेरोजगार नहीं है? जो अनपढ़ है क्या वह बेरोजगार नहीं है? प्लस टू वाला तो कहीं-न-कहीं नौकरी कर लेगा, फैक्टरी में भी चला जायेगा लेकिन अनपढ़ क्या करेगा? --(व्यवधान)-- अरे भाई, अनपढ़ को कौशल विकास भत्ता देंगे तो कौन-सा कौशल बढ़ायेगा? वे लोग क्या बेरोजगार नहीं हैं? ऐसी स्थिति आज आपने कर दी है। ये बेरोजगार

आपके कल के लिए मुसीबत हैं। यह जो यू0पी0 और उत्तराखंड में हुआ, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार आपके लिए करेंगे। ऐसी स्थिति आज आपने कर दी है।

इसके अलावा अभी यहां पर खुले में शौच मुक्त की बात हो रही थी। भाई बलदेव जी ने स्थिति बताई। मेरे यहां की यही स्थिति है और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी यही स्थिति है। जो हमारे दूर-दराज के क्षेत्र हैं उसमें यही स्थिति है। कहां बने हैं शौचालय? ऐसा आपने वाहवाही लूटने के लिए किया। केन्द्र वालों को तो जहां आप लेकर जायेंगे, वे वहीं जायेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति मेरे वहां की है। स्कूलों की भी यही हालत है। स्कूलों में पानी नहीं है, शौचालय नहीं हैं। अनेक ऐसे स्कूल्ज़ हैं जहां पेयजल नहीं है। मैं जब गवर्नर स्पीच पर बोल रहा था तो उस समय भी मैंने ज़िक्र किया था कि अनेकों स्कूल ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है तो शौचालय की क्या हालत होगी? जब पीने का पानी ही नहीं है तो बच्चे कैसे शौचालय में जायेंगे? ऐसी स्थिति है।

जहां तक स्वास्थ्य या शिक्षा की बात करें या सड़कों की बात करें तो हर जगह यह सरकार पिछले सवा चार साल में फेल रही है। मैं स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करना

15.03.2017/1750/SS-AS/2

चाहूंगा। आज मेरा प्रश्न भी लगा था। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी पहले यहां बैठे थे और अब चले गए हैं। प्रश्न संख्याः 3833 मैंने पूछा था। सिविल हॉस्पिटल राजगढ़ और सिविल हॉस्पिटल सराहां मेरे यहां हैं। राजगढ़ की मैं बात करना चाहूंगा कि हैरानी की बात है कि 8 पोस्टें डॉक्टरों की हैं और 8 में से 6 खाली हैं। खाली कब हुईं? एक 26 मार्च, 2016 को, एक 12 मई, 2016 को, एक 27 मई, 2016 को, एक 11 मई, 2016 को, एक 8 जुलाई, 2016 को और एक 19 अक्तूबर, 2016 को। ऐसी क्या मुसीबत आई कि छः डॉक्टरों को दस महीने के अंदर ट्रांसफर करना पड़ा? क्या आप जान-बूझकर ऐसा भेदभाव हमारे साथ कर रहे हैं कि जहां पर बी0जे0पी0 के विधायक हैं वहां के संस्थानों को खाली कर दिया जाए? जो राजगढ़ सी0एच0सी0 है वहां 14 में से 9 पोस्टें खाली हैं। अभी जो प्लानिंग की बैठक हुई थी उसमें मैंने माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष यह बात रखी। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपके

पास फार्मासिस्टस तो होंगे। लेकिन मेरे यहां राजगढ़ में फार्मासिस्टस भी नहीं हैं। तीन पोस्टें थीं और तीनों ही 2005 से खाली चल रही हैं। आज तक वे पोस्टें नहीं भरी गईं। यही स्थिति मेरे यहां सी0एच0सी0 सराहां की है। यहां चार पोस्टें हैं और चार में से एकमात्र डॉक्टर है। तीन पोस्टें खाली हैं। कब से खाली चल रही हैं, अगस्त, 2015 से। यहां डेट नहीं दी। राजगढ़ में तो आपने एक साल में उठा दी थी लेकिन यहां आपने डेट नहीं बताई। अगस्त, 2015 से खाली चल रही हैं। 11 में से केवलमात्र 5 पोस्टें भरी हैं, 6 पोस्टें खाली चल रही हैं। ऐसी स्थिति आज सिविल हॉस्पिटल की है। ऐसी स्थिति पी0एच0सीज़0 की है। 11 पी0एच0सीज़0 हैं, 11 में से मात्र 3 पी0एच0सीज़0 में डॉक्टर्ज़ हैं। 8 में डॉक्टर्ज़ नहीं हैं। आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा विकास और काम आपने कर दिये हैं। बजट में भी दिया है कि इतने डॉक्टरों के पद भर दिये। कहां गये वे डॉक्टर? क्या आप जान-बूझकर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? ऐसी स्थिति शिक्षा संस्थानों की है। आज आपने कई स्कूलों का दर्जा बढ़ा दिया, अच्छी बात है। मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरे यहां पहले बहुत सारे स्कूलों की कमी थी, आपने दर्जा बढ़ाया लेकिन उसमें स्टाफ नहीं है। ऐसी स्थिति है। आज ही मुझे पंचायत समिति के लोग मिलने आए थे और मुझे यहां पर रैजोल्यूशन दे कर गये। मैं बताना चाहूंगा कि सीनियर सकैंडरी स्कूल, जदोल-टपरोली में 8 पोस्टें खाली हैं। चार टीचिंग की और चार नॉन-टीचिंग की।

जारी श्रीमती ए0वी0

15.3.2017/1755/av/as/1

श्री सुरेश कुमार ---------- जारी

एक गवर्नमैंट मिडिल स्कूल पेन कुफर वहां पर चार में से तीन पोस्टें खाली है। जी0एम0एस0 ठंडीधार में भी चार पोस्टें खाली हैं। जी0एम0एस0 उलकतोगा में भी दो पोस्टें खाली हैं। प्राइमरी स्कूल तिरगनू है वहां जे0बी0टी0 नहीं है। यह तो उन स्कूलों की बात कर रहा हूं जो मुझे आज ही बताये गये हैं मगर मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में यही स्थिति है। यहां पर शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने बहुत ज्यादा

प्रोग्रैस कर ली है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो शिक्षा संस्थान अभी अपग्रेड हुए हैं उन सबकी यही स्थिति है। आज उनमें बच्चे नहीं है और बच्चे कैसे होंगे जब स्टाफ ही नहीं है। जो स्कूल चल रहे थे उन में से भी स्टाफ को दूसरी जगह डेपुटेशन पर भेज दिया गया है। सराहां कालेज जो कि हमारी पार्टी की सरकार ने खोला था। इस सरकार ने आते ही वर्ष 2013 में उसको बंद कर दिया। बंद करते समय कारण दिया गया कि यहां पर इनफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग नहीं है तथा केवल तीन कमरों में कालेज चल रहा है। वर्तमान मुख्य मंत्री जी आए और वहां पर कालेज की फिर से घोषणा कर दी। इस सरकार को बने चार-साढ़े चार साल बीत गये मगर वह कालेज आज भी उन तीन कमरों में ही चल रहा है। उस समय बच्चे कम थे मगर आज तो वहां पर 250 बच्चे हैं तथा बच्चे उन तीन कमरों में ही भेड़-बकरियों की तरह बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपने कहा कि हमने बहुत सारी सब-तहसीलें खोल दीं। कई सब डिविजन खोली गई और मेरे यहां भी खोली। हमारी सरकार ने दो सब-तहसीलें खोली थी और इस सरकार ने आते ही अपना फट्टा लगाने के लिए उनको पहले बंद किया तथा उसके बाद दोबारा खोल दिया। आज वह सब-तहसीलें एक-एक कमरे में चल रही है। एक सब-तहसील का माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले दिनों शिलान्यास किया था लेकिन उसकी बिल्डिंग का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। मुख्य मंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र में आए थे और उस समय बहुत सारी घोषणाएं की गई। लेकिन उनकी घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई। अभी कर्नल साहब कह रहे थे कि यहां पर हारे और नकारे लोगों की फौज खड़ी की हुई है और बहुत सारे चेयरमैन /वाईस

15.3.2017/1755/av/as/3

चेयरमैन बना दिए। उनका काम केवलमात्र इतना है कि क्षेत्र में जाओ और जिन स्कीमों के उद्घाटन या शिलान्यास हो गये हैं उनका दोबारा से उद्घाटन/ शिलान्यास करो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इतनी घोषणाएं हुई हैं कि अगर उन पर पूरे हिमाचल प्रदेश का बजट भी लगा दें तो भी शायद वे योजनाएं पूरी नहीं होगी। यहां पर किशोरी लाल जी कह रहे थे

कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे कामों की डी0पी0आर0 बन गई हैं, पैसा आ गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की केवल एक सड़क की डी0पी0आर0 बनी थी मगर बाद में वह डी0पी0आर0 ही गुम हो गई। उसको गुम करवा दिया गया मगर बाद में जैसे-कैसे प्रयास करके उसको निकाला। उस सड़क के लिए पैसा स्वीकृत हुआ और एक दिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र से नोमिनेटिड उपाध्यक्ष वहां भूमि पूजन करने पहुंच गये। आजकल शिलान्यास की जगह भूमि पूजन चला हुआ है। मैंने जब उसके बारे में विभाग से पूछा तो बताया गया कि उसका शिलान्यास नहीं हुआ यह तो भूमि पूजन हुआ है। फिर मैंने पूछा कि किसने करवाया तो बताया गया कि ठेकेदार ने करवाया है। जहां तक ठेकेदार वाली बात है तो उस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्लानिंग की बैठक में कहा था। मैंने जब उनके समक्ष सड़कों की बात रखी थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिला सिरमौर के बारे में कहा कि वहां तो ठेकेदार ही राज कर रहे हैं। हमारे यहां डी0पी0आर0 नहीं बन रही है। हो सकता है कि हमारे साथ जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे यहां डी0पी0आर0 क्यों नहीं बन रही है? किशोरी लाल जी और ब्राक्टा जी यहां पर कह रहे थे कि इनके निर्वाचन क्षेत्र में पता नहीं कितनी सड़कों की डी0पी0आर0 बन चुकी है। इसका मतलब हमारे साथ जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप कितना समय लेंगे?

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, 5-10 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष : अब इस सभा का समय 6-15 बजे अपराह्न तक बढ़ाया जाता है।

श्री सुरेश कुमार **श्री वर्मा द्वारा जारी**

15/03/2017/1800/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री सुरेश कुमार : मैं पीने के पानी की स्थिति की बात करना चाहूंगा। वैसे माननीय मंत्री जी यहां सदन में नहीं हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसी भी पंचायत में जाएं, वहां पर यदि कोई

समस्या हैं तो पीने के पानी की समस्या है। मैंने 100 हैंडपम्पों को विधायक प्राथमिकता में डाला था, उसकी डी0पी0आरज0 भी बनी, लेकिन हर बार उस डी0पी0आर0 को कुछ-न-कुछ ऑब्जेक्शन लगाकर वापिस कर दिया जाता है, क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर कहीं 100 हैंडपम्प इस क्षेत्र में लग जाएंगे, तो शायद विधायक को उसका श्रेय न चला जाये। इसलिए जानबूझकर उस डी0पी0आर0 को अप्रूव नहीं किया जा रहा है। पिछले वर्ष गन्दे पानी के कारण पीलिया का प्रकोप हिमाचल प्रदेश में फैला था। मेरे यहां की स्थिति भी यही है। वहां पर ज्यादातर ग्रेवटी की योजनाएं हैं और उनमें कहीं पर भी फिल्टर नहीं हैं। पिछले वर्ष मैंने प्रश्न भी किया था। ज्यादातर स्कीमों में फिल्टर/फिल्टर बैड नहीं बने हैं और लोगों को सीधा गन्दा पानी पिलाया जा रहा है। आने वाले समय में भी यही स्थिति होने वाली है, क्योंकि गर्मियां आने वाली है। पिछले वर्ष भी मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी से मिला था, जैसे ही मैंने कहा कि पच्छाद में पानी की समस्या है, तो मंत्री जी ने कहा कि वहां के विधायक अभी मेरे पास आये थे। मैने कहा कि विधायक तो मैं हूं। लेकिन उसके बाद उन्होंने एस0सी0 आई0पी0एच0 को फोन किया था। सड़कों की जहां तक बात है, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। हमारी सरकार ने नेशनल हाईवे घोषित किए और 5 नेशनल हाईवे मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ते हैं, लेकिन उनकी डी0पी0आरज नहीं बन रही है। सरकार कहती है कि बजट नहीं आया और अभी हमें प्रिंसिपल मंजूरी मिली है, लेकिन पैसा तो तब मिलेगा जब आप एस्टीमेट देंगे। लेकिन इस सरकार की मंशा ही नहीं है। ये नहीं चाहती कि ये नेशनल हाईवे बने। कहीं ऐसा न हो कि वहां से हमारा सुपड़ा ही साफ हो जाये। ऐसी स्थिति इस सरकार की है। मेरे भाई बिक्रम सिंह जरयाल जी यहां पर बिजली की बात कर रहे थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी आज बिजली की यह स्थिति है कि बिजली के तार हरे पेड़ों में लटक रहे हैं। मेरे राजगढ़ क्षेत्र का जो ऊपर का एरिया है, मैं पिछले दिनों वहां पर गया था, जदोल टपोली एक पंचायत है उसका जो अप्पर एरिया है उसमें जो टालीभूजल, मांठल,भघोग पंचायतें हैं, उनमें अनेक ऐसी जगहें हैं जिसमें बिजली के तार अभी भी हरे पेड़ों में लटके हुए हैं। पिछले दिनों भारी बर्फबारी हुई और डेढ़-

15/03/2017/1800/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

डेढ़ महीनों तक लोगों को बिजली नहीं मिली, क्योंकि तारों के टुकड़े-टुकड़े हो गये थे। मेरे क्षेत्र में लो वॉल्टेज की समस्या भी है। वहां के नेता कहते हैं कि आदर्श विधान सभा क्षेत्र बन

गया है, लेकिन आज भी आप जाकर देखें कि हमारे क्षेत्र की क्या स्थिति है? सड़कों की बात मैं कर रहा था। डा0 वाई0एस0 परमार जो हमारे प्रदेश के निर्माता है, उनका जन्म मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुआ, लेकिन उस क्षेत्र में जाकर आप देखें। यहां पर विकास के बहुत बड़े-बड़े दावे होते हैं। आज भी उनके घर तक पक्की सड़क नहीं हैं। जिस स्कूल में वे पढ़े हैं, उस स्कूल में आज अध्यापक नहीं हैं। वहां पर जो कच्ची सड़क है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी और माननीय धूमल जी ने बनाया है। वहां का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसां हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने +2 किया है। कॉलेजों की हालत क्या है, इसका अंदाज आप खुद ही लगा सकते हैं। वैसे कॉलेजों को डिक्लेयर तो कभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि घोषणा करने में क्या जाता है। वहां बागथल रेस्ट हाऊस में जाकर यदि आप देखें, यदि उसके वी0आईपी0 रूम में कोई व्यक्ति सो गया तो अगले दिन बेहोश मिलेगा। ऐसा विकास मेरे विधान सभा क्षेत्र का है। इस बजट में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे दावे किये गये,

श्रीमती एन0एस0 ... द्वारा जारी।

15/03/2017/1805/ एन0एस0/डी0एस0 /1

श्री सुरेश कुमार -----जारी

लेकिन यह तो मात्र केवल घोषणाओं को पिटारा है जोकि आने वाले विधान सभा चुनाव को देख कर ऐसी घोषणायें यहां पर की गई हैं। यहां पर बहुत सारी समस्याओं का जिक्र हुआ है। बन्दरों की समस्या के बारे में भी यहां पर जिक्र हुआ है। 1.13 लाख बन्दरों की नसबन्दी की गई है लेकिन आप हमारे क्षेत्र में आ करके देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कैसी स्थिति है? लैंटाना ग्रास और केसू की बात इस मान्य सदन में की गई है और कहा गया है कि हमने इसका बहुत उन्मूलन कर दिया है। मैं अभी दो-तीन दिन पहले अपने विधान सभा क्षेत्र में गया था, तब मैंने देखा कि इसको ऊपर से काट करके जगह-जगर पर ढेर लगाये जा रहे हैं और करोड़ो रूपये इस पर खर्च किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति इस सरकार की है।

Speaker : Wind up please.

श्री सुरेश कुमारः वन माफिया आज पूरी तरह से मेरे क्षेत्र में हावी है। जो अधिकारी इन वन काटूओं को पकड़ते हैं, उनको ट्रांसफर का रोब दिखाया जाता है। ऐसी स्थिति आज मेरे क्षेत्र की है। मेरा मानना है कि जानबूझ कर हमारे क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जानबूझ कर हमारे कार्यों की डी0पी0आर0 नहीं बनाई जा रही है। जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, सब चोर दरवाजे से हो रही हैं। हर तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई रोस्टर नहीं लगाया जा रहा है। मेरा क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ता जा रहा है। आज स्थिति यह है कि बजट में जो घोषणायें की गई हैं वे केवल मात्र घोषणायें ही हैं। आने वाला समय बहुत नजदीक है और अब तो सरकार के महीने ही नहीं बल्कि कुछ दिन ही बचे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह बजट सरकार का केवल मात्र अंतिम बजट है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसका समर्थन करूं। मैं इसका विरोध करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

15/03/2017/1805/ एन0एस0/डी0एस0 /2

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 16.03.2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 15.03.2017 **सचिव।**